Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 09-03-2005

Participants : Jatiya Dr. Satyanarayan,Mahtab Shri Bhartruhari,Kumar Shri Shailendra,Shaheen Shri Abdul Rashid,Chakraborty Shri Ajay,Senthil Dr. R,Sharma Shri Madan Lal,Sonowal Shri Sarbananda,Fernandes Shri George,Pathak Shri Brajesh,Chinta Mohan Dr. ,Prabhu Shri Suresh,Vijayan Shri A.K.S.,Meinya Dr. Thokchom,Naik Shri Dharavath Ravinder,Barman Shri Hiten,Tripathi Shri Chandramani,Yadav Prof. Ram Gopal,Rawat Shri Bachi Singh,Yerrannaidu Shri Kinjarapu,Kharventhan Shri Salarapatty Kuppusamy,Bellarmin Shri A.V.,Gandhi Shri Pradeep,Shivanna Shri M,Aaron Rashid Shri J.M.,Virendra Kumar Shri ,Wangyuh Shri W.,Satpathy Shri Tathagata,Mistry Shri Madhusudan Devram,Acharia Shri Basudeb,Mehta Shri Alok Kumar,Dhindsa Shri Sukhdev Singh,Shah Lt. Col.(Retd.) Maharaja Manabendra,Rawat Prof. Rasa Singh,Owaisi Shri Asaduddin,Deo Shri Bikram Keshari,Singh Ch. Lal,Krishnadas Shri N.N.,Mishra Dr. Rajesh Kumar,Yadav Shri Parasnath,Ravichandran Shri A.,Singh Shri Ganesh,Rathod Shri Harisingh Nasaru

Title: Further discussion on the Motion of Thanks on the President's Address moved by Shri Pawan Kumar Bansal and seconded by Shri Ajay Makan on the 2nd March, 2005. (Discussion not concluded)

12.11 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S

ADDRESS – contd.

MR. SPEAKER: Hon. Members, let us now come to item No. 26, namely, further consideration of the Motion of Thanks on the President's Address moved by Shri Pawan Kumar Bansal and seconded by Shri Ajay Maken.

Hon. Members whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated, may, if they desire to move their amendments, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the amendments they would like to move. Those amendments only will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 25, 2005'. "

Now, Shri George Fernandes may speak.

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : धन्यवाद अध्यक्ष जी।

राट्रपति के अभिभाण को मैंने जो सुना और पढ़ा उससे मुझे लगा कि उसमें ऐसी अनेकों बातें हैं जिनके साथ हम अपने को जोड़ सकते हैं, लेकिन अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें मान लेना सम्भव नहीं है। अभिभाण के शुरू में ही राट्रपति जी ने कहा है कि

> "In the span of three quarters of a year that the United Progressive Alliance Government has been in office, considerable time and energy has already been devoted to the implementation of the National Common Minimum Programme."

यह एक-तिहाई सत्य है। इसलिए कि इन्हीं की सरकार के साथ जुड़े हुए लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि श्री प्रकाश करात, सी.पी.आई.(एम), सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि

> "Nine months have passed but there is no proof that it is taking steps to fulfil the commitments made in the CLP."

यह गलत बात राट्रपति जी के मुंह से क्यों कहलवाने की जरूरत पड़ी यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, राट्रपति जी, एक और बात को कहते हैं कि बिलकुल सब लोग खुशहाल हैं, सब चीजें ठीक चल रही हैं, यह बताया जा रहा है। इसे भी सत्य मान लेना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा साधन नहीं दिख रहा है। वे कहते हैं कि 'the Congress like a leopard that won't change spots'.

जिस पार्टी की मदद से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार चला रही है, उस पार्टी का व्यक्ति कह रहा है कि यह ऐसा जानवर है, जो कभी बदलेगा नहीं। करात साहब का यह कहने के लिए कुछ कारण होगा, क्योंकि वह मात्र सरकार का समर्थन करने वाले नहीं, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन देने वालों में है, लेकिन इससे बढ़ कर जिस बात को मुझे आपके और सदन के सामने रखना है, इसमें कितनी बातें सही नहीं हैं, वे इसमें हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन महामंत्री के मुंह से आई हुई बात है। वे बोलते हैं -

> "The Congress will publish booklets after November 17th on the use of *panchayati raj* funds, industry, agriculture, law and order and the deaths of 11,000 political workers. "

He further says:

> "The ruling Marxists have been using the *panchayati raj* funds for party work, building party offices in the State. The Congress wanted to give them sleepless nights in the coming days."

इस पृठभूमि में यह मान कर चलना कि ये सब चीजें सब लोग बहुत ही सुख और आराम से तथा प्यार से, एक-दूसरे के साथ रिश्ते बना कर एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में लगे हुए हैं। मैंने कहा कि यह एक-तिहाई सत्य है, लेकिन असल में यह पूर्ण सत्य है।

अध्यक्ष महोदय, जब शुरुआत ऐसी हो रही है तो फिर आगे किन बातों पर विश्वास किया जाए, यह मेरे सामने एक प्रश्न के तौर पर है। जिस घोाणा-पत्र को प्र ाकाशित किया, उसमें रोजगार निर्माण करने के लिए काफी महत्व दिया है। मेनिफेस्टो में कही हुई बात एक रही और बजट में आई हुई बात कुछ और ही हो गई तथा राट्रपति के अभिभााण में वह तीसरी बात हो गई। हम लोग किस पर विश्वास करें? आपने मेनिफेस्टो में कहा -

> "The UPA Government will immediately enact a National Employment Guarantee Act. "

आपके इमिडिएट में कितने सैकिंड्स होते हैं और वह कानून कहां है? अगर वह छपा रखा है तो क्यों वह वैसे ही रखा है?

> "This will provide a legal guarantee for at least 100 days of employment to begin with on asset-creating public works programmes every year at minimum wages for at least one able-bodied person in every rural and middle class family."

यह मेनीफेस्टो है। बजट में कहा जाता है:

I now refer to the National Rural Employment Guarantee Scheme mentioned in this year's Budget. I quote:

> "After the National Food for Work programme was launched in November 2004, provision was made for the cash component and the foodgrain component. In overall terms, the expenditure in the current year is estimated at Rs.4,020 crore. For 2005-06, a provision of Rs.5,400 crore for the cash component and 50 lakh MT of foodgrains have been made and, in overall terms, the allocation will increase to Rs.11,000 crore. It is Government's intention to convert this programme into the National Rural Employment Guarantee Scheme. When fully rolled out, the Scheme will provide livelihood security for crores of poor families, and I promise to find the money for the programme. "

I repeat the sentence " I promise to find the money for the programme."

यानी अभी कुछ पैसा एलाट नहीं हुआ है। बात वहीं समाप्त नहीं हो जाती है, राट्रपति के अभिभााण में कुछ और ही बात आ जाती है। वे कहते हैं:

> "To take care of those who are likely to be left behind by development processes and to ensure that there is a safety net, especially in some of the more backward regions of the country, my Government has come forward with a National Employment Guarantee Bill. This Bill before Parliament will provide legal guarantee for at least 100 days of employment to at least one person in every poor household initially in some of the most backward districts of the country."

अध्यक्ष जी, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सरकार की रोजगार के इतने महत्व के प्रश्न पर एक सोच क्यों नहीं हो सकती है? अन्त में इसे लोग भूल जायें या किसी और रास्ते पर वे चले जायें, यह इनके दिमाग में बात हो या और कोई भी बात हो तो हम चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री अपना भााण दें तो वे इसकी सफाई करें। उसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात है और वह है, भारत महान की। भारत महान की कल्पना राट्रपति ने अपने अभिभााण में देश के सामने रखी है। उसे रखते हुए उन्होंने अपने भााण में यह कहा ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: No whisperings please!

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, उन्होंने अपने भााण के अंत में एक बात कही और उसमें यह कल्पना रखी कि "Rural India should be seen as a growth engine and public investment is required in the area of rural infrastructure to unleash its growth potential. My Government proposes to undertake a major plan for rebuilding rural India called 'Bharat Nirman'. This will be a time-bound business plan for building rural infrastructure…" आदि-आदि कहकर वे अंत में यह बात कहते हैं "The details of this programme will be outlined by the Union Finance Minister in his Budget Speech." And what does the Union Finance Minister, in his Budget Speech, has to assure and fulfil the point made by the President? It is a very long statement that he has made which I do not want to read here. All that he has conveyed is: "'Bharat Nirman' will require huge resources. Government believes that 'Bharat Nirman' is an achievable project and it is our intention to give rural India a new deal fully involving Panchayati Raj Institutions in the planning and implementation."

राट्रपति जी की कही हुई बात, उनका जो सपना भारत के लिए रहा, उसको ऐसी जगह लाकर पहुँचा दिया कि जिस पर अमल होगा या नहीं होगा, इस पर विश वास नहीं किया जा सकता है।

राट्रपति जी के माध्यम से यह कहा गया कि हमारा लोकतन्त्र कितनी मजबूती से चल रहा है और इसे हिंसा के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। बुलट से नहीं बैलट से काम होना चाहिए। अभी जो बैलट हुए, उसका अनुभव सामने है। यह स्पट हो चुका है कि यह सरकार लोकतन्त्र से कितनी बंधी हुई है। गोवा से शुरूआत हो चुकी है और वह झारखण्ड पहुँच गया है और खोज रहे हैं कि और कहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के पुराने और नये नेता लोग इन बातों को चलाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम तो बार-बार आ जाता है। इसलिए श्री करात जी ने जो कुछ भी कहा कि ये अपनी शक्ल को कभी बदलेंगे नहीं और यही आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है और जो बातें राट्रपति जी की जुबान पर लायी जाती है, उनकी कोई कीमत इस सरकार के सामने नहीं है। यह बात यहाँ कहना जरूरी है।

अध्यक्ष जी, कम्यूनल हॉरमनी पर राट्रपति जी के मुँह से बातें कहलवायी गई हैं। …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: The total time of his Party is over.

… (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): He is speaking on behalf of the NDA… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please, you make your submissions. Why I put the bell was that his time was ten minutes for the entire debate. Nobody has considered time to him, therefore, I have rung the bell after 14 minutes.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : He may be given time from our Party.

MR. SPEAKER: You should say that. How much time? Your Party's time is also limited.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : He may be given time from our Party till he finishes his submission.

MR. SPEAKER: Very well, it will be deducted from your Party.

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): It should strictly apply to others also.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Then, in that case it will apply to other Parties also… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please do not impute any motives to me, Shri Ananth Kumar.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, I am not imputing any motives… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You should mention that. I have said that you know very well that so much hours we are not having with us. So many hours we could have devoted to this discussion are not longer available.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Any time we have to restrict, we have to restrict the number of speakers. We have allotted three-four days.

Therefore, instead of that, we have to do that. I am prepared to allow the House to run till 12 o' clock in the midnight. I do not mind. But his Party's time for the entire debate was 10 minutes. I have given the bell after 14 minutes. You are saying

this assuming that I shall be unfair. This is not proper. You have said that whatever time he takes should be deducted from your Party. Very well, let him carry on. Please do not impute.

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, you can take it now. There is time available. I do not mind now.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please do not interrupt each other. This is an important debate. We have lost a lot of time. Let us utilize this time.

Yes, Mr. George Fernandes, please go on.

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : कम्युनल हारमनी की बात राट्रपति के मुंह से लाई गई । कम्युनल हारमनी का अनुभव हम लोग आज से नहीं, दशकों से करते आए हैं । इसका अनुभव इस सदन में अनेक लोगों ने किया है । सैक्युलर कम्युनल हम लोगों ने बना कर रखा है । अगर कल भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ कर किसी दूसरी पार्टी में गया, तो वह सैक्युलर हो जाएगा और अगर किसी दूसरी पार्टी का आदमी या हमारी पार्टी का आदमी बीजेपी से चला जाता है, तो वह कम्युनल हो जाता है । उन्हें कम्युनल और सैक्युलर का अर्थ मालूम नहीं है, तो उनसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । अभी जो पिछली लोकसभा के चुनाव के समय हमारी पार्टी का, एनडीए का एक कार्यक्रम होना था । उसके मैनिफैस्टों में अनेक बातों में से एक बात यह थी कि "The NDA Government shall continue to strengthen the ideal of secularism enshrined in India's Constitution. The NDA believes that an early and an amicable resolution of the Ayodhya issue will strengthen national integration. We continue to hold that the judiciary's verdict in this matter should be accepted by all. At the same time, efforts should be intensified for dialogue and a negotiated settlement in an atmosphere of mutual trust and goodwill. " और जब यह बात सामने लाई गई तो कहा गया कि देखिए ये लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या-क्या बनाने जा रहे हैं और जितना हम लोगों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, इसको पढ़ कर सुनो, किसी के मुंह से सुनो तो उन्होंने मानने से इंकार किया और हम कम्युनल बन गए । जो अयोध्या का मामला…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not disturb him.

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अब आप सोशल हार्मनी, वेल्फेयर ऑफ माइनॉरिटी के बारे में राट्रपति से जो कहलवा रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि the UPA is committed to the implementation of the Protection of Places of Worship Act, 1992. … (*Interruptions*) It also says that on the Ayodhya issue, it would await the verdict of the Courts while encouraging negotiations between parties to the dispute for an amicable settlement which, in turn, must receive legal sanction. … (*Interruptions*) हमने भी वही कहा था।…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हमने आपकी सीडी देखी है।…(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आपकी सीडी भी हमने देखी है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है।

…(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ :हमारी बातों को जब लिखते हैं तो वे सैकुलर हो जाते हैं और जब हम उसे लिखते हैं और अमल में लाते हैं तो कम्युनल होते हैं। इन लोगों का कम्युनल और सैकुलर यही है।…(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : क्या जस्टिस बैनर्जी की हिन्दी रिपोर्ट इनको नहीं दी?…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members from all parties would get a chance to speak. So, why are you interrupting him? You can make your submissions when you speak.

… (*Interruptions*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि जब इस सरकार के अनेक सदस्य इस बात पर सार्वजनिक चर्चा लाए कि डिफैंस के लिए बजट ज्यादा हो रहा है, उसे कम करना चाहिए। जिनको जानकारी नहीं होती वे ही इस प्रकार की बातें कह सकते हैं, जानकारी इस मायने में कि सेना किन हालात में रहती है, किन हालात में काम करती है और उनकी जो जरूरतें हैं, उनको लेने और लाने के लिए कितनी तकलीफ होती है, किन-किन रास्तों से उनको जाना पड़ता है, जिनको यह मालूम नहीं है, वे ही इस बात को कह सकते हैं। इस सरकार ने अपनी शक्ल को ही दिखाने का काम किया। ये पहले जो चला रहे थे, आज भी उसे वहीं पर ले आए। हम चाहेंगे कि जहां सेना और सेना की आवश्यकताओं का सवाल आता है, उनके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो।…(व्यवधान)

मैं आखिरी बात महिलाओं के आरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं। एक लम्बे अरसे से इसे एक मजाक का विाय बनाया गया। अनेक बहाने बनाकर कहा जाता है कि यह क्यों नहीं हो सकता, यह भी बताया जाता है। यह मानकर चलना कि संसद में केवल पुरुा ही सब काम बढ़िया ढंग से काम करने वाले हैं और महिलाओं के बस का नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए। मेरा आग्रह है कि इस सत्र में इस मामले को लाकर, इसे पारित किया जाए। कल समूची दुनिया ने महिला दिवस मनाया, इस बात को ख्याल में रखकर संसद में इस कार्य को करना चाहिए।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. George Fernandes, you address the Chair. Please ignore them. You have already taken half-an-hour.

... (Interruptions)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : यहां दो बातें की गई हैं । एक उनको कफन घोटाले पर चर्चा चाहिए । *

यह उनका घोटाला है।...(व्यवधान)

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: No notice has been given on this. I would look into it.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: You have not given any notice. I would look into it.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You have not given any notice. It cannot go on record. The name cannot go on record.

... (*Interruptions*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : यह सत्य है। इसे हमने नहीं छेड़ा, आपने छेड़ा है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have already given a ruling. There is no notice given under the rule. Therefore, the name will not go in the record.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri George Fernandes, you have already taken half-an-hour. How long will you take? Please conclude.

... (*Interruptions*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : सत्य उनको मालूम हो जायेगा। ...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : आपको सच सुनना चाहिए। ...(व्यवधान) पहले आप डिफर करते हैं और बाद में सुनना भी नहीं चाहते। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: One of your leaders is speaking. Please take your seats.

... (*Interruptions*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : यह प्रधान मंत्री जी को लिखा हुआ पत्र है। ...(व्यवधान) आप इसकी जांच कराइये। ...(व्यवधान) इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? ...(व्यवधान) किसको बचाने का काम हो रहा है ? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है ?

*(Interruptions)**

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: Nothing will go on record. Please take your seats. What is this going on?

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

MR. SPEAKER: May I appeal to all of you? Please take your seats. Why are you getting agitated? Let him conclude. श्री राम कृपाल जी, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Shri Fatmi, please sit down. Please take your seats. What is happening inside the House? Please take your seats.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिये।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is not right.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please take your seats. I would not allow this. I am regulating the House. Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Shri George Fernandes is one of the senior most Members. He can look after himself. Let him speak. I have allowed him to speak. When you get a chance, you can reply. What are you doing?

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: What is this going on? This is very unfair.

… (*Interruptions*)

*Not Recorded.

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कैसे चलेगा ?

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri George Fernandes.

(Interruptions) *

MR. SPEAKER: Please sit down. I request all the hon. Members to sit down. लालू जी, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिये। यह क्या हो रहा है ?

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing is being recorded.

*(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए न।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Let the whole country see what is happening here.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Let the whole country see what is happening inside the Lok Sabha. We have started functioning today. I will request Shri George Fernandes to please conclude his speech.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए ।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : You are not the Chair. You are not the authority.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I will do that. Please sit down. I must have the freedom.

... (*Interruptions*)

*Not Recorded.

MR. SPEAKER : Thank you very much. Please sit down.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Everybody must sit down. When I am on my legs, everybody must sit down.

... (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : ये अपने शब्द वापस लें।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Please sit down. I will not allow this.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Shri George Fernandes, please sit down.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : When I am on my legs, you must sit down.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Mr. Harin Pathak, I am noticing everything as to who is instigating what. I am noticing it.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I am saying it is on all sides.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I will warn you. I will have to name somebody in this House.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Please sit down.

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, पहले ये माफी मांगेंगे।…(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Shri George Fernandes, you have taken more than half-an-hour.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। आप लोग बैठिए। यह नाटक नहीं है। हाउस में नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। फर्नांडीज जी, आप अपनी बात समाप्त करिए।

…(व्यवधान)

MR. SPEAKER : I am requesting every Party, every side. When you speak, you deal with whatever points that are taken up. I have been requesting you. Mr. George Fernandes can very well look after himself. Why everybody is standing? Why all this?

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I have already said to them. Mr. Malhotra, do not be unfair to me. I have been asking them. I am warning them in your presence. Even then you are accusing.

… (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, every Minister is speaking. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Nothing has been recorded.

(Interruptions) *

MR. SPEAKER : I am appealing to every section. This is the Parliament of India. After so many days, we are sitting today. I will express my great satisfaction and thank you for your cooperation.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Is this the way the House will function? I am requesting Shri Fernandes. Please do not take names for which you have not given notice. Please do not do it. The rules are extremely clear. You know very well. You cannot just name somebody without proper notice. Please conclude your speech. You said about your last sentence.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Please allow him. When you will speak, you can reply to him.

… (*Interruptions*)

*Not Recorded.

MR. SPEAKER : Let there be no cross-talks.

… (*Interruptions*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा था। मैंने असल में कहा कि मैं बात समाप्त करना चाहता हूं लेकिन जो बातें यहां पर कही गईं,…(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Nothing has been recorded. Do not worry.

… (*Interruptions*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : रिकार्डिंग की बात नहीं है। इस बात का कभी न कभी खुलासा होना चाहिए। जैसे ही नई सरकार बनी, मैंने उस सरकार के प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा और प्रधान मंत्री जी को पत्र में कहा कि एक अर्से से आपकी पार्टी की अध्यक्षा इस प्रकार का प्रचार चलाती आईं हैं जो असत्य है और उनको मालूम है कि वह असत्य है।…(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Do not record it. This is not a parliamentary word. Bring it to my notice.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I have said it.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : When you do not need a Speaker, you do not need anybody in the Chair. I am myself interjecting.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Do you not want a Speaker then? Then you decide it by fisticuffs.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : You are now allowing the House to function.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है ?

…(व्यवधान)

श्री लाल कृण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, पिछली लोकसभा में हम जानते हैं कि श्री जॉर्ज फर्नान्डीज रक्षा मंत्री थे। उनके साथ जिस प्रकार से सारे ि वपक्ष की ओर से जैसा आचरण किया गया और सारा काम इसी आरोप के आधार पर किया गया और जब इस आरोप के बारे में इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखकर यह बताने की कोशिश की कि यह आरोप सरासर असत्य है तो उनको यह कहने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है और उनको अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। There is nothing objectionable in what he is saying. He has been maligned for so many years continuously and he was not allowed even to answer questions on this ground. If he is clarifying his position on the basis of a letter he has written to the Prime Minister, why should he be prevented? … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Advani, you know very well that the word is not parliamentary.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He has said that the Prime Minister will reply.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You can use any other word signifying the same meaning. You know that very well.

… (*Interruptions*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, यद्यपि मेरा पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा गया था लेकिन मैं वह पत्र सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार हूँ।…(व्यवधान) केवल वही पत्र नहीं बल्कि जो तहलका-तहलका कह कर ये लोग नाच रहे हैं, उसके पीछे कौन है, किसके घर पर बैठकर यह सब तैयार किया गया, किन लोगों की मदद से यह सारा काम हुआ, उससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, मैं उनको सदन के सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार हूँ ताकि सत्य देश और दुनिया के सामने आ सके। …(व्यवधान) मैं इन दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आपको सुझाव देने की जरूरत नहीं हैं।

TEXT OF AMENDMENTS*

The following MPs moved the amendments to Motion of Thanks on the President's Address:

SHRI ABDUL RASHID SHAHEEN (BARAMULLA)

DR. LAXMINARAYAN PANDEY (MANDSAUR)

SHRI BACHI SINGH RAWAT 'BACHDA'(ALMORA)

SHRI ARJUN SETHI (BHADRAK)

SHRI GANESH SIGH (SATNA)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI)

SHRI JUAL ORAM (SUNDERGARH)

SHRI PRADEEP GANDHI (RAJNANDGAON)

* For full text of the Amendments, please refer to Original Verision of Debate dated 09.03.2005

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, आपने राट्रपति महोदय के अभिभााण पर बोलने का मुझे जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दो बातों के साथ अपना भााण शुरू करूंगा।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, हमारी तरफ से माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया वह एक अलग बात है …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You can only raise a point of order, but not now. Nothing will be recorded. Nothing is being recorded.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Okay. All right.

… (*Interruptions*)

श्री लू प्रसाद : इन्होंने एक टीवी के इन्टरव्यू में कहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी का भी वही हाल होगा जो श्रीमती इन्दिरा गांधी का हुआ था।…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let him speak. I have called Shri Madhusudan Mistry. Sit down. Nothing is being recorded.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: I have called Shri Madhusudan Mistry. Please sit down.

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, I am on a point of information. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No, there is no point of information.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: This is not the way to raise a matter. It is not that any time you can do anything you like. Sit down. Send a slip. Try to behave in a responsible manner. आप चुनकर आए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारत सम्राट बन गए हैं। You do not bother for the people you are representing.

… (*Interruptions*)

*Not Recorded.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF OVERSEAS INDIANS AFFAIRS (SHRI JAGDISH TYTLER): Sir, what Shri Lalu Prasad has said is that he has threatened Shrimati Sonia Gandhi. That is not a small thing. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am here and I am watching.

…. (Interruptions)

SHRI JAGDISH TYTLER: We are not questioning him on what he said. He has openly threatened that what had happened to late Indira Gandhi will happen to

Shrimati Sonia Gandhi. … *(Interruptio*ns)

MR. SPEAKER: I have noticed what he has done. I shall look into it.

SHRI JAGDISH TYTLER: Is that not important? He has threatened that whatever happened to late Indira Gandhi will happen to ShrimatSonia Gandhi. Is that a small thing? … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am there. I shall look into it and decide.

Shri Madhusudan Mistry.

… (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : ऐसी बात कही गई, इनके दिमाग में क्या है, उस बात का पता लगना चाहिए। …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is very very unfortunate. An hon. Member of your own party has been called to speak on the Motion of Thanks to the President's Address, and you are interrupting.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Do you want the House to run or not?

… (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : What conspiracy is being made against the Government. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Let me know from the Government. Do you want the House to run or not? I am asking all the hon. Members either belonging to this side or the other side. Let us know it first. This *tamasha* should stop.

… (*Interruptions*)

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, I am on a Point of Information. … (*Interruptions*)

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Sir, they were not given permission to reply on the issue. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please sit down. I will name all of you. Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing is being recorded. Nothing will be recorded except the speech made by Shri Mistry.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: You may go on shouting till the end, and I will not hear you. Please sit down.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, कितने दुख की बात है और शर्म की बात है। We are talking of people, and people are not under our consideration.

… (*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य : जार्ज साहब को समझाइए।

अध्यक्ष महोदय : जिसको समझाना है, वह समझेगा। मैं उनको कह रहा हूं जो नहीं समझ रहे हैं। आप बैठ जाएं और शांति से सुनें। हम लोगों ने पांच रोज काम नहीं किया है। मिस्त्री जी आप अपना भााण चालू रखें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राट्रपति जी के भााण से एक-दो अंश पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने अपने भााण में कहा,

"My Government is committed to an inclusive society, a caring polity, and a sharing economy."

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: Please, no cross-talks. If you want to raise an issue, then there is a method of raising it. You must learn it if you do not know it. Mr. Mistry, please carry on.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उनके अभिभााण से मैं सदन में एक-दो अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था,

"My Government is committed to an inclusive society, a caring polity, and a sharing economy."

उसके आगे जाकर उन्होंने यह भी कहा, मैं इनकी जानकारी के लिए कह रहा हूं।

"My Government wants India to shine, but it must shine for all!"

अभी हमारे सामने बैठने वाले सदस्यों की तरफ से एक बात कही गई। यह पार्टी कम्यूनल हार्मोनी, महिला आरक्षण बिल और एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट इन सबके प्र ाति कमिटेड है। महिला आरक्षण की बात इनके मुंह से मैं तब से सुन रहा हूं जब ये लोग इधर बैठते थे और उस समय गुजरात के अंदर कम्यूनल रॉयट्स हुए थे, उस पर चर्चा हो रही थी। गुजरात के अंदर महिलाओं का रेप हुआ था और तब ये कह रहे थे कि एक-दो महिलाओं का रेप हो गया तो क्या हुआ, ऐसा तो होता है।...(व्यवधान) महिलाओं के बारे में इनके दोहरे मानदंड हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : यह बिल्कुल असत्य बात है, ये लोग क्या मजाक बोल रहे हैं...(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, what is this? … (*Interruptions*) This should not be allowed. Can they speak anything in the House? … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I will look into it. If there is anything un-parliamentary, then I will delete it.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I do not understand it. All the hon. Members want every matter to be sorted out immediately.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : अगर असत्य बोल रहे हैं तो बोल दिया है। अब आप इन्हें बोलने दें। अब तो जजमेंट पास कर दिया है। अब इन्हें बोलने दें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : ये कम्यूनल हार्मोनी की बात कर रहे हैं। इनके मुंह से यह अच्छा नहीं लगता है। गुजरात में, इनके पैट्रोनेज के कारण दो हजार लोग मारे गए। इन लोगों को वहां के मुख्य मंत्री का सहारा था। आठ दिन तक उनको कम्पनसेशन नहीं दिया जा सका। ये लोग झारखंड के अंदर और यहां दागी मंत्रियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर की बात कर रहे थे। गुजरात में कम्यूनल वायलेंस के बारे में वहां की सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किया, उसको भी ये याद करें और उस पर भी कुछ कहें। मैं इन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आपके दोहरे मानदंडों को जानते हैं। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, it is 1 o'clock. What does the House propose to do?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, we do not have much time at our disposal, and we have to finish this today. So, I would request the hon. Members, and also request the hon. Speaker to skip the lunch today.

MR. SPEAKER: If all the hon. Members are agreeable, then there will be no lunch hour.

… (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Thank you, Sir.

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : लंच ऑवर तो करवा दें, भले ही आधे घंटे का करवा दें।

13.00 hrs.

MR. SPEAKER: Nobody is prevented from going out and replenish himself or herself.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : राट्रपति जी और यह सरकार सभी तबके के लोगों को साथ रखने के बारे में कमिटेड है। जब से बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट आई है तब से इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है।...(व्यवधान) You cannot listen to criticism. थोड़ी पेशेंस रखिये। आपका फासिस्ट एटीट्यूड और माइंडसेट है और आपको तो केवल अपनी वाह-वाह चाहिए। आप कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। गुजरात में क्या हो रहा है? फोन टेप हो रहे हैं। हमारी सरकार ने तो हरेक गांव के रोड को जोड़ने का काम किया है...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You rightly objected when Shri George Fernandes was speaking. You rightly objected and I also asked them to keep quiet. Now, when they are speaking, you are doing the same thing. You have to set some example.

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : राट्रपति जी के अभिभााण पर बोलिये।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं राट्रपति जी के अभिभााण पर ही बोल रहा हूं।

MR. SPEAKER: Phone tapping is a Central matter.

… (*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : He is not to provoke the other side. Kindly ask him not to provoke the Opposition. He is making a provocative speech.

MR. SPEAKER: I did not know that each only has to congratulate the other.

श्री खारबेल स्वाईं : प्रवोक करने का काम तो हम भी कर सकते हैं।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am only saying, within the norms of parliamentary behaviour, if you raise any issue, I shall allow it. I am requesting all sides, all hon. Members, to please allow others to speak. Please develop the art of listening also. That is also important. In a parliamentary democracy, we should be ready to listen to others viewpoint. That is the crux of democracy. I am saying this from whatever little I know, subject to Mr. Swain's understanding and decision.

SHRI KHARABELA SWAIN : Art of speaking should also be developed; that is also very important.

MR. SPEAKER: Everyone is not so articulate as you are.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am appealing to all of you that when your turn will come -- the Leader of Opposition will also speak and others will speak -- you can give a fitting reply, a more strong reply.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र कायम करने के लिए कमिटेड है। हमने इस देश को जात-पांत, हिंदू-मुस्लिम में डिवाइड करने का काम नहीं किया है जोकि आप आज तक करते रहे हैं। सत्ता हासिल करने के लिए रिलीजिएस लीडर्स को आप पार्टी के अंदर लाए। जो भगवा कपड़े पहनते हैं और जिनको हम नमन् करते हैं तथा जिनके हम पैर छूते हैं। भगवा कपड़ा तो त्याग की निशानी है लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए आप उनको पार्टी में लाए। गुजरात के अंदर जो सबसे बड़ा संप्रदाय है, जिनको आपकी तरफ से एनकरेजमेंट मिलता रहा है, उनके साधुओं की सैक्स सीडी बिक रही हैं (व्यवधान) बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद आपके पैरों की जमीन खिसक रही है (व्यवधान) आप जस्टीफाई नहीं कर सकते हैं (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में इतने सारे लोग जो बेघरबार हुए, क्या आपने एक गज जमीन भी उन बेघर, गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए दी है। एक भी कैम्प में क्या आपके लीडर्स गये। मैं तो अपोजीशन लीडर्स, आपको उस समय के मिनिस्टर्स से पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी कैंप में जाकर आपने पूछा कि उन लोगों का

क्या नुकसान हुआ हैं ?

13.05 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)SHRI MADHUSUDAN MISTRY : We are committed to communal harmony in this couny. That is why I am telling you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आप समझें या नहीं। आइए, बताइए कि क्या चल रहा है? गुजरात और राजस्थान में जाकर देख लीजिए। ...(व्यवधान) आप चुप रहिए। यह कमिटमैंट की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं। अभी एम्पलॉयमैंट गारंटी एक्ट की बात की गई। माननीय सदस्य को पता नहीं होगा कि उसकी क्या स्थिति है? ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। वह इस सैशन में पास भी होगा। पहली बार राट्रपति के अभिभाण में पूरे देश के गांवों के लिए और भारत निर्माण के लिए जो चार-पांच-छः मिनिमम चीजें बतायी गई हैं, उसे पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है। गांव के एक आदमी को सौ दिन की मजदूरी देना छोटी बात नहीं है। आज करोड़ों घर ऐसे हैं जिन की रोज की पांच रुपए की आमदनी नहीं है। यूपीए सरकार ने एक घर के अन्दर सौ दिन की मजदूरी और वह भी मीनिमम वेज रेट से देने की बात कही है। अच्छी क्रांति की बात की गई है। गांवों में इनकम की जो हालत है, वह सभी जानते हैं। वहां जो पैसा जाना चाहिए, उसकी तरफ यह एक सही कदम है। यह बात इनको पसंद नहीं है। यह हमें बता रहे हैं कि दोहरे मापदंड हैं। आपके दोहरे मापदंड हैं। आप यहां हिन्दू की बात करते हैं। इनके जो एक मिनिस्टर पैसा लेते पकड़े गए, वह सौगंध खा रहे थे। ये बाहर बात करेंगे राम की लेकिन वह कह रहे थे कि पैसा सब कुछ नहीं लेकिन खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं है। यह आपके मिनिस्टर ने कहा है। यह आपके दोहरे मापदंड हैं। आप एक धर्म से हेट करते हैं लेकिन उनके स्कूल के अन्दर अपने बच्चों को भेजते हैं। उनसे आपको कोई परहेज नहीं है। उनके कोटे के मकान है लेकिन उनके ऊपर हमला किया जाता है। उन्हीं के एजुकेशनल इनस्टीटयूशन्स के अन्दर सबसे ज्यादा आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं। मैं आपको और पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके ये दोहरे मापदंड हैं। बैनर्जी कमीशन और उजागर करेगा कि हादसा किस तरह हुआ? उसके बारे में अभी डाउट किए जा रहे हैं। शंका की जा रही है ...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : वह बैनर्जी कमीशन नहीं है। वह बैनर्जी कमेटी है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : वह कमीशन भी हो जाएगा। आप चिन्ता मत करिए। सवाल कमेटी या कमीशन का नहीं है। सवाल इस बात है कि किस तरह से रेल के डिब्बे में आग लगायी गई, जिस में कार सेवक थे ...(व्यवधान) आप उसे भुलाना चाहते हैं और थोपना चाहते हैं कि इसके पीछे पूरी कॉन्सीप्रेसी थी। कॉन्सीप्रेसी नहीं थी। ...(व्यवधान) I have not yielded. Why is he standing up and speaking, Sir? … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Swain, please do not speak without the permission of the Chair. … (*Interruptions*)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : There is an allegation by a senior police officer on the Government of Gujarat that he was tutored as to what to speak and what not to speak before the Nanavati Commission.

यह सब पेपर में आया है। ऐसे आदमियों के साथ उन्होंने मैनेज करके …(व्यवधान)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what Rule?

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : We are supposed to move our amendments to the Motion of Thanks to President's Address within fifteen minutes of the debate being taken up. We have given a lot of amendments to be moved. When can we move these amendments, Sir?

उपाध्यक्ष महोदयः चेयर से सबमिट हो चुका है।

… (*Interruptions*)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : No announcement has been made in the House.

उपाध्यक्ष महोदयः एनाउंसमैंट हो चुका है। मिस्त्री जी, आप अपनी स्पीच कंटीन्यू रखिए।

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्ति करना चाहूंगा कि पूरे देश में आवक की क्रांति शूरू हो गई है। यूपीए सरकार ने हर घर में पैसा पहुंचाने का काम किया है। राट्रपति जी ने अपने अभिभााण में इस बात को रखा है। हम उसे पूरा करने की तरफ जा रहे हैं। हमारा मैनिफैस्टो पांच साल का है और हम पांच साल रहेंगे।

यह सरकार पूरे पांच साल चलेगी । इस सरकार ने मेनिफेस्टो में जो लिखा है उस पर अमल किया ह, और नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अमल करके सरकार बजट के अंतर्गत जितने भी प्रावधान हो सकते हैं, उनको करने का प्रयास कर रही है । इस सरकार ने इस देश के अंदर सभी गांवों को रोड, ड्रिंकिंग वाटर और काम्यूनिकेशन से जोड़ा है जिससे गांवों में शहरों जैसी सभी सुविधाएं मिल सकें। मैं याद दिलाना चाहता हूं, माननीय राट्रपति जी ने अपने अभिभााण में कहा - India should shine and it should shine for all यही हमारी मंशा और कमिटमेंट है । यह भारत निर्माण की बात है । एनडीए सरकार ने जो नीतियां बनाई थीं, उनके परिणाम उनकी आंखों के सामने हैं और उसी के कारण आज वे सामने बैठे हैं ।

जहां तक डिफेंस के बजट की बात है, डिफेंस का बजट बहुत बड़ा है, 83,000 करोड़ का है । उसमें फिसकल रिस्पांसिबिल्टी एंड बजट मैनेजमेंट बिल का जो प्र ाावधान है, उसे सामने रखते हुए इस सरकार ने पहली बार ऐसा बजट पेश किया है जिससे फिसकल डेफिसिट कम होगा । इतना ही नहीं इसमें किसी प्राइम रिस्पांसिबिल्टी को शर्क नहीं किया गया है, हटाया भी नहीं गया है । नेशनल कॉमन प्रोग्राम के मुताबिक सभी चीज़ें की गई हैं ।

हम गांवों को कॉम्यूनिकेशन से जोड़ना चाहते हैं । हर एक गांव में टेलिफोन ले जाना चाहते हैं । इसमें जितनी अड़चनें और दिक्कते हैं, उन्हे दूर करेंगे । यह सरकार डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए आज भी कमिटिड है । इसी सरकार की वजह से देश के इलैक्शन रेगुलर होते हैं, असैम्बली में सरकारें बनती हैं और सुचारू रूप से कार्य का संचालन होता है । लेकिन आज हो क्या रहा है? इस देश के अंदर हमने टेलीफोन के माध्यम से देश को कनैक्ट किया है लेकिन मेरी खुद की स्टेट में इन्हीं की पार्टी के राज्यसभा के एक एमपी ने उन्हीं के चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलीगेशन लगाया कि मेरे, एमपी और एमएलए के फोन गुजरात में टेप किए जाते हैं । आप इसका जवाब नहीं दे सकते । मैं इसकी इंक्वायरी के लिए नोटिस भी देने वाला हूं । गुजरात में एमपी और एमएलए के फोन टेप करने का एलीगेशन, गुजरात के जो एमपी हैं उन्होंने रिकॉर्ड के आधार पर रूलिंग पार्टी के प्रेजीडेंट को चिट्ठी लिखी कि हमारे यहां टेलीफोन टेप किए जाते हैं और इस संबंध में इंक्वायरी की जाए । इसके लिए हम भी मिनिस्ट्री को लिखेंगे । टेलीफोन टेप करने की बात करने वाले ये एमपी आज हमें सिखा रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ स्टेट्स में एडेयर नहीं कर सके हैं । हमने आपका एटीटयूड मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों स्टेट्स में देखा है । वहां आपका डिजाइन बिल्कुल समान है कि हर एक जगह दंगे करवाओ और राज करो। आपका माइंड डेवलपमेंट वाला नहीं है इसलिए आप इसे कभी कर भी नहीं सकते । एक बार भूल से आप लोग यहां आ गए, आप वह मंशा छोड़ दीजिए, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठिए । जब हम वहां पर थे तो आप हाऊस न चलने देने वाले लोग कम्प्लेंट करते थे । डेमोक्रेसी का गला घोंटने वाली, हाऊस न चलने देने की प्रक्रिया चलाने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राट्रपति ने अपने भााण के आखिरी पैराग्राफ में कहाद है कि हर एक एमपी पार्लियामेंट के अंदर अपने काम को याद करे, उसके लिए समय दे । लेकिन छोटी-छोटी बातों में हाऊस नहीं चलने दिया जाता है, हाऊस को रैनसम पर लिया जाता है । ये लोग साईन करके बैठ जाते हैं और खुश होते हैं कि आज हमने हाऊस नहीं चलने दिया ।

मैं इन से पूछना चाहता हूं कि ये किस मुंह से बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश के चुने हुये प्रतिनिधि जब सदन में अपनी बात रखने के लिये खड़े होते हैं तो उन्हें अपनी बात रखने नहीं दी जाती है। हमारी सरकार गांवों में सड़क से जोड़ने की बात डिज़ास्टर सिचुएशन, पीने के पानी की स्थिति, खेती के विकास और राट्र की समृद्धि, आदिवासी, दलित और स्त्रीवर्ग के उत्थान के बारे में सोच रखती है जिसे राट्रपति जी के अभिभााण में नज़रिये के रूप में पेश किया गया है। इस कारण महामहिम के अभिभााण में एक ब्लू प्रिंट परिलक्षित किया गया है। उन्होंने सरकार की प्रायरिटीज गिनाई हैं जिन्हें बजट में रिफलैक्ट किया गया है। जब बजट पर चर्चा होगी, उस समय मैं अपनी बात रखूंगा ।

उपाध्यक्ष जी, मैं राट्रपति जी के अभिभाण के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सरकार के पूरे ढांचे की प्रायरिटीज को लिस्टेड किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सामने बैठे हुये लोगों को परमात्मसद्बुद्धि दे। इस सदन में अच्छे लोग काम करने आते हैं जो खड़े होकर जनता के हित में सवाल उठाते हैं, ये लोग डिस्टर्ब न करें। मेरा दावा है कि यह सरकार पूरे पांच साल चलेगी। इन लोगों की यह मंशा पूरी नहीं होगी, ये जहां बैठे हुये हैं, पांच साल तक वहीं बैठे रहेंगे।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address. The President's Address was made at the back-drop of a national disaster Tsunami. I congratulate this Government the way it has taken prompt action in regard to providing rehabilitation and relief to the thousands and thousands of affected people. I also congratulate this Government for not allowing foreigners to intervene in our relief and rehabilitation activities. The entire country was shaken and the entire country stood as a rock at the time of disaster.

The mandate of the people in the last Lok Sabha elections was a mandate for change. Our Finance Minister started his Budget speech referring to this change. He has said that the Government has chartered a new path that is more acceptable to the people of this country and that will bring greatest good to the people. He has also referred to the change in the policy. The people of our country in the last Lok Sabha elections not only wanted a change in the ruling formation but also wanted a change in the policy. The people of our country feel that here is a Government that would take care of 80 to 90 per cent people of our country who are farmers, agricultural labourers, working class and middle class people. That is why, we, the Left parties have been asking and demanding that there should be a change in the policy of this Government. We endorse the Common Minimum Programme that was formulated because a number of issues and programmes have been included in it.

They have all been included in the National Common Minimum Programme, which are for the welfare of the majority of the people of our country.

Sir, hon. Rashtrapati-ji has referred to our Rural India. India lives in villages. In his Address, he said: 'My Government is committed to giving a new deal to Rural India This new deal involves, among other things: reversing the declining trend in investment in agriculture; stepping up credit flow to farmers; enhancing public investment in irrigation and wasteland development; increasing funds for agricultural research and extension; creation a single market for agricultural produce; investing in rural healthcare and education; promoting rural electrification and rural roads; setting up commodities futures markets and insuring against risk in farming and rural business.'… *(Interruption*s) Sir, the situation is worsening. There has been decline in the agricultural growth in the last consecutive three years. It is less tn the growth in population. The food grain production has fallen below the rate of population growth. During Nineties, it was leading to an absolute decline in the *per capita* of Indian output.

Sir, the average number of days work for agricultural workers has declined all over the country. The rural development expenditure, which was 14 per cent in the Eighth Five Year Plan, has come down to only five per cent in the Ninth Five year Plan. There has been a drastic cut, and it is because of the decline in investment in the rural areas. In case of agriculture, in case of healthcare, in case of education and in case of employment, it has caused great distress among the rural poor. This distress is not confined to only the rural poor, it is also confined to a large section of the peasantry. There is a wide gap between the higher input price and lower output price.

What have we seen during the last six years of the NDA regime? They had gradually reduced the Government support to the agriculture. As a result of this, there has been an increase in the production cost of the agricultural commodities and the farmers did not get the fair remunerative price. It is because of the switching over from the food grains to cash crop, commercial crop, that there has been decline in the food grain production.

As a result of this, in the past, we have seen a number of starvation deaths in many parts of our country. We have not heard, in the past, about thousands and thousands of farmers committing suicide. But we have seen that in the last few years? Why do farmers commit suicide? Farmers are today also committing suicide because farmers are not getting fair price or remunerative price for their produce. The Government gradually has reduced subsidy on fertiliser, subsidy on agricultural inputs, subsidy on electricity tariffs, etc. As a result of this, there had been an increase in the production cost and this had adversely affected agricultural inputs.

What we have seen in the past is that there is growing unemployment among agricultural labourers which constitute 22 crore out of 40 crore workers. Rashtrapatiji has correctly referred to the condition of the people living in the rural areas.

Institutional funding or institutional credit to agriculture and capital formation in agriculture have been gradually reduced. There has not been any extension of irrigated areas in the last several years. He has correctly mentioned about the

enhancement of public investment in irrigation and wasteland development, which is the need of the hour, if we want to protect the interests of the farmers of our country.

This is because of the wrong policy which was being pursued by the earlier Government. LPG, the policy of Liberalisation, Privatisation and Globalisation has resulted in disaster; it has an adverse effect on our economy, on our employment growth, on poverty levels, on agricultural production and on the condition in which our farmers live today.

The growth in employment in rural areas is only 0.58 per cent whereas in the urban areas, it is 1.58 per cent. That is why, the main thrust of Rashtrapatiji in his Address was on agriculture which is the mainstay of our rural people, the people living in villages.

Rashtrapatiji in his Address has also referred about the labourers belonging to unorganised sector. We have a 40-crore workforce in our country. Out of that 40-crore, we have 37.5 crore in the unorganised sector. They are agricultural labourers, the labourers engaged in beedi industry, in construction work and in such other industry in the unorganised or informal sector. What is the condition of these workers?

The social security, which these workers used to enjoy, has been gradually reduced. Although in the National Common Minimum Programme it has been stated that the UPA Government will bring legislation for agricultural workers, there has been no mention of it in the President"""""""

I was listening to the speech of Shri George Fernandes. He was explaining who is secular and who is not secular. He said that if any member goes from the BJP to other party, he becomes non-communal and if any member joins BJP, he becomes communal. Secularism or communalism does not depend on any individual but it depends on the policy of a political party. We cannot forget what happened in Gujarat. We cannot justify the incident that took place in Gujarat in 2002 by referring something which happened some 20 years back in Delhi. We condemned that incident also. Our Party, the Communist Party of India (Marxist) condemned what happened in 1984. In order to justify what happened in Gujarat, if we refer to what happened in 1984, it is not correct. If there are only riots, then we would say that it is communal. We have seen during six years of NDA regime how our educational system was saffronised, how their ideology was cleverly and clandestinely infiltrated into all the aspects of our society, and how many thousand crores of rupees came from foreign countries for all these things. What is the need of the hour today? The mandate of the last Lok Sabha election was against communal ideology of Bharatiya Janata Party and their hidden agenda. There is a need for detoxification of the wrong that had been done during the six years of NDA regime.

It has been mentioned very appropriately in the Common Minimum Programme of the UPA Government that this Government will bring a suitable legislation to tackle communal problem in our country. India is a secular country. We cannot compare ourselves with Pakistan. This ideology of secularism was maligned and distorted during the six years rule of the previous NDA Government. There is a need to restore it back to its earlier position.

Sir, same is the case with regard to our foreign policy. The concept of non-alignment had been integrated in our foreign policy since our early days of Independence. We have seen how this policy of non-alignment, which had been pursued for long, was distorted in the past few years. We expressed ourselves during the Korean war of 1952; we expressed ourselves when Vietnam was attacked, but we did not express ourselves strongly enough when Iraq was attacked in 2002. We had to wait for long seven days to express our views. We had to stall the proceedings of the House for three days. When the Resolution on this issue was adopted, it was adopted in Hindi and the word `condemn' was not used in that Resolution. What we have seen in the last six years of the NDA rule is how this age-old concept of non-alignment was distorted. There is a need to restore that to its earlier position. How can we support the cause of the people of Palestine who are struggling for a separate motherland by having a good relation with Israel? Can we really extend our support to the cause of the Palestinians by improving our relations with Israel who are occupying a portion of Palestine? Can these two things – supporting the cause of the Palestinians on the one hand and also improving our relations with Israel – go together? I would like to request this Government to have a re-think on our relations with Israel.

Sir, the earlier Government pursued the policy of disinvestment. It is good that it has been mentioned specifically in the Common Minimum Programme of the UPA Government that profit-making public sector undertaking would be neither privatised nor disinvested.

Sir, our Party is extending support to this Government from outside. Shri George Fernandes had referred to a statement made by Shri Prakash Karat about the policy of the Congress Government. We have to fight the Congress Party in our State. There would be elections to the State Assembly in the year 2006 in our State and we will have to fight the Congress Party politically. There is no existence of BJP in our State. Their representation is nil. We do not support the policies of the Congress. But why are we then supporting the Government at the Centre? It is because we do not want a fascist party like the BJP to come to power at the Centre. After the incidents in Gujarat and at Manoharpur in Orissa, which George Saheb termed as an international conspiracy, they could only be called a fascist party.

Under the leadership of Bajrang Dal, he said that it was an international conspiracy to malign them. Today, that party is not only communal but a fascist party also after the Gujarat incident. We will not allow a fascist party to come to power. We are supporting the National Common Minimum Programme and our support is confined to this Programme. We have been asking this Government to always stick to this Programme. We have been telling them that whenever we find that their action or policy is outside this one, then we will not support them. But that does not mean that we will allow a fascist party to come to power again. We will not allow them to come to power. Sir, there are other issues also.… (*Interruptions*)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, the hon. Member is going away from the actual subject of Motion of Thanks to President's Address. … (*Interruptions*) The results in Bihar and Jharkhand have proved it.… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not to be recorded.

*(Interruptions)**

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will come to Bihar and Jharkhand. I know that as I have mentioned about Manoharpur, you are speaking like this…… (*Interruptions*)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Manoharpur is *sub judice.*

SHRI BASU DEB ACHARIA : It is not *sub judice*. How can you say that it is *sub judice*? How can you support it? How can you say that it was an international conspiracy?… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : The Government of Naveen Patnaik there has condemned this incident..… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why should a profit-making public sector undertaking be disinvested?… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने आधा घंटा ले लिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं सर, मेरे 2-3 इमापोर्टेंट पाइंट्स बाकी हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, वह यह है कि क्या आप ही आपकी पार्टी का सारा टाइम लेंगे? आपकी पार्टी का टाइम 42 मिनट है तो क्या आप...

*Not Recorded.

श्री बसुदेव आचार्य : हम पांच मिनट में खत्म कर देंगे। उन लोगों को 10-10, 20-20 मिनट दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके 2-3 और भी मैम्बर्स बोलने वाले हैं, अगर उनको नहीं बुलाना तो मुझे कोई एतराज नहीं है। You can continue then.

श्री बसुदेव आचार्य : उन लोगों को भी बुलाएंगे। आप हमें बराबर 5-10 मिनट ज्यादा देते हैं, आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं। उस समय 1984 में ये लोग नहीं थे, 1984 में हम और आप थे। उस समय बी.जे.पी. के दो लोग चुनकर आये थे, आपको मालूम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अच्छी तरह से याद है।

श्री बसुदेव आचार्य : बी.जे.पी. के दो लोग चुनकर आये थे। आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Will the hon. Member yield for a minute?

SHRI BASU DEB ACHARIA : No, I am not yielding. Why is NTPC, a public sector undertaking, now being proposed to be disinvested may be by 5 per cent?… (*Interruptions*) Why is there a proposal for disinvestment of Bharat Heavy Electricals which is a *Nava Ratna? …* (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड पर कुछ नहीं आयेगा।

*(Interruptions)**

SHRI BASU DEB ACHARIA : They wanted to disinvest it. His Government wanted to disinvest and privatise NALCO, and we protested against it. We told that Government to back out from that decision..… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not to be recorded.

*(Interruptions)**

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, there are some decisions which we feel are not in the interest of our country like allowing foreign banks..… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will be recorded.

*(Interruptions)**

*Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only the speech of Mr. Basudeb Acharia should be recorded.

SHRI BASU DEB ACHARIA : There are some decisions like allowing foreign banks to grab the share of the private sector banks of our country upto 74 per cent. We are opposing FDI in the case of telecom, civil aviation and insurance. They allowed insurance opening upto 26 per cent. When Mr. George Fernandes was in the Government, they allowed it. Now, when they are in the Opposition, they are opposing it.… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why are you making noise? Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : But we were consistent when we were supporting the United Front Government. We opposed the opening up of insurance sector. Why were we opposing it? Our opposition is not only for the sake of opposition. Why should we allow more than 49 per cent in the telecom sector? Even when there is 49 per cent cap, they have violated in a number of foreign banks. Is it that in order to legalise it that this cap is being enhanced? We are not against FDI.

FDI to West Bengal from Japan is the highest in comparison to other States. If FDI helps us to increase our productivity, employment, and bring new technology, then we have no objection. But when our own companies are capable of doing things, why should we privatise? Why should we privatise two airports, Delhi and Mumbai? We have submitted an alternative proposal to the hon. Prime Minister. Airports Authority of India"""""""

rule was imposed at that time. It was passed in this House. But there was no majority for NDA in Rajya Sabha. So, they could not do that in Rajya Sabha. Hence, that Government was restored back to power. They tried to intervene by using article 355, not 356, in West Bengal. Did you not send your officers to West Bengal when you received a compliant from your colleague? What will happen to the Centre-State relations? They have jeopardised the federal structure of our country. That is the ideology of the BJP. They are not for the federal structure. They are for the unitary structure. They have weakened and destroyed the federal structure of our country. We had to put the UPA Government in power. We are supporting this Government for charting an alternative path.

Today, millions and millions of the people of our country are suffering.

Coming to the National Rural Employment Guarantee Scheme, I would like to say that there are a number of lacunae. Our proposal is not only for the rural areas but also for the urban areas. Lakhs and lakhs of unemployed youth are there in the urban areas. We have a large number of slums. I know that people are residing in the slums for the last thirty years. If the Government today removes them from there, where will they go? So, there is a need for a Slum Policy. At present, there is no such Slum Policy in our country. Today, lakhs and lakhs of people are living in the slums. Mr. Minister, you cannot throw away those people today saying that you need the land or saying that they are residing in a land which belongs to some Department of the Government – say the Railways.

About the Railways, I know about Malegaon in Assam where 10,000 families are residing in a Railway land since Partition. Where will they go now if you evict them? So, lakhs and lakhs of such people are residing in the slums. Therefore, there should be a policy for rehabilitation of such people. At present, there is no such national policy for rehabilitation of such people.… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you, Shri Acharia. Now, you conclude.

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों का मामला है।…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have to conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will finish my speech within two minutes. He has referred to the adivasis. It is good. The adivasis and the tribal people are there. These tribals are residing in the forest land for years together. Shri Baalu was the Forest Minister at that time. Because of the Supreme Court's order, some State Governments started evicting the adivasis from the forest land. But West Bengal and some two or three States said that they would not evict any adivasi because the tribal people are living there for years together, for generations together. He has referred to that. Therefore, I demand that the UPA Government should bring forward a suitable legislation to legitimise the stay of the people who are living in the forest land.

Next, I come to right to strike. This issue is being debated. Shri George Fernandes has not mentioned about it because he is already a changed man now. He is not the man of 1974 when he spearheaded the railway strike. So, right to strike should be there.

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का सारा टाइम ओवर हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : सारा टाइम ओवर नहीं हुआ है, अभी दस मिनट बचे हुए हैं।…(व्यवधान)

MR. DEPTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : So, the Government should bring forward a legislation to include the right to strike of the workers and employees. That should be included in the Fundamental Rights of our Constitution.… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Prof. Ram Gopal Yadav to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will conclude now. I hope that the Government will think over the issues that we are raising and will try to have an alternate policy for the protection of the interests of the millions and millions of the people of our country.

With these words, I thank you for giving me this opportunity.

SHRI C. KUPPUSAMI : Mr. Deputy-Speaker, Sir, in Tamil Nadu, all the MLAs belonging to the Opposition have been arrested.… (*Interruptions*)

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): Sir, in Tamil Nadu, all the MLAs belonging to the Opposition have been arrested. They have been thrown away.… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will give you time. Whatever you may like to say, you can say at your own time allotted to you.

… (*Interruptions*)

SHRI A. KRISHNASWAMY : All the MLAs belonging to the Opposition have been evicted from the Legislative Assembly.… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: When your time comes, you can say anything.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: When your Member speaks, he can say about it.

SHRI A. KRISHNASWAMY : They are criticising the Central Government also. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to me. When your Member speaks, at that time, he can say whatever he likes to say but not now. This is not the 'Zero Hour.'

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, let one Member speak on this issue.… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: First of all, you should all take your seats.

… (*Interruptions*)

*Not Recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि जब आपके सदस्य की बोलने की बारी आएगी, आप उस समय बोलिएगा। लेकिन इस तरह हाउस को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है।

14.00 hrs.

… (*Interruptions*)

SHRI C. KUPPUSAMI : Sir, all the leaders of Opposition have been arrested. All the MLAs belonging to Opposition Parties have been thrown out of the Assembly. There is no democracy at all in the State of Tamil Nadu… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। प्रो. राम गोपाल यादव के बोलने के बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, not only the Members belonging to DMK Party, but Members belonging to Congress and other Parties have also been thrown out of the Assembly… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, all the leaders of Opposition have been arrested and all the MLAs belonging to Opposition Parties have been thrown out of the Assembly. Please allow them to speak for two minutes… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: After Prof. Ram Gopal Yadav, I will give them time.

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राट्रपति जी ने बहुत सारे बिन्दुओं पर सरकार की नीतियों के संबंध में बात कही है। मैं उनमें से कुछ प्रमुख बिन्दुओं तक ही अपने को सीमित रखता हूं। पिछले कई वर्ाों से हम देखते आये हैं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण घोाणा होती है, चाहे वह महामहिम राट्रपति जी के मुंह से हो या सरकार की विभिन्न एजेंसियों के जरिये हो, खेती गांव और किसानों के बारे में बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही जाती हैं लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है।

वर्ा 1950 में देश की कुल जीडीपी का 50 फीसदी हिस्सा एग्रीक्लचर सैक्टर का था जो अब घटकर 24 परसेंट से भी कम रह गया है। टैन्थ फाइव ईयर प्लान के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने 25 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन उसको केवल 13 हजार करोड़ रुपये का ही एलोकेशन हुआ। 25 हजार करोड़ रुपये के अगेन्स्ट 13 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन एग्रीक्लचर सैक्टर को जो आज देश के लगभग 65 परसेंट लोगों को रोजगार दे रहा है, बहुत कम है। देश में टोटल जितना इम्प्लायमैंट है, उसका लगभग 65 प्रतिशत केवल एग्रीक्ल्चर सैक्टर के द्वारा दिया जाता है। आज भी देश की 72 से लेकर 74 प्रतिशत जनता एग्रीक्लचर पर ही निर्भर करती है। इसके लिए एलोकेशन में निरंतर कमी की जा रही है।

वर्ा 2004-05 में एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने 4513 करोड़ रुपये की डिमांड की थी जबकि उसे केवल 2670 करोड़ रुपया ही दिया गया। यही नहीं, एग्रीक्लचर सैक्टर में जो इन्वेस्टमैंट है, वह भी निरंतर कम हो रहा है। 1990 में एजीडीपी का इन्वेस्टमैंट 1.9 परसेंट था जो घटकर पिछले साल तक 1.3 परसेंट रह गया है। एक तरफ आप कोई एलोकेशन नहीं करेंगे, एग्रीक्लचर में इन्वेस्टमैंट कम करेंगे और फिर कहेंगे कि हम भारत के गांवों को न्यू डील दे रहे हैं। जब ये लोग (एन.डी.ए.) सत्ता में थे तब कहते थे कि देश चमकेगा। ये भारत को शाइन कर रहे थे और अब ये लोग (U.P.A.) नया भारत बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। एक तरफ यह कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को ऋण देंगे। हालांकि ऋण देने से कोई लाभ नहीं होता। केवल कर्ज का झुनझुना देकर यह कहा जाये कि हम गांवों की शक्ल बदलने के लिए किसानों को खेती के लिए ऋण देने जा रहे हैं, तो उससे उनकी शक्ल नहीं बदल सकती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक जो टोटल ऋण देते हैं, उसका कम से कम 18% फार्मर्स को देना चाहिए लेकिन आप उनको कितना दे रहे हैं ?

60 प्रतिशत से भी अधिक राट्रीयकृत बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया है और जो बैंक ऋण देती भी हैं वह लगातार लोगों को बहुत परेशान करने के बाद देती हैं और मजबूरन किसान या गरीब आदमी महाजन के पास चला जाता है। ऋण के ब्याज के बारे में एग्रीकल्चर कमेटी ने बार-बार सिफारिश की है कि यह सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए। नाबार्ड के माध्यम से कोआपरेटिव बैंक्स वगैरह जो सबसे ज्यादा किसान को ऋण देती हैं, 5 प्रतिशत या सवा पांच प्रतिशत से लेकर पौने 6 प्रतिशत तक ब्याज देती है और 5 और 6 प्रतिशत के ब्याज पर जो पैसा जाता है, उस पर किसान से 9 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, यानी मिल रहा है 5 प्रतिशत पर और दे रहे हैं 9 से लेकर 15 प्रतिशत तक। एग्रीकल्चर कमेटी ने सिफारिश की कि 9 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए तो उसमें कर दिया गया कि जो 50,000 तक का ऋण लेगा, उसके लिए 9 प्रतिशत है लेकिन उसमें भी जहां किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, जैसे हम कोलार में गए और भी कई जगह गये हैं तो वहां लोगों से पूछने के बाद पता चला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है और बैंक देती नहीं हैं तो किसान महाजन के पास जाता है। सोसाइड का एक बड़ा कारण यह भी है। न तो क्रैडिट फ्लो बढ़ रहा है और न ही इंवेस्टमेंट का ट्रैंड रिवर्स हो रहा है, जैसा महामहिम राट्रपति जी ने कहा है। इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा है और दूसरे जो फसल किसान पैदा करता है, उस पर जो लागत आती है, उसके हिसाब से मूल्य नहीं दिया जा रहा है।

मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और जो एग्रीकल्चर से संबंधित विशेाज्ञ हैं, उन्होंने सर्वे करने के बाद बताया कि धान की फसल जब पैदा होती है तो उस पर लागत मूल्य पिछले वर्ा 680 रुपया प्रति क्विंटल निकाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को रिकमेंड किया कि धान का मूल्य 750 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाए लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस 560 रुपया प्रति क्विंटल देना डिसाइड हुआ। लागत मूल्य 680 रुपया प्रति क्विंटल है और दिया जा रहा है 560 रुपया प्रति क्विंटल। अगर ऐसे ही चला तो कैसे आप नया भारत बना लेंगे ?

जहां दो तिहाई से तीन चौथाई लोग कृाि पर निर्भर हों और किसान की दुर्गति यह है कि जो वह लगा रहा है, उसकी लागत भी नहीं मिल रही है तो आप कुछ नहीं दे सकते। केवल बहुत लम्बी और बड़ी बातें कह सकते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च की भी बात उसमें कही गई। मैं लम्बी बात नहीं करूंगा लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक अकेली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन जो है, इसमें 3700 वैकेंसीज हैं। पवार साहब ने भी माना कि एक सिफारिश नहीं मानी गई है जो वैकेंसी से संबंधित है । अकेले 1400 वैकेंसीज साइंटिस्ट्स की हैं। मान्यवर, क्या वैज्ञानिक का काम कोई नॉन-टैक्नीकल आदमी कर सकता है ? कई वर्ाों से 1400 वैज्ञानिकों की वैकेंसीज आईसीएआर में खाली हैं तो आप नया रिसर्च कैसे लाएंगे ? आप देखते हैं, रोजाना पेपर में आता रहता है कि यह सीड बढ़िया है, यह अच्छा है, सब अपना पैदा करते रहते हैं, कोई नया रिसर्च नहीं हो पा रहा है। कृाि विज्ञान केन्द्र खाली पड़े हैं। रोगों की रोकथाम का कोई इन्तजाम नहीं हो पा रहा है। ऐसी व्यवस्था है।

एक बात एनीमल हस्बैंड्री के बारे में मैं कहना चाहता हूं, उसमें जिक्र किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। 2003-2004 में देश को जो कुल राजस्व की प्र ाप्ति हुई है, वह धान से 74,000 करोड़ थी। गेहूं से 44,000 करोड़ थी और गन्ना से 28,000 करोड़ थी लेकिन अकेले दूध से ही 1,03,000 करोड़ थी। लेकिन पशु-धन के संबंध में पिछले कई वर्ाों से पूरी तरह से नैगलीजेंस बरती जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है।

माननीय श्री ओला साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इनके राज्य में बहुत अच्छी नस्ल के गाय और बैल मिलते हैं, लेकिन हम वहाँ से दूध के लिए भी कोई अच्छी गाय नहीं ला सकते हैं। हमारे किसान लोग गाय-बछड़ों का व्यापार करते थे। इनके झुंझनू और पर्वतसर में जाते थे। पर्वतसर में गाय की बेहतरीन प्रजाति मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दो साल पहले हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने पर्वतसर से दो गाय मंगवाई थीं। ये गाय ट्रक से आ रही थीं। उनको अलवर में रोक लिया गया और मुश्किल पैदा हो गई। जब स्वयं श्री मुलायम सिंह यादव ने अलवर के एसएसपी और राजस्थान सरकार के वरिठ अधिकारियों से टेलीफोन पर बात की कि ये गाय दूध के लिए मंगवाई हैं, तब कहीं जाकर उन गाय को लाया जा सका। पशुधन का कहीं से भी मूवमेंट नहीं हो रहा है और सारा पशुधन खत्म हो रहा है, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति पशुधन से हो रही है। यह पूर्णतः उपेक्षित क्षेत्र है। इसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हो रही है। एग्रीकल्चर कमेटी ने सिफारिश की थी कि जिस तरह से आईसीएआर है, उसी तरह से आईसीवीआर की स्थापना की जानी चाहिए। क्या कारण है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है? पशुओं को होने वाले विभिन्न घातक रोगों जैसे खुरपका आदि का इलाज अभी तक संभव नहीं हो सका है।

महोदय, महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण में फूड प्रोशिसिंग की बात कही गयी है। ब्राजील में में 80 प्रतिशत फूड प्रोशेसिंग होती है और ब्रिटेन तथा अमेरिका में यह 60 से 70 प्रतिशत तक है, लेकिन हमारे यहाँ यह मात्र दो प्रतिशत है। हमारे यहाँ प्रतिर्वा 50,000 करोड़ रूपए के फल और सब्जियाँ नट हो जाते हैं। इस दिशा में अब तक सरकार की ओर से क्या किया गया है?

जल संरक्षण एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। प्रतिर्वा वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। दस वार्षों के बाद देश के तमाम हिस्सों में आदमी पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। पिछली बार हमारे वित्त मंत्री का बजट सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई थी कि व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तालाब खोदे जाएंगे, लेकिन इस बार उसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। जल संरक्षण के लिए एक बड़ी परियोजना बननी चाहिए वरना यह देश के लिए एक अशुभ संकेत है। प्रत्येक र्वा भयानक बाढ़ से देश में बिहार का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। हर साल हम इस पर चर्चा करते हैं कि नेपाल से आने वाली नदियाँ बिहार में बाढ़ लाती हैं, इसके लिए नेपाल सरकार से बातचीत होनी चाहिए, कोई बाँध बनना चाहिए। फिर से बाढ़ आने वाली है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि इस संबंध में क्या इन्तजाम किए गए हैं? हम लोग बाढ़ की चर्चा करते हैं लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, जो हर साल बर्बाद होते जाते हैं, उनके लिए कहीं कोई चिन्ता दिखाई नहीं देती है। जब बाढ़ आ जाती है, तब यहाँ से कमेटी जाती है। कृाि विभाग कमेटी भेजता है और गृह मंत्रालय मदद करता है ।

महोदय, विद्युतीकरण का उल्लेख किया गया है। देश भर में लगभग 1.25 लाख गांव ऐसे हैं जहाँ विद्युतीकरण होना बाकी है। इनमें से 82 हजार गांव केवल उत्तर प्रदेश, बिहार औरट्ठें झारखण्ड में । उत्तर प्रदेश की स्थिति ज्यादा खराब है, जहाँ मात्र 19 प्रतिशत घरों में ही बिजली उपलब्ध है। बिहार और झारखण्ड में यह प्रतिशत क्रमशः 9 और 10 प्रतिशत है। मेरा आग्रह यह है कि जिस प्रकार से देश के कुछ राज्यों को 90 और 10 के अनुपात में सहायता देते हैं, जिसमें राज्य सरकार को मात्र 10 प्रतिशत धनराशि लगानी होती है और केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत धनराशि वहन करती है, उसी प्रकार हिन्दुस्तान के इन तीन बड़े राज्यों को भी सहायता दी जानी चाहिए। अभी उनके लिए जो कार्यक्रम बनते हैं उनमें 25 प्रतिशत राशि सहायता के रूप में, 25 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में और 50 प्र ातिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा लगानी होती है। आप देश के विद्युतीकरण के लिए चाहे जो भी कहते रहें, लेकिन अगर इन तीन राज्यों के विद्युतीकरण पर ध्यान न दिया गया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार समाज में कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड का विद्युतीकरण किए जाने के लिए, उत्तरांचल, पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर की ही भांति, सहायता दी जानी चाहिए।

मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। राट्रपति जी के अभिभााण में पड़ोसियों से सम्बन्धों की बात का भी जिक्र किया गया है। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम यहां कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरह से रिश्ते पड़ोसी देशों के साथ होने चाहिए, वैसे नहीं हैं। सफल विदेश नीति वह होती है जब कोई देश अपनी नीति के चलते मित्र देशों की संख्या बढ़ाए और शत्रु देशों की संख्या कम करे। दुर्भाग्य से हमारे मित्र देशों की संख्या में कमी हो रही है, बढ़ नहीं रही है। यह हमारी विदेश नीति की असफलता का एक प्रमाण है।

महामहिम राट्रपति जी ने अपने अभिभााण में कहा है कि बांडुंग सम्मेलन की पचासवीं र्वागांठ आ रही है। मैं यहां इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं और सरकार के जिम्मेदार लोग यहां बैठे हुए हैं, वे सुन नहीं रहे हैं। हम लोग 50 साल पहले भी बांडुंग सम्मेलन में गए थे। तब भारत तीसरे विश्व का नेता था। नेहरू, नासिर और टीटो को तीसरे विश्व का अगुवा माना जाता था। हम लोग बांडुंग सम्मेलन की पचासवीं र्वागांठ मनाते समय यह भी सोचें कि हम तब कहां थे और आज कहां हैं। इस पर भी हमें आत्म चिंतन करना होगा।

एक बात की काफी चर्चा हुई। इधर बैठे हुए और उधर बैठे हुए माननीय सदस्य काफी उस पर शोर करते हैं। हम बीच में बैठते हैं इसलिए ज्यादा शोर नहीं मचाते। चर्चा हुई साम्प्रदायिकता की। मैं उसकी दो घटनाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक ताकतें चाहे खुले रूप में हो या छिपे रूप में हों, जिस रूप में भी हों, देश के लिए घातक हैं। इधर बैठने वाले खुले रूप में साम्प्रदायिक हैं तो उधर बैठने वाले छद्म रूप में साम्प्रदायिक हैं। जिस समय इन्दिरा गांधी जी की हत्या हुई तो उसके बाद दिल्ली और उसके आसपास जो कुछ हुआ, वह सबको मालूम है। सिख कम्यूनटी की अलग पहचान रही है। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो या सीमा पर जब-जब भी खतरा आया है, तब-तब इस कम्यूनिटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की आबादी में कम अनुपात होने पर भी इसे कम्यूनिटी का बहुत ज्यादा योगदान रहा है और इनकी शौर्यता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस वक्त इन लोगों को जिस तरह से टार्चर किया गया, डिमोरेलाइज किया गया और इनकी हत्या की गई, वैसी घटना और कोई देखने में नहीं आती। मैंने स्वयं देखा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लोग इस कम्यूनिटी को लूट रहे थे। कानपुर में सिखों को बचाने के लिए हमें गोलियां चलानी पड़ीं और हम लोगों ने इटावा में सिखों को बचाने के लिए गोलियां चलाईं।

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : ऐसी बात न कहें कि हम भी शामिल थे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Satyanarayan Jatiya, please sit down.

… (*Interruptions*)

प्रो. राम गोपाल यादव : मैंने खुद देखा है, ये साथ में थे।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

प्रो. राम गोपाल यादव : यह पूरी तरह से सत्य है।...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : सिख दंगों में हमारा कोई हाथ नहीं था।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kharabela Swain, please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Prof. Ram Gopal Yadav.

*(Interruptions)**

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं कह रहा था जब-जब साम्प्रदायिक शक्तियों को खत्म करने की बात आती है, गुजरात में जो कुछ हुआ, पूरे देश के माथे पर एक कलंक था। उसके लिए केवल दिल्ली में बैठी हुई सरकार और वहां की सरकार जिम्मेदार थी। उसी वक्त केन्द्र सरकार को गुजरात की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन जब-जब इन साम्प्रदायिक शक्तियों को खत्म करने या कमजोर करने की जरूरत होती है, जहां ये खत्म हो सकती हैं, वहां कांग्रेस और ये एक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब विधान सभा के चुनाव हुए थे, तो मुलायम सिंह जी को खत्म करने के लिए अटल जी जो बोल रहे थे, वही भााा सोनिया जी बोल रही थीं।

राजनैतिक रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर खत्म हो जाते तो आप यहां नहीं बैठ सकते थे। मुलायम सिंह जी ने ही इन्हें 50-60 सीटों से 10 सीटों पर ला दिया और अब तो वहां पर इनके जमानत जब्त वाले लोग ही रह गये हैं। लेकिन आप दोनों एक थे। इस बात पर बहुत सारे दल हमसे सहमत हैं लेकिन इस बात को कह नहीं सकते हैं। माननीय वासुदेव दा यहां से चले गये हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी इनसे सावधान रहियेगा। कांग्रेस के लोग जिसका समर्थन लेते हैं, उसी को धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश करते हैं। धीरे से माननीय लालू जी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। यह इनकी पॉलिसी है। इस बात को समझना चाहिए। ...(व्यवधान)

* Not Recorded.

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Sir, he has no right to talk about the Congress. … (*Interruptions)* How can you allow this? … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Prof. Yadav, please conclude.

श्री गुलाम नबी आज़ाद : प्रो. साहब, आप भी इनके साथ हो गये हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात खत्म कीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बीजेपी को खत्म करने के लिए ईमानदारी से मेहनत होनी चाहिए। आजाद जी, आप तो खत्म करना चाहते हैं।...(व्यवधान) आपका तो पूरा परिवार आतंकवादियों से परेशान है। लेकिन जो दिशा देने वाले लोग हैं, वे ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। वे बीजेपी से मिलकर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के वे लोग आपकी निगाह में महत्वपूर्ण हैं लेकिन हमारी निगाह में महत्वपूर्ण नहीं है। वे ही ऐसा काम कर रहे हैं। साम्प्रदायिकता की बात बार-बार चलती है। .....(व्यवधान) कौन बीजेपी से मिला हुआ है, सब जानते हैं। मैं यह बात कहना नहीं चाहता हूं। मेरे पास सारे तथ्य हैं। .....(व्यवधान) चाहे किसान की बात हो, खेत और गांवों के विद्युत्तीकरण की बात हो, हमें उसके लिए ईमानदारी से सोचना होगा। हां, यह ठीक है कि अभी जो दैवी आपदा आई, उसमें सारा हिंदुस्तान और भारत सरकार ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है और उसके लिए पूरी सरकार बधाई ही पात्र है। जो काम ठीक है, वह ठीक ही कहना चाहिए। लेकिन आज किसान की निरंतर उपेक्षा हो रही है। किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। अगर किसान को उसकी लागत से कम पैसा मिलेगा तो उनकी आत्महत्याओं को आप रोक नहीं सकते हैं। उनके लिए ब्याज की दर कम कीजिए और एक-तिहाई असिंचित जमीन में सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम कीजिए, जिसका इंतजाम आज नहीं है। जल संरक्षण की व्यवस्था गांवों में होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर बैंकों से कर्जा लेने में किसान को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, ऐसे इंतजाम करने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए जो समय दिया गया, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी पूर्ववक्ताओं ने विस्तार से महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण पर अपने विचार रखे। मैं राट्रीय जनता दल

की ओर से महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण में व्यक्त बातों को बारी-बारी से उठाते हुए अधिकांश बिन्दुओं को यहां रखूंगा। उनके अभिभााण में सुनामी की घटना का जिक्र हुआ और कहा गया कि इसके लिए विदेशों से किसी तरह की सहायता नहीं ली गई। इस बात पर अमल करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राट्रपति जी के अभिभााण पर मुद्रास्फीति को कम करने और उसको मेनटेन करने के लिए चर्चा हुई है । ग्रामीण क्षेत्रों और कृाि क्षेत्रों में जो बातें बताई गई हैं, हमें आशा है यदि सचमुच उसका पालन हो तो एक नए भारत को बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम सिद्ध हो सकता है । अभिभााण में कृाि के क्षेत्र में विशेा पहल करने की बातें कही गई हैं । भारत एक कृाि प्रधान राट्र है । लंबे समय से तोते की तरह हम रटते आ रहे हैं और रटाए भी जाते हैं कि भारतर्वा एक कृाि प्रधान राट्र है। पिछले दिनों जो सरकारें रही हैं, कृाि के क्षेत्र में जो उनके एलोकेशन्स रहे हैं, वे बिल्कुल पर्याप्त नहीं हैं । जिसका नतीजा यह हुआ कि कृाि, जिसमें अधिकतम नैचुरल रिसोर्सिस लगते हैं, उसके बाद मानव संसाधन लगते हैं, हमारे फंड बहुत कम मात्रा में इन रिसोर्सिस की अपेक्षा लगाए जाते हैं । इकी मात्रा बहुत कम करके अन्याय करने पर पिछली सरकारें तुली हुई थीं । इसमें एलोकेशन की बात कही गई है और इसे प्र ाथमिकता देने की बात कही गई है, उस पर हम जोर देना चाहेंगे ।

हमारे देश में 75 प्रतिशत लोग कृाि पर निर्भर हैं । छोटे और बड़े किसान, मजदूर, खेतिहर किसान और कई तमाम लोगों की निर्भरता कृाि पर है और इस देश में बचे हुए 25 प्रतिशत की निर्भरता किसानों के द्वारा उत्पादित अनाज पर है । हम इस बात पर थोड़ा जोर देना चाहेंगे कि कृाि की तरफ सरकार का विशेा घ्यान जाना चाहिए । अभिभााण में इस पर जोर अवश्य दिया गया है लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि लंबे समय से जो ग्रामीण भारत के लिए नारों की श्रृंखला तो चली लेकिन जब कार्य करने की बात आई, जब रिसर्च और डेवलपमेंट की बात आई, किसानों को सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराने की बात आई, संसाधनों को जमीन तक पहुंचाने की बात आई, उसमें हम विफल होते रहे हैं । आने वाले दिनों में किसान, कृाि और कृाि उत्पादों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य केंद्रित होना चाहिए। जो अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं, जिनमें नैचुरल रिसोर्सिस अधिक मात्रा में हैं, उन उत्पादन तंत्रों को, जिनमें कृाि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उन एलोकेशन्स की ओर ध्यान जाना चाहिए ।

हम कृाि में विशेा तौर से फल, सब्जी, दुग्ध उत्पादन और जो एग्रीकल्वरल फील्ड्स हैं, फिशरीज़ है, उन क्षेत्रों की ओर ध्यान जाना चाहिए जिनकी चर्चा विस्तार से अभिभााण में की गई है । ऐसे क्षेत्रों की अधिक उत्पादकता बढ़ाकर हम राट्रीय उत्पादकता को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं । पिछले दिनों कृाि अनुसंधानों का ि वकेंद्रीकरण नहीं हो पाया । पिछली सरकारें थीं, उस काल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीटयूशन्स की जो आउटपुट थी, उसे गांव के छोटे बड़े, मध्यम दर्जे के किसानों तक बात पहुंचाने की ज़हमत नहीं उठाई गई ।

उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राट्रपति जी के अभिभााण में 'गांवों की ओर ग्रामीण भारत की नई पहल' के अंतर्गत ग्रामिण क्षेत्रों में कृाि अनुसंधानों के आउटपुट्स हैं, छोटे-छोटे किसानों को पहुंचाकर कृाि उत्पादन की ओर वह नया कदम बढाने का काम करे।

अभी प्रो. राम गोपाल यादव जी फल एवं सब्जी उत्पादन के विाय में बता रहे थे। हमारे देश में फल एवं सब्जी तथा दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों की बहुत सारी समस्यायें हैं। हमारे देश में प्रतिर्वा 50 हजार करोड़ रुपये की सब्जी और फल बर्बाद होते हैं। किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। पिछड़े राज्यों यथा- बिहार और उड़ीसा में हौर्टिकल्वर का बहुत स्कोप है और इसीलिये वहां उत्पादन भी ज्यादा होता है। बिहार में दूसरे उद्योग नाममात्र के हैं। लोगों की कृाि पर अधिकतम निर्भरता है। किसान हर र्वा बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में रहता है। उर्वरा भूमि के कारण फल सब्जी का उत्पादन बहुत होता है। इसलिये उस क्षेत्र में कृाि पर आधारित उद्योग लगाये जाने की जरूरत है। कृाि उत्पादन के साथ साथ एलायड एग्रीकल्वर प्रोड्क्ट पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाये जाने की जरूरत है। चूंकि फल और सब्जी का सपोर्ट प्राइस एवं सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं है, इसलिये किसानों को लाभ नहीं मिलता है। इसके अंतर्गत फल सब्जी आधारित उद्योग लगाये जाने चाहिये। इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलेपमेंट इंस्टीट्युशन्स अधिक संख्या में खोले जाने चाहिये। बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उ पक्रमों को खोले जाने की आवश्यकता है। बिहार बटवारे के बाद उसकी स्थिति लगभग गम्भीर है, उस क्षेत्र में कहीं कोई उद्योग नहीं है।

मैं महामहिम राट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की बात कही है। मेरा कहना है कि आज से पहले शायद ही कभी नीयत और नीति साथ साथ चले हों। यदि हमारी सरकार इस मामले में सचमुच गम्भीर है तो नीयत और नीति दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा। हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उस आरक्षण में सामाजिक न्याय की बात कही जाती है, सैकुलरिज्म की बात कही जाती है लेकिन हमारे संविधान में दिये गये प्रावधानों को अमलीजामा पहनाने वालों की नीयत में बहुत साफगोई नहीं दिखती रही है। इस कारण बहुत दिनों से यह गैर-बराबरी का खेल खेले जाते रहे हैं। हम सामाजिक न्याय के तहत चाहे वह महिला आरक्षण की बात हो, चाहे डाउनट्रोडन इकोनिमकली वीकर सैक्शन की बात हो, उन तमाम लोगों के साथ साफ नीयत के साथ इन्साफ होना चाहिये। ऐसा नहीं हो कि इन्साफ के नाम पर एक सैक्शन से इन्साफ करते-करते दूसरे सैक्शन के लिये नाइन्साफी की बात उठने लगे। इसलिये मै सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि जब इस सदन के माध्यम से महिला आरक्षण की बात कही गई है, हम इसके पक्षधर हैं लेकिन इस आरक्षण के अंदर ही अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछडी जाति की महिलाओं को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये। इसी प्र ाकार माइनौरटीज का आरक्षण भी किया जाना चाहिये। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रावधानों से हम उन के साथ न्याय कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष जी, राट्रपति जी के अभिभााण में निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कही गई है। मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस तरह की बात लोक सभा में और सड़कों पर डिसकस होती रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये उन्होंने अपने अभिभााण में इस बात को उठाया है।

लेकिन इसके साथ-साथ उसमें यह भी जोड़ना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों के लोगों को भी निजी क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यह सामाजिक न्याय के कदम का हिस्सा है। हम हर जगह सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अत: इन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए।

अभी श्री जॉर्ज फर्नांडीज जी इस सदन में बोल रहे थे। मैं बचपन से उन्हें एक सोशलिस्ट के रूप में जानता था। मैं पिछले कुछ वर्षों में भगवा सोशलिस्ट जैसे शब्दों को भी सुनता रहा हूं। अभी कुछ दिनों से मैं उनकी भााा सुन रहा हूं और उनके कार्य-कलापों को देख रहा हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कट्टर सोशलिस्ट माने जाने वाले लोगों की भााा सिर्फ सत्ता और पद के लोभ में कैसे बदलती है, इस बात को हमने इस सदन में देखा है। आर.एस.एस. और बजरंग दल की वकालत करने वाले ऐसे लोग, जिनका नाम लेकर सोशलिज्म को भारत में सराहा जाता था, उनके ऐसे दोहरे रूप और दोहरे चरित्र को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं और कहना चाहता हूं कि श्री जॉर्ज फर्नांडीज के मुंह से धर्मनिरपेक्षता की बातें अच्छी नहीं लगती। अब धर्मनिरपेक्षता की बातें वैसे लोगों को करनी चाहिए

जिनके जेहन में इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए वेदना हो, चाहे वे सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, चाहे कोई भी भााई और धार्मिक अल्पसंख्यक हों और जो तमाम तरह के लोगों के हित की बातें समझते हों और उनकी दिक्कतों, परेशानियों को महसूस करते हों।

"गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमैन्ट" पर सिगनेचर करने वाले लोग जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि देश मन ही मन उन्हें कोसता होगा । इस देश का जो सिद्धांत है, संविधान है, उसका जो सेक्युलर स्ट्रक्चर है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें संकीर्णता से ऊपर उठकर काम करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए। आपकी पार्टी के एक स्पीकर और हैं, आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता : मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। पिछले चुनाव में विकास का जो नारा दिया गया, विकास की बातें करने वाले घूम-घूम कर ि वकास के मुद्दे का प्रचार कर रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की जनता को गुजरात का विकास का मॉडल पसंद नहीं आया, इसलिए उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ऐसे लोग यहां आकर विकास की परिभाा को सदन में बदलकर पेश करते हैं। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, जिन्होंने पिछले छः वर्ों में पूरे देश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की। इन्होंने गुजरात को एक जलता हुआ शोला बना दिया। ऐसे लोगों के मुंह से धर्मनिरपेक्षता शब्द सदन में अच्छा नहीं लगता। हमारी यू.पी.ए. सरकार का हर कदम सेक्युलरिज्म की ओर अग्रसर है। इसके लिए हम अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी सरकार द्वारा इस ओर पहल किये जाने पर हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज पर्यावरण के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिये जाने की जरूरत है, क्योंकि यह ग्लोबल इम्पॉर्टेन्स का मामला है। हमारा जो वाटर लैवल है, जमीन में पानी का जो स्तर है, वह लगातार घटता जा रहा है और वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है, उसके पतला होने और उसमें छेद होने की वजह से सम्पूर्ण मानवता के ऊपर एक खतरा पैदा हो गया है। इसलिए इस क्षेत्र में रिसर्च एडं डेवलपमैन्ट पर इम्फेसिस दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में पूरा जोर लगाकर हमें काम करना चाहिए। हमें पार्टी पालिटिक्स तथा विभिन्न तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर इस विाय में गंभीरता से काम करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राट्रपति के अभिभाण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय राट्रपति जी के अभिभाण पर सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में भाग लेने और बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

माननीय राट्रपति महोदय ने अभिभाण में सरकार के जिन विचारों को प्रस्तुत किया है, उनमें से कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर मैं अपना मत स्पट करना चाहूँगा। राट्रपति महोदय ने पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में नये कदम जोड़ने की बात कही है। हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि उन्हे हमसे असुरक्षा महसूस न हो, बल्कि वे महसूस करें कि हमारे पड़ोसी ताकतवर हैं और हमारी मदद करेंगे। हमें पड़ोसी मुल्कों से ऐसे संबंध बनाने चाहिए जिनसे उनके अंदर सुरक्षा की भावना पनपे। आज नेपाल में जिस प्रकार लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, उस मामले में हम अपनी आँखें बंद किये चुपचाप बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि वह हिन्दुस्तान के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है।

आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये। सुनामी आपदा के दौरान जिस तरीके से सरकार ने, हिन्दुस्तान के लोगों ने और हमारी सेना ने रीति-नीति अपनाकर इस विपदा से मुक्ति दिलाई, उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं और सबका धन्यवाद पूरे हिन्दुस्तान ने और इस सदन ने किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं भरे सदन में एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिस पर न ही राट्रपति महोदय ने और न ही सरकार ने कोई स्पट बात कही है। सुनामी आपदा के दौरान अखबारों में एक खबर छपी थी कि नागपट्टिनम क्षेत्र में दलितों और अछूतों को राहत कैम्पों में घुसने नहीं दिया गया। हमने होम अफेयर्स की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिग में इसे प्रमुखता से रखा था कि हमारे अछूत भाई, जो सुनामी पीड़ित हैं, उन्हे भी राहत कैम्पों में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें खाने का सामान मुहैया कराना तो दूर रहा, शौचालय में भी उनको घुसने नहीं दिया गया। यूनिसैफ द्वारा मुहैया कराई गई पीने के पानी की बोतलें तक उन्हें नहीं दी गईं। इस बात को लेकर आज भी हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हिन्दुस्तान को आज़ाद हुए आज 57 वर्ा बीत गए, लेकिन जिन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की, उनके खिलाफ सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया और न ही कोई सख्ती किये जाने की बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत में हिंसा की वारदातें होती रही हैं, चाहे जम्मू-कश्मीर का मामला हो या नक्सली हिंसा हो अथवा हमारे पूर्वोत्तर राज्य हों, जहां हिन्दुस्तान के नौजवान साथियों की राहें भटक गईं थीं। माननीय राट्रपति महोदय के अभिभाण में तीन प्रमुख समस्याएं बताई गई हैं, जिन पर हम लोगों को विचार करना है। मैं राट्रपति महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने तीन प्रमुख मुद्दों को, जिनसे हिन्दुस्तान भर के नौजवान डिस्टर्ब होते हैं, उनको अभिभाण में जोड़ने का प्रयत्न किया है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर सख्ती से निपटेगी।

अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी श्वेत पत्र लाने की बात सरकार द्वारा कही गई है। इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और मांग करते हैं कि राट्रपति महोदय सरकार को निर्देश दें कि हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों - चाहे वे मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों - उनकी दशा पर भी एक श्वेत पत्र जारी कर, उन्हे नौकरियों में आरक्षण देकर, उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर उठाने की बात स्पट रूप से रखी जाए।

गांवों तथा शहरों के बीच जो विकास का अनुपात है, आज वह बदल रहा है। हमें गांवों को भी साथ-साथ जोड़ना पड़ेगा और विकास की मुख्यधारा में लाना पड़ेगा। अगर हम गांवों को मुख्यधारा में नहीं जोड़ सकते, तो हमारा हिन्दुस्तान वास्तव में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। सांप्रदायिकता और हिंसा से निपटने के लिए अलग से अभिभाण में कानून बनाने की बात कही गई है। सरकार के इस कदम का हम लोग स्वागत करते हैं। वर्तमान समय में सरकार ने प्र ामुख रूप से एक परिवार को कम से कम सौ दिन रोज़गार देने की बात कही है। हम सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में मजबूत कदम उठाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में "काम के बदले अनाज" योजना, "अन्नपूर्णा योजना" या स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना जैसी कई योजनाएं शुरू तो की गईं हैं, जिनके लिए केन्द्र सरकार से पैसा और अनाज जाता रहा है, लेकिन बड़े दुख का विाय है कि पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पर भारत सरकार के पैसे का, जो 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का गेहूँ, चावल या खाद्यान्न भेजा गया था, उसे फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर और फर्जी संस्थाएं गठित कर बेचने का काम वहां के दलालों और बिचौलियों ने किया है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि केन्द्र सरकार जो पैसा राज्यों को भेजती है, उसका उपयोग वास्तव मे गरीबों और दलितों के हित में किया जा सके और उसका दुरुपयोग न हो।

तभी हम हिंदुस्तान के लोगों को वास्तव में अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं । बहुत-सी बातें और भी हैं, जिनके बारे में आज हम प्रमुख रूप से कहना चाहते हैं ।

हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने 26 तारीख को रेल बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि सारे हिंदुस्तान में आठ कारखानें लगाए जाएंगे । लेकिन बड़ा कट होता है कि उन कारखानों में से चार कारखानें केवल बिहार में लगेंगे और बाकी चार हिंदुस्तान में लगाए जाएंगे । हमारा बिहार से विरोध नहीं है । बिहार हिंदुस्तान का बहुत पिछड़ा राज्य है। लेकिन हम आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत-से पिछड़े जिले हैं । हमारे जनपद उन्नाव में रेल पहिए का कारखाना या रेल कारखाना लगा दिया जाए तो हमारे पिछड़े क्षेत्र को विकसित होने का मौका मिल सकेगा । मैं रोज अखबारों में पढ़ा करता हूं और सौभाग्य से मैं ऐसे जनपद से चुन कर आता हूं जहां हमारी बाईं तरफ हिंदुस्तान की सरकार चलाने वाले लोग वर्तमान समय में हैं और दाईं ओर पूर्व में हिंदुस्तान की सरकार चला रहे थे, वे बैठे हैं । साथ ही गंगा पार करके चले जाइए तो हिंदुस्तान के गृह मंत्री रहते हैं । बहुत दुःख होता है, हम सौतेली माँ के बेटे की तरह चिल्लाते रहते हैं । रायबरेली की जो सांसद हैं, वे कहतीं हैं कि चार सौ करोड़ रुपये ले लीजिए । उन्होंने 235 करोड़ रुपये उन्होंने नहरों के विकास के लिए दिए, 111 करोड़ रुपये सड़कों के विकास के लिए दिए और 35 करोड़ रुपये अस्पतालों के विकास के लिए दिए । माननीय अटल जी ने अपने क्षेत्र को जो चाहे दिया, वे उस समय सरकार में थे । श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने एक विशेा पैकेज कानपुर को दिया । हम भी मतदाताओं के द्वारा चुन कर आते हैं । हम को वही मतदाता वोट देते है हैं जो रायबरेली वालों को देते हैं या कानपुर वालों को देते हैं या लखनऊ वालों को देते हैं, तो फिर उन्नाव के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? उन्नाव के मतदाताओं से स्पट रूप से कह दिया जाए कि अगर इस तरह की अशोभनीय बातें होंगी तो उन्नाव के मतदाता अपने मतदान का उपयोग न करें । उन्नाव के सांसद की जरूरत इस लोकसभा में कतई नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि उन्नाव को भी विशेा पैकेज दिया जाए जिससे हम अपना चेहरा अपने निर्वाचन क्षेत्र में दिखा सकें कि उन्नाव के लोगों के भी जज्बात हैं । उनके सांसद में भी लड़ने की क्षमता है । अगर हम गरीब खानदान में पैदा हुए और हमारे पीछे राजनीतिक सरपरस्ती नहीं है तो हमारे मतदाताओं को सड़क पर छोड़ने का काम किया जाता है । इस बात पर हम खेद व्यक्त करते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय राट्रपति महोदय के अभिभााण का समर्थन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हिंदुस्तान के विकास के लिए, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर या किसानों के मुद्दे पर, बहुजन समाज पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी।

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम भारत के राट्रपति के अभिभााण पर हम धन्यवाद प्रस्ताव के लिए यहां पर चर्चा कर रहे हैं । निश्चित रूप से इस चर्चा की जो शुरूआत हुई है उसमें जो प्राकृतिक विपदा, त्रास्दी जो झेलने का काम हमारे देश में हजारों लोगों को और दुनिया में लाखों लोगों को करना पड़ा है उसके बारे में कहा गया है कि उसके प्रबंधन में जो-जो भी हमने सहायता और सहयोग दिया है निश्चित रूप से यह हमारे देश में जो सं वेदन है उसको प्रकट करने का काम करता है। निश्चित रूप से अभी-अभी बहुत काम करना बाकी है और उस संरचना के काम में केवल कुछ समय तक ध्यान जाए, यह बात नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों के पुनर्वास के लिए, रोजगार के लिए और जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक जरूरतें हैं उनका ठीक-ठीक प्रबंधन होना चाहिए । वैसे भी हमारा यह देश ऐसा देश है, जहां हमारी अन्तनिहित शक्ति है वह अत्यंत प्रभावी है ।

उपाध्यक्ष महोदय,

देश की प्रच्छन्न क्षमता पर मुझे विश्वास है,

नाभि में इसके अमरता का अनश्वर वास है।

शक्तियां सहार की खेलें भले ही नाटक कई

राट्र की संजीवनी शक्ति में छिपे सामर्थ्य पर मुझे विश्वास है।

राट्र का यह छिपा हुआ सामर्थ्य संजीवनी शक्ति की तरह इन सारे लोगों के पुनर्जीवन का काम, पुनर्वास का काम कर सकेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने राट्रपति महोदय से अभिभााण के आठवें अनच्छेद में कहलवाया है कि

> "राजनैतिक मुख्यधारा में निहित बहुलवाद, सर्वसमावेश, पंथनिरपेक्षता तथा समता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक वृद्धि की ओर वापसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का राट्र के प्रति महत्वपूर्ण योगदान रहा है।"

उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें हमारे संविधान में हैं और उसी के लिए सरकार यदि अपना संकल्प करती है, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि वह यह काम किस प्रकार करेगी, उसके लिए सरकार को उपाय करने के लिए वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है।

महोदय, बजट के प्रावधानों में भी हमने देखा है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी, जिसमें मजदूर, खेतिहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो देश की आबादी का प्रायः 40 करोड़ हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। देश की आबादी के 40 करोड़ लोगों को यदि छोड़ दिया गया, तो फिर अभिभााण में अभिप्राय रहेगा क्या?

महोदय, भााण में अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक, भाााई अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, विकलांग, युवा आदि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, फिर चाहे वह स्वतंत्रता दिवस का संदेश हो या और कोई संदेश हो, सरकार का भााण इन सारी बातों के समावेश के बिना पूरा नहीं होता। हम इनके बारे में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार इनकी सहायता करने वाले हैं, कैसे इन्हें सहायता पहुंचाने वाले हैं, उसके बारे में इसमें कोई उपाय नहीं है।

महोदय, हमने बजट में रोजगार के बारे में प्रावधान किया है। रोजगार देने हेतु 100 दिन की गारंटी देने वाला विधेयक हम लेकर आने वाले हैं, लेकिन उसमें रोजगार की कोई गारंटी है ही नहीं। प्रत्येक परिवार से एक आदमी को रोजगार का प्रस्ताव है और यदि उस व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, तो फिर आप उसे उस श्रेणी से हटा देंगे। यदि वह आदमी किसी दूसरी जगह चला जाए, जहां उसे बेहतर रोजगार मिल रहा है, तो उसका रोजगार समाप्त हो जाएगा। उसे जो वेज देने वाले हैं, वह भी निश्चित नहीं है। वेज का मामला आपने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है और कहा है कि राज्य सरकारें, जो मिनीमम वेज है, वह देंगी। केन्द्रीय सरकार ने मजदूरों के लिए मिनीमम वेज तय किया है उसे बढाने की दृटि से भी देखा जाए।

महोदय, हमारे देश में श्रमिक वर्ग बहुत बड़ा है। जो मजदूर देश के निर्माण में लगा है, अपनी शक्ति और संयम से देश का निर्माण कर रहा है, उसके बारे में कोई प्रभावी उपाय इसमें नहीं है। जो अभिभााण है, उसमें सारी बातें कही गई हैं। अभिभााण में लोकतंत्र की आस्थाओं को स्थापित करने के बारे में कहा गया है। निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।

महोदय, हम संविधान की उद्देशिका (प्रीएम्बल) में पढ़ते हैं कि भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे - ये सारी बातें हम करने वाले हैं, लेकिन कैसे, यह नहीं बताया गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, समानता, सद्भाव, बंधुता, सामाजिक, आर्थिक समानता सबको देने वाले हैं, लेकिन देंगे कब ? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव जी, आप उन्हें बोलते समय बीच में डिस्टर्ब न कीजिए। जब आपकी बारी आए, तब आप अपनी बात कहिएगा। जब आप बोलेंगे, तब ये भी आपको नहीं टोकेंगे। आप डिस्टर्ब न करिए।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : ये सारी बातें हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये सारी बातें ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. सत्यनारायण जटिया जी, आप चेयर को एड्रैस करिए।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : मैं एग्रीकल्चर वर्कर्स की बात कर रहा हूं। आप उसे किस प्रकार रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान देंगे ? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर जटिया, आप चेयर को एड्रेस करके बोलिए।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : कृाि श्रमिकों के लिए हमने पेंशन, बीमा की योजना शुरू की। यदि आप सुनना चाहते हैं, तो मैं सुना सकता हूं। जो हमने किया है वह बात मैं अपने आप से नहीं कहना चाहता था।

15.00 hrs.

वह योजना यह थी कि एक रुपया मजदूर और एक रुपया सरकार मिलाएगी। उसे पूरे समय तक, पेंशन मिलने तक, उसकी उम्र 60 वर्ा होने तक वह उसे कंटीन्यू करता रहेगा। अंत में उसे 1800 रुपए की पेंशन और बीमा की राशि के रूप में डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। यह योजना हमने शुरू की है, ऐसा नहीं है कि हमने योजना शुरू नहीं की है। अब उस योजना को विस्तार देने की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने आप से अपनी सारी बातें कहूं। हमने जो अनुसूचित-जाति के लोगों के लिए किया है, निश्चित रूप से हमने शिक्षा के बारे में उपाय किए हैं। उनके लिए हमने जो स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, उनमें जो मेधावी विद्यार्थी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और दसवीं पास होने के बाद, अपने पास संसाधन न होने के कारण जिनकी पढ़ाई रूक जाती है, उन्हें हमने 60 हजार रुपए प्रथम स्थान पर आने वालों को, दूसरे स्थान पर आने वालों को 50 हजार रुपए और तीसरे स्थान पर आने वालों को 40 हजार रुपए और बाकी के लोगों को दस-दस हजार की स्कॉलरशिप देकर हमने इस बात की शुरुआत की और उस योजना को हमने एक करोड़ से अधिक रुपए से शुरु किया था। अब जरूरत इस बात की है कि इसे विस्तार देने का काम करें। हमने अनुसूचित जाति के बीमार लोगों को सहायता देने के लिए चिकित्सा योजना की शुरुआत की थी और उसमें 50 हजार रुपए भी चिकित्सा उपचार के लिए देने का उपाय किया है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. It is not to be recorded.

*(Interruptions)**

* Not Recorded

डॉ. सत्यनारायण जटिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही मुख़ातिब होकर सारी बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सारे लोग अपनी-अपनी तरह से अपनी-अपनी बातों को कहने के लिए होशियार हैं और

मैं अपनी होशियारी इस तरह बताना नहीं चाहता, जिससे कि मैं अपनी बात न कह सकूं। महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण में सारी बातें आई हैं, उसमें कहा है कि हमने पंथ निरपेक्षता की बात कही है, लेकिन ये बातें करते हुए, किसी एक वर्ग को महत्व देना और बाकी के लोगों को भूला देना ठीक नहीं है। देश का एक

बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो बहुत गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का है। आज उसकी आबादी 25 प्रतिशत हो गई है। निश्चित रूप से उन लोगों तक वे सारी बातें पहुंचने की जरूरत है, जिनके लिए हमने प्रावधान किए हुए हैं। भारत के संविधान में भी इस प्रकार के प्रावधान हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाएगी। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिटतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशे सा वधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोाण से उनकी संरक्षा की जाएगी। भारत के संविधान और नीति निदेशक तत्वों में जो कहा गया है, उसे पूरा करने का दायित्व सरकार का है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, परन्तु इस सारी व्यवस्था में से गरीब जनता का हित संरक्षण करना चाहिए। संतों ने जो कहा है, सतगुरू रवि दास जी ने जो कहा है - "ऐसो चाहूं राज मैं, मिले सबन को अन्न, छोटों-बड़ों सम बसें, रवि दास रहें प्रसन्न।" उनकी जो जरूरत है, उसकी पूर्ति करने के लिए भी अगर कोई रास्ता नहीं है तो वह क्या बात होगी। सारे बजट भााण में जो कहा है, उसमें गरीब वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, कमजोर वर्ग के बारे में, उनकी उन्नति, विकास और रोजगार के बारे में जो संभावनाएं तलाश करनी चाहिए थीं, वे उसमें नहीं की गई है। अभिभााण को पढ़ने में सवा घंटे का समय लगा पचहत्तर मिनट तिहत्तर पैराग्राफ, इसमें उक्त समावेश चाहिए था।

हम जानते हैं कि विकलांग लोगों के बारे में कहा गया और इन लोगों के बारे में यह है कि जो बजट में मिला हुआ है, वह भी 14 जनवरी तक 225 करोड़ 54 लाख रुपए थे, लेकिन उसमें से 57 करोड़ 37 लाख रुपए ही खर्च किए गए। इन्हें जो बजट में मिला हुआ है, उसे खर्च नहीं करने के लिए किसी ने मना नहीं किया। इन सारी बातों को पूरा करना चाहिए। विकलांगता के बारे में छोटा उल्लेख कर बात को खत्म कर दिया है। निश्चित रूप से मनुय के जीवन में जो ि वकलांगता है, उसे समर्थ बनाने के लिए, उसके लिए जो-जो उपाय करने चाहिए, उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए, उसे छोड़ दिया गया है। वृद्धों के बारे में जो विचार होना चाहिए, उनके बारे में भी इसमें कुछ समावेश नहीं किया है। देश की आबादी में प्राय: सात प्रतिशत लोग वृद्ध हैं, उन्हें किस प्रकार से संरक्षा देने वाले हैं, सुरक्षा को आगे बढ़ाने वाले हैं? यह कहा गया कि सरकार ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए उद्योग जगत से विचार-विमर्श करने हेतु मंत्रियों का समूह बनाया है। सरकार उसमें आरक्षण के उपाय करने वाली है। ये मंत्रियों के समूह और फिर आरक्षण के उपाय कैसे लागू होंगे, कौन करने वाले हैं?

इस प्रकार से इन सारी बातों को धकेलते जाना, पीछे-पीछे धकेलते जाना, इससे बात नहीं बनने वाली है। निश्चित रूप से जो उपाय उपलब्ध हैं, उनको निश्चित रूप से कानून के जरिये से लाकर उसे पूरा करने का काम करना चाहिए, तभी जाकर इन सारी बातों को पूरा करने का मौका होगा।

ग्रामीण भारत को नई पहल देने के बारे में वचनबद्धता प्रदर्शित की गई है और उसमें कहा गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों को बढ़ावा और बाकी की बातें कही गई हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आप बिजली के तार तो ले जा सकते हैं, पर इतनी बिजली कहां पैदा होने वाली है? बिजली पैदा करने के लिए जो हमारे पास संसाधन चाहिए, जिस प्रकार का उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, वह बढ़ावा देने के उपाय क्या हैं? आज देश में बिजली की भारी कमी है और हम देखते हैं कि बिजली, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, उसके नहीं होने के कारण से भी देश का सर्वंगीण विकास, देश की सारी बातों को पूरा करने का मौका नहीं है।

कृाि के बारे में पैराग्राफ 20 से लेकर प्रायः 28 पैराग्राफ तक हमने इन सारी बातों को कहा है। इसमें कृाि के अनुसंधान की बातें हैं, पर उसमें किसान का कहां फायदा हो रहा है? किसान के बारे में कोई उपाय नहीं है। उसमें कहा है कि हम किसान को ऋण देने वाले हैं, कर्ज देने वाले हैं। यदि उसे कर्ज दे दिया गया, परन्तु उसकी उपज का उत्पादन लागत के आधार पर समर्थन मूल्य नहीं मिला, बाजार भाव नहीं मिला तो निश्चित रूप से वह होगा, जो कि हम देख रहे हैं, लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस तरह से किसानों के बारे में कर्ज देने की बात तो कही गई, किन्तु उसको जो उत्पादन वह कर रहा है, उसमें जो लागत मूल्य लग रहा है, उन लागत मूल्यों के बारे में लाभकारी मूल्यों की कोई गारण्टी देने की बात नहीं कही है और इस दृटि से इस र्वा का बजट किसान विरोधी है, उसमें किसानों के बारे में कुछ नहीं है। गांव के विकास के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं।

जल संसाधन को बढ़ाने के बारे में बहुत बात कही गई, जल को संसाधन बनाने के लिए निश्चित रूप से एक समय था, जब पहली पंचर्वाीय योजना, दूसरी पंच र्वाीय योजना में जल संसाधन को बढ़ाने के उपाय किये गये, किन्तु बाकी के समय में उसकी उपेक्षा हुई और आज हम देख रहे हैं कि जल संसाधन की कमी होने के कारण से बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए हमें विवश होना पड़ रहा है। कृाि क्षेत्र के बारे में, उसके उत्पादन के बारे में और जो हम फल, सब्जी और बागवानी की बात कर रहे हैं, उसमें बागवानी के बारे में तो अभी बताया गया है कि निश्चित रूप से बागवानी में जितना उत्पादन हो रहा है, उसे खरीदने की क्षमता हमारे लोगों की नहीं है। न्यूट्रीशन चाहिए, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी कैलोरीज चाहिए, वह कैलोरीज प्राप्त करने के लिए लोगों की आय नहीं है, उसके पास साधन नहीं है और उसकी आय नहीं होने के कारण गरीब तबका, जो देश की आबादी का प्रायः 60 ्र ातिशत होता है, उस आबादी को न्यूट्रीशन स्वास्थ आहार के लिए कितनी कैलोरीज की जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए कोई उपाय नहीं है।

श्रमशक्ति के बारे में जिस प्रकार की सारी बातें हैं, इन सारी बातों की उपेक्षा करते हुए भी जो बातें कहलाने का काम किया गया। पैराग्राफ 50 में जो कहा है, मेरी सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द निश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है। साम्प्रदायिक सौहार्द कौन नहीं चाहता, यह बहुत अच्छी बात है, किन्तु इन सारी बातों को करने के लिए देश के संविधान की बातों को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक-एक बात को लेकर अलग-अलग टुकड़ों में देश को विभाजित करने का काम किया जा रहा हैं। इस प्रकार से टुकड़ों में बांटते-बांटते देश कहां चला जायेगा? भारत एक देश है, एक देश, एक रक्त, फिर भी हम विभक्त हैं। एक शक्तिशाली किन्तु दूसरा क्यों अशक्त है, कमजोर है । इस बारे में कहीं तो विचार होना चाहिए। जाति-पांति के फेर में उलझ रहे सब लोग। इन सारी बातों को छोड़कर ही हम एक जन एक राट्र हैं। एक राट्र होने के नाते हमारी ताकत कम नहीं है। इस दृटि से भी कहीं न कहीं सर्वांगीण रूप से, एकात्म रूप से विचार करने की आवश्यकता है । जो-जो भी उपाय हमें करने हैं, इन सारे उपायों के लिए जो संसाधन हमें जुटाने होंगे। इन सारी बातों के रहते हुए भी हम निराश नहीं हैं। किन्तु इस प्रकार से लोगों में भ्रम और संशय फैलाकर, साम्प्रदायिकता की बातों को बड़े जोर से करके हम क्या बताना चाहते हैं? हम एक राट्रीय के नाते, एक समाज होने के नाते हमारी कमजोरी क्या है? इस कमजोरी को देश के विकास के रास्ते से दूर करना चाहिए। साम्प्रदायिकता का हौवा खड़ा करना, संभलकर रहना, यह मुश्किल पैदा हो जायेगी, इन सारी बातों को करने से देश आगे बढ़ने वाला नहीं है इन सारी बातों से भी हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें यदि जान मिली है तो वह जान उस मालिक की मेहरबानी से मिली है और यदि किसी से डरना चाहिए

तो इन्सान से डरने की कोई जरूरत नहीं है हमारे यहां पर बहुत अच्छी उक्ति अर्थवेद में आई है:

यथा द्यौश्च पृथिवी, च न बिभीतो न रियतः। एवा मे प्राण मा विभेः।।

यथाहश्च रात्री च न बिभीतो ने रियतः। एवा मे प्राण मा विभेः।

यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न बिभीतो न रियतः। एवा मे प्राण मा विभेः।।

मेरे प्राण, तूभी कभी न डरते हुए आगे बढ़।

इन बातों को प्रकृति से लेकर कहा गया है, इन सारी बातों में किसी प्रकार का डर नहीं है और इस हेतु किसी से न डरते हुए सारी बातों को करते हुए इस देश और समाज को जोड़ने का काम करें व यदि हम यह काम कर सकें तो राट्र निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे।

मुझे विश्वास है कि हमारा देश विकसित एवं शक्तिशाली राट्र होगा। मेरा देश ऐसा बढ़े जिससे कि दुनिया में इसका नाम हो।

क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में, हम उठें नवप्राण भरने।

नवसर्जन की साध लें, हम उठें निर्माण करने।

साधना के दीप शुभ हों, ज्ञान का आलोक छाए।

नट तृणा के तिमिर हों, देश मेरा जगमगाए।

हम इस देश को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प हैं। सदन में अलग-अलग विचारधाराओं के दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्तु देश को आगे बढ़ाने की दृटि से एक अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब साथ में आएं।

संगच्छध्वं सं वो मनांसि जानताम्

समान मंत्रः समिति समानि।

सबको साथ-साथ लेकर आगे बढ़ने की कल्पना की गई है, उसको सार्थक साकार करें।

सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखभाग्भवेत्।

सभी सुखी हों, सभी निरोग हों एवं सभी कल्याण को देखें और कोई दुखी न हो।

राट्रपति जी ने जो अभिभााण दिया उससे विमत होते हुए भी मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address.

Before I get into the main debate I would like to respond to what Shri George Fernandes mentioned about Shri Prakash Karat and his statements. I am also going through the statements made by Shri Karat. The Left Parties are a constituent of this UPA Government. They have the right to say something on the affairs of this Government. But with all humility I would like to submit that the constituent parties of this Government, particularly the Left Parties have never tried to interfere in the matters of the Government. They are a very respectable party. They have only said about the Common Minimum Programme and they have a right to comment on that. Shri Fernandes mentioned about the manifesto, the address of the hon. President and about the Budget speech delivered by the hon. Finance Minister. He always finds faults with others. But there is no substantial reason for him to say that the UPA Government is not working in accordance with its manifesto or the Common Minimum Programme.

Sir, another hon. Member, Shri Jatiya mentioned about democracy. Congress is the party that brought freedom to this country; Congress is the party that gave a good Constitution to this country; and Congress is the party that brought democracy to this country. Countries like Russia and China do not have good democracies in their own countries. Coming to holding of elections etc., I would like to submit that advanced countries like the United States do not have an Electronic Voting System even today, but India today has got a full Electronic Voting System. This is where the Congress Party has made a contribution to the growth of this country. My party has got a 115 years of national history. The leaders of this party had participated in the freedom struggle. There were other leaders from other parties, like Shri B.T.Ranadive, who were also

involved in the struggle for India's Independence. Congress is the only party that has taken more trouble for bringing freedom to this country.

Sir, Shri Jatiya also mentioned about the problems of the farmers. The problems of the farmers are being fully attended to in the Congress regime. During the time of the late Indira Gandhi in 1979 the concept of giving subsidy to the farmers was brought in. Fertilizer subsidy was first introduced under the signature of the late Indira Gandhi in 1979.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): At that time the Janata Party was in power at the Centre.

DR. CHINTA MOHAN : It happened after the fall of that Government. I was the Minister of Fertilizers at that time and I saw the file also. It was during her time and under her signature that fertilizer subsidy to farmers was introduced.

Coming to the question of giving 100 days of employment I would like to submit that that this UPA Government is fully committed to giving employment to the poor people, particularly in the rural areas. The `Food for Work' programme has already been started. There is no unemployment problem particularly in the rural areas.

I have gone through all the speeches delivered by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad till the President of today. The speech is very lengthy. The President gave his speech for one hour and fifteen minutes. It was very illustrative. It has got its own meaning. He mentioned a few things which are resounding and he has used high sounding words in his speech. He has said about the share of economy. Yes, the UPA Government is fully committed to sharing with the poor. We have cross subsidisation. The money that is collected from the rich people is shared with the poor people. And there is harmony between the rich and the poor.

Coming to caring quality, there is a special word which is not found in any of the speeches of earlier Presidents. Caring quality was not used earlier in other speeches. Ideologically, the Congress and the Left Parties are different. But we are together today to form this Government and the Government is going on in full harmony. This type of a Government was never seen earlier. The Congress Party had formed Governments with 400 Lok Sabha Members. Today, we are reduced to 145 Members. Yet we share power with other political parties, we respect each other and very good development is seen in the President's Address.

Another point is about equity with growth. The speeches of the past Presidents also fully mentioned about equity. We are sharing whatever we have in the budget with the poor people, particularly the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women and everyone. Equity with growth is a special word which Rashtrapatiji has mentioned.

Finally, regarding social justice, it is there in the Preamble of the Constitution. This was fully debated in the Constituent Assembly and the party in power is fully committed for social justice.

Coming to the Common Minimum Programme, we are committed to it. I have a few points to mention. Particularly for education, we have allotted more than Rs. 18,000 crore and an amount of Rs. 18,000 crore has been allotted for health and Rs. 16,000 crore for fertilizers this year. For agriculture, Rs. 10,000 crore has been allotted. These amounts have been earmarked for these areas.

I would not like to quote everything from the budget but I will cull out a few points from it. The Congress Party has done something substantial about science. We all know that before and after Independence, people used to travel by bullock carts. Where are we now? We are travelling in aeroplanes, launching rockets and we see missiles and atom bombs everywhere. This is a positive development which the Congress Party has brought to this nation. Such a thing had not been done by any other political party in India. No political party can dare to say that, in the field of science, they have made this much development. Earlier, people used to die due to malaria and cholera but now, they are going in for heart transplantation. It is the Congress Party which has contributed more to the nation particularly in the field of science which no other political party can say that they have done. I will say that even BJP or other political parties cannot dare to say that they have contributed this much to the nation. The Congress Party has contributed so much to the nation in the field of science.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : You should praise our scientists and others concerned.

DR. CHINTA MOHAN : Of course, it is always there. Their contribution is always there and we all admire them.

Coming to education, earlier, there were no schools. Primary schools were missing in every village. Today, in about six lakh villages, primary schools and high schools are there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But does every school have four or five teachers? You are going into the details of six lakh villages. Does every school have teachers?

DR. CHINTA MOHAN : Today, so many colleges are there. Many universities were brought in now. The policy of education was brought by late Shrimati Indiraji in 1968.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Would you yield for a minute? … (*Interruptions*)

DR. CHINTA MOHAN : No, I am not yielding.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, through you, I would like to ask one thing.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not the Question Hour. Please listen to me.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not to be recorded.

*(Interruptions)**

* Not Recorded

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not Question Hour. Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Dr. Chinta Mohan.

*(Interruptions)**

DR. CHINTA MOHAN : Before the hon. Member joined politics, the Congress Party, particularly the late Indira Gandhi, brought an education policy in 1968. In 1968, the Congress Party gave an education policy. It was intended that fruits of development should go to all. Today, in the field of education, everybody is enjoying the fruits of development. In 1986, the late Rajiv Gandhi brought a policy on education. After that, in 1992, the Congress Party brought another revised education policy. Due to these policies, we have so many educational institutions, universities and colleges and there is no problem for education. Compared to what it was 57 years back, today, since the Congress Party was in power and also behaved responsibly in the Opposition, changes have been brought in education. Today, the literacy rate has gone up. These are the positive contributions of the Congress Partry.

I now come to the subject of health. Health is an issue about which everybody is bothered. Previously, in villages, when there used to be cholera or small pox, people used to die. Today, there is no such thing. Now, people are going for heart transplantation, liver transplantation, stem cell transplantation etc. So much of research is being done in AIIMS. This is the positive contribution of the Congress Party. There is a proposal to build AIIMS-like hospitals. People who belong to middle class are going below the poverty line. To bring them back above the poverty line and to help those who belong to middle class, the Congress Party and the UPA Government is committed to set up 13 AIIMS-like hospitals at the tertiary levels. It will be set up in States where there is a problem of health. This is a positive development. The money has also been allocated for setting up of these institutions. These would come up within next two or three years"""""""

Coming to railways, we all are aware that railways got their own history. They used to run on coal and fire. But today there is so much of advancement in railways. Sixty-three thousand kilometres length of railway lines are there; 11,000 trains are running everyday; and they are not having even one minute rest. Sir, 7,000 railway stations are there all over the country. There are about 15.5 lakh employees in Railways, who work with discipline and harmony. This is the achievement of the UPA Government and the Congress Party.

Let me now come to telephone. That used to be a big thing. Nobody used to know what is a telephone. I myself saw it when I was studying in Pre-University Course. Today, telephone is there everywhere. They are not ordinary telephones, but cell phones. Everybody has got two or three telephones. This is the achievement of the Congress Party and the UPA Government.

Coming to food, before Independence, we used to import food grains from Burma and other countries. During Indira Gandhi"""""""

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलते हुए बीस मिनट हो गए हैं। आपकी पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों को भी बोलना है। अगर आप अपनी पार्टी का पूरा समय लेना चाहते हैं तो कृपया आप अपनी पार्टी से पूछ लीजिए। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है।

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPAKER: I have no objection to that.

DR. CHINTA MOHAN : My Party is with me.

The Mid-Day Meals Scheme is a very important scheme where. Poor children in this country studying in the primary schools are getting mid-day meals. This Scheme has been brought by our Party.

Coming to unemployment, this is a very important thing. There are four crore educated unemployed people in this country. In 2001, Shri Yashwant Sinha was the Finance Minister. He brought the rule of Recruitment Optimisation. We have 40 lakh Central Government direct civil employees in this country. Every year, three per cent of them are retiring. That goes to show that 1,20,000 jobs are falling vacant. But now, they cut 80,000 jobs every year. I would request the hon. Prime Minister and the Chairman of the UPA to remove the words "Recruitment Optimisation." The Government should go in for providing massive employment and see that the poor people who are educated are given jobs.

Coming to the issue of equity, it has been mentioned in the President's Address. In the Common Minimum Programme, particularly for Health, Education and Rural Development, they have set apart Rs.18,000 crore, Rs.18,000 crore and Rs.10,000 crore respectively. In this, I would request the hon. Prime Minister and the Chairman of the UPA that money should be earmarked for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Of course, the Special Component Plan was there. In the same way, in the Common Minimum Programme, the money that is allotted is Rs.70,000 crore. This sum of Rs.70,000 crore equitable portion should be allotted exclusively for the uplift of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the poorer sections. That way, it will be helpful.

The last point which I will mention is a very important point. It is about Indo-Pakistan relationship.

Recently, I happened to go through the newspapers and found that the Left leaders Shri Harkishen Singh Surjeet and Shri A.B. Bardan had gone to Pakistan. They were there for more than nine days. Never has it happened after partition that Indian leaders had gone to Pakistan and addressed public meetings. They had been addressing public meetings. This is a positive achievement of the UPA Government. Many public meetings were addressed by Comrade Surjeet and Comrade Bardan. It was allowed by the Government of Pakistan. I was told, they travelled for sixteen hours a day. Comrade Bardan and Comrade Surjeet travelled sixteen hours a day from Lahore to Islamabad to address public meetings and people attended those meetings in large numbers, to hear them. This is a positive achievement of the UPA Government. This has never happened earlier in these 57 years.

There were also talks between General Musharraf and Comrade Harkishen Singh Surjeet over three rounds. Probably hon. Members sitting on the other side are not aware that three rounds of discussions took place and they were very cordial. General Musharraf had asked Comrade Surjeet what he wanted. This type of a thing has happened for the first time in 57 years of Independence. I would say that this is an achievement of the UPA Government. Earlier, we used to fight. When General Musharraf came to Agra, they fought with him, he saw the Taj Mahal and went back. Now, when Comrade Surjeet and Comrade Bardan went there, there was a rousing reception for them. There was a red carpet welcome for them. When Comrade Surjeet was asked what he wanted, he asked for the release of 200 prisoners from his State who were in the prisons of Punjab (Pakistan) and General Musharraf readily agreed to it. This is the achievement. This is the relationship between Pakistan and India today. Sitting in Congress benches, I congratulate the Left leaders. They have given a positive sign and they have brought about friendly relations between India and Pakistan.

With this, I conclude my speech by thanking the hon. President for giving us, in the Central Hall of Parliament, for one hour and fifteen minutes a beautiful Address. I thank the mover and the seconder of the Motion of Thanks and I also thank the Chair for giving me this opportunity.

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महामहिम राट्रपति जी ने एक लम्बा भााण हमारे सामने रखा, जिस पर धन्यवाद प्रस्ताप पारित करने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। हमारे राट्रपति जी, देश में जितने जाने-माने और सबसे ज्यादा जिनके प्रति हमारा आदर है, ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने देश के सामने पूरे देश का चेहरा बदलने के लिए एक एक्शन प्लान रखा था। मुझे उम्मीद थी कि शायद उनके अभिभााण में इसका प्रतिबिम्ब होगा, जिसके तहत हम 15 साल में देश को पूरी तरह से बदल कर एक विकसित राट्र बना पाएंगे। इस समय गरीबों की जो हालत है, वह ऐसी न रहे, पानी की समस्या हल हो, सड़कें बनें और पूरे देश को एक जगह से दूसरी जगह तक हम जोड़ पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उसका कोई चिंतन इसमें नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि राट्रपति जी नए साल की

शुरूआत में सभी सांसदों को सम्बोधित करते हुए ऐसा भााण देते हैं। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधान मंत्री जी देश को सम्बोधित करते हैं और वित्त मंत्री जी सदन के सामने बजट के माध्यम से अपने विचार रखते हैं। तीनों महानुभाव देश की अलग-अलग समस्याओं की चर्चा करते हैं और उनके भााणों से लगता है कि अब ये समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन जब तक बजट में उनके लिए प्रावधान न हो, तो उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि एक ही भााण ऐसा हो, जो हैड आफ दि स्टेट या हैड आफ दि गवर्नमेंट, राट्रपति जी या प्रधान मंत्री जी दें कि आने वाले दिनों में किस तरह से वे देश की समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं और उनको कैसे हल करेंगे। मैं समझता हूं कि यह सबसे जरूरी है।

इस अभिभााण में "मिलेनियम डैवलेपमेंट गोल" का जिक्र नहीं है, जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किये हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में रहते हैं। उनकी गरीबी को दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं, इस पर भी विचार करने की जरुरत है। अभिभााण पढ़ने से लगता है कि

" मिलेनियम डैवलेपमेंट गोल" अस्तित्व में नहीं है। उस पर भी चर्चा करने की जरुरत है। हमने इस बात को कहा है कि पानी की समस्या को हम इंटिग्रेटेड तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में जो आश्वासन दिये थे और जैसा माननीय चिंता मोहन जी कह रहे थे कि 90 प्रतिशत गांवों में पानी की समस्या नहीं है। यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं अगर वे भी कहते हैं कि 90 प्रतिशत गांवों में पानी की समस्या नहीं है तो ठीक है और अगर इसी तरह से मानकर हम आगे समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो वह भी ठीक है। लेकिन हमारे सामने आज सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी, वह पानी की समस्या होगी। खेती में पानी के लिए किसान परेशान हैं, शहरों में पीने के पानी के लिए लोग परेशान हैं, स्त्रियां परेशान हैं। अगर हम पानी की समस्या को आने वाले समय में हल कर पाएंगे तो यह एक बहुत बड़ी समस्या को हल करना होगा।

भारत सरकार में आठ ऐसे मंत्रालय हैं जिनका सीधा संबंध पानी से है और उन्हें पानी की समस्या पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर हम पानी की समस्या को इंटिग्रेटिड तरीके से हल करना चाहते हैं तो हमें एक ही मंत्रालय इसके लिए बनाना होगा, जो पूरी तरह से पानी की समस्या पर ध्यान दे सके।

अभिभााण में हमने कहा है कि बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण देश के कई भागों में बहुत नुकसान हो रहा है। राजीव गांधी रिसर्च फाउंडेशन ने बताया है कि हमारे देश में ऐसे जिले सबसे ज्यादा पिछड़े हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं। इसलिए यह समस्या भी पानी से जुड़ी समस्या है। एक तरफ पानी की कमी है तो दूसरी तरफ बाढ़ की विभीाका है। हमें पानी की क्वालिटी से संबंधित एक कानून बनाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पानी की क्वालिटी क्या हो?

जब हमने इस साल का आर्थिक सर्वे सदन में रखा तो देखा कि देश की जीडीपी में खेती का जो हिस्सा है उसमें साढ़े तीन प्रतिशत की गिरावट आई है। किसानों की आमदनी कितनी कम हुई है, यह इसी बात से पता लगाया जा सकता है और हमें इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरुरत है। खेती और पानी का एक दूसरे से सीधा संबंध है, इसलिए पानी और खेती की समस्या पर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है।

अभिभााण में दो-तीन चीजों का उल्लेख नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वाइल्ड-लाइफ के खतरे पर चिंता प्रकट की है। इसमें इस बात पर कोई चर्चा नहीं है। हमारे देश में टाइगर्स की संख्या करीब साढ़े तीन हजार के लगभग थी, लेकिन आज उनकी संख्या का हमें अंदाजा नहीं है। इसलिए पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ पर बहुत ध्यान देने की जरुरत है। इकोनोमिस्ट मैग्जीन ने चीन और भारत की तुलना करते हुए एक सर्वे किया है। पहले तुलना एलीफेंट्स से की जाती थी लेकिन आज टाइगर्स से की जाती है कि कितने टाइगर्स इंडिया में हैं। आज देश के सामने उनके संरक्षण की बात है तो उनके संरक्षण के लिए देश में अभियान चलाया जाना चाहिए। आज से 26 साल पहले प्रोजैक्ट टाइगर्स बना था लेकिन उस पर दुबारा से ध्यान देने की जरुरत है। हैल्थ, एजुकेशन पर हमने ज्यादा से ज्यादा आउट-ले किया है।

चिदम्बरम जी टेलीविजन के किसी चैनल में कह रहे थे कि आउट ले से आउट कम इम्पौर्टैंट है। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं। उसकी अभी जरूरत नहीं है लेकिन आउट कम लाने के लिए मेजर्स उठाने की जरूरत है। जो भी धन यहां से जाता है, लोगों तक पहुंचता है, इसमें जो अन्तर है, उसे दूर करने के लिए जब तक ब्यूरोक्रेसी के डिलिवरी मैकेनिज्म में रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वह अन्तर कभी कम नहीं होगा। सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर निकालना चाहिए। आगे आने वाले तीन साल. चार साल, तीन महीने, छः महीने में पूरी ब्यूरोक्रेसी को रीइनवैंट करने के लिए क्या करेगें इस पर सोचने की जरूरत है। जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो उसे पर्सपैक्टिव में रखना चाहते हैं। आबादी की तुलना में ब्यूरोक्रेसी का परसैंटेज बहुत कम है। किसी भी कंट्री या एशियन कंट्री से कम्पेयर करेंगे तो बहुत कम पाएंगे लेकिन उसमें क्या परिवर्तन करने की जरूरत है? आज ब्यूरोक्रेसी में बैंच के हिसाब से प्रमोशन होते हैं। 1966 और 1974 बैच को प्रमोशन मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बैच में जिस ने अच्छा काम किया, उसे प्रमोशन नहीं मिलता। काम को प्रमोशन नहीं मिलता। उसने देश को कितनी सर्विस दी, उसे देखते हुए प्रमोशन दिया जाता है। इसमें एक प्रावधान करके परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसी से जुड़ी बात मैं कहना चाहूंगा। साईंस ऐंड टैक्नॉलोजी सैक्टर के बारे में कहते हैं कि भारत का भविय बहुत उज्जवल है। हमने पिछले सालों में शिक्षा के क्षेत्र में जो इनवैस्टमैंट की थी उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि साईंस ऐंड टैक्नॉलोजी में हमने प्रगति की है। गवर्नमैंट के साईंस ऐंड टैक्नॉलोजी के जो डिपार्टमैंट हैं उसमें नए लोगों और वैज्ञानिकों के आने के लिए कोई प्रावधान नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था, 15-20 साल पहले उनको तकनीकी ज्ञान देने का अलग तरीका था। उस समय उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में सीखा, उसे देख कर उन्हें आज प्रमोशन मिल रहा है। यह देश के लिए बहुत खतरे की बात है। राट्रपति जी विश्व के जाने-माने वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट होने के नाते उन्होंने जो अभिभााण किया और जिस पर यह बहस चल रही है, मैं इस बात को मानता हूं कि साईंस ऐंड टैक्नॉलोजी में इनवैस्टमैंट करने की जो बात हो रही है और जो लोग इनमें काम कर रहे हैं, उसमें बढ़ोत्तरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने की आवश्यकता है और उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

हमारी बढ़ती आबादी के बारे में कोई चिन्ता नहीं की गई है। क्या हम अभी यह सोच कर चल रहे हैं कि जिस तरह देश की आबादी बढ़ रही है, वह देश के लिए बहुत अच्छी बात है। यदि 4 प्रतिशत विश्व का पानी हमारे देश में है और उसके ऊपर निर्भर करने वाली विश्व की 17 प्रतिशत आबादी हमारे देश में है तो पानी की समस्या होगी ही इसलिए जब हम पानी की समस्या को हल करना चाहेंगे तो उसके साथ बढ़ती आबादी का सिलसिला जुड़ा ह इसलिए मैं मानता हूं कि क्या हमारे देश में किसी बात की प्रॉयरिटी है या नहीं? यदि है तो इसके बारे में अभिभााण में चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।

इनसैंटिव और डिसइनसैंटिव को आगे बढ़ाने की चर्चा देश में काफी सालों से चल रही थी। हम इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए किस तरह का प्लान होगा इसके बारे में कुछ चर्चा करने की जरूरत है।

किसानों की खराब हालत से पूरे देश के लोग परेशान हैं। इस बारे में सदन में भी बार-बार चिन्ता व्यक्त की गई। इसमें साढ़े तीन प्रतिशत की गिरावट आई है। हम लोन की संख्या बढ़ा कर किसानों की समस्या हल करेंगे, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम इस तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का इस बारे में जो प्लान है या जो आउट ले है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने अखबारों में एक्शन प्लान की बात पढ़ी थी। उसमें भी परिवर्तन करके बजट में प्रावधान किया जाए। वित्त मंत्री जो बजट पेश करते हैं उसमें आउट ले होता है। जब प्रधान मंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से घोाणा करते हैं और राट्रपति जी अपना अभिभााण देते हैं तो तो उनके सामने बजट के प्रॉवीजन नहीं होते हैं। तीनों को इंटीग्रेट करके इस समस्या को हल करेंगे तो लाभ होगा।

राट्रपति जी के अभिभााण के तुरन्त बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें अलग-अलग बातों पर चिन्ता व्यक्त की गई है। बिजनेस के लिए जो एंट्री और एग्जिट रूल है जब तक हम उसमें बदलाव नहीं लाते तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। जब तक वह एक्सपैंड नहीं हो पाएगा तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा।

देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाथ का काम मिले । मेरा मानना है कि इस प्रकार की चिंता को एड्रैस करना चाहिए ताकि किसी तरह से मैनुफैक्चरिंग बढ़े । एंट्री एक्जिट रूल के लिए चर्चा की गई है लेकिन इसका कोई जिक्र पॉलिसी में नहीं आया है । मैं चाहता हूं इसे एड्रैस करने की जरूरत है । फुटवियर, सॉफ्ट टॉएज़, इलैक्ट्रॉनिक गुड्स और टैक्सटाइल, इनमें सबसे ज्यादा एम्पलाएमेंट पोटेंशियल है । सरकार ने स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने की बात कही है । पूरे देश में एक-एक इकनॉमिक जोन, एक-एक प्रोडक्ट को बनाना चाहिए ताकि एक-एक इकनॉमिक जोन में लाखों लोगों को जॉब मिल सके । जिस तरह से चीन में लो वैल्यू एडेड मैनुफैक्चरिंग में तरक्की की है उसी तरह से हमें करना चाहिए ताकि उसमें वैल्यू एडीशन सिर्फ लेबर का हो ताकि एम्पलाइज बढें । इसके ऊपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । यदि अभिभााण सही मायने में हमें लाना है तो सरकार की तरफ से हर चीज के ऊपर एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है । अगर एक्शन प्लान को असलियत में अमल में लाने पर ही हम यह परिवर्तन कर पाएंगे । एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चिंता है । हमारे जैसे गरीब देश में जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे है । यह हमारे लिए क्रूड जोक है कि 53 या 54 बैरल के दाम से हम खरीदेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी । उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है । हम विदेश में एक्प्लोरेशन लिए जा, यह ठीक बात है, इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है । हमारे रिन्युअल एनर्जी के कम्पोनेंट में कम से कम 10 का इन्क्रीमेंट प्रतिशत होगा । सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी को एड्रैस करना चाहिए । आगे आने वाले दिनों में 25 प्रतिशत ज्यादा रिन्युअल एनर्जी बनेगा, उसमें रिन्युअल एनर्जी का परसेंटेज 25 प्रतिशत से ज्यादा होगा । इसे सबसे पहले करने की आवश्यकता है । रिन्युअल एनर्जी की बढ़ोत्तरी करनी है ताकि दाम भी कम हो । इसके लिए हमें आर एंड डी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है । हाइड्रो सिस्टम की भी जरूरत है । दिन में सोलर सिस्टम है तो रात में विंड सिस्टम चलना चाहिए । दोनों सिस्टम साथ में चलाने के लिए हाइड्रो सिस्टम बनाने की जरूरत है । हमें इसमें काफी इन्वेस्ट करना होगा।

आने वाले दिनों में न्यूकलीअर एनर्जी में भी बहुत ज्यादा तरक्की करनी होगी । हमने सन् 2020 तक सिर्फ 20,000 मेगावाट न्यूक्लिअर एनर्जी तैयार करने का उद्देश्य रखा है । हम अपने देश में एनर्जी सिक्योरिटी को एड्रैस करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं । एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एनर्जी मिक्स किस तरह से हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए । अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम एनर्जी सिक्योरिटी को सही मायने में ध्यान में रख सकेंगे और उसमें परिवर्तन कर सकेंगे ।

*SARDAR SUKHDEV SINGH DHINDSA (SANGRUR) : Honourable Deputy Speaker Sir, I thank you for the opportunity given to me to speak on the Motion of Thanks on the President's address to Parliament. First of all, I would like to talk about a positive aspect of the address. I would like to associate myself with Honourable member who talked about improvement in India's relations with her neighbours. Sir, India's relations with her neighbours have never been good. So much so that although we played a major part in the creation of Bangladesh and shed our blood for that cause, still we do not have friendly relations even with Bangladesh. And it further spoiled our relations with Pakistan. So, any improvement in our relations with Pakistan is a step in the right direction. My Party, the Shiromani Akali Dal has always been in favour of friendly relations between India and Pakistan. First of all, this matter was initiated by Shri I.K. Gujral. Later on, Shri Atal Bihari Vajpayee continued with this process and he started the 'Bus-Diplomacy' to Lahore. I congratulate the Prime Minister Sardar Manmohan Singh that his Government has tried to further improve our relations with Pakistan. It should be commended. Today, we can see that the love and affection of people of Indian Punjab and Pakistani Punjab for each other is increasing and sports like Cricket, Hockey, Kabaddi and cultural exchanges are playing a major role in it. It will exert further pressure on the Governments of

* Translation of the speech originally delivered in Punjabi

both the countries to further improve relations between both the countries. Secondly, Sir, I want to highlight the saga of injustice that was meted out to Punjab. Prime Minister Manmohan Singh is present here today. Deputy Speaker Sir, Punjabis, especially Sikhs have played a pivotal role during the pre-independence era in the struggle for gaining independence for India. It is a record in itself. I would like to quote some figures. In the struggle for gaining independence, 121 people were hanged. Out of them, 93 were Sikhs. 2646 people got life-imprisonment. Out of them, 2147 were Sikhs. In the Jallianwallah Bagh massacre, 1300 people were shot dead. Out of them, 799 were Sikhs. During the Kuka agitation, 91 people were martyred. All 91 of them were Sikhs. During the Akali movement for getting freed the Gurudwaras, 500 people attained martyrdom. All 500 of them were Sikhs. And in 1925, Mahatma Gandhi had congratulated the then Akali Chief Baba Kharak Singh when the Gurudwara Act was passed that you have won India's first war. But, unfortunately, injustice was meted out to Punjab ever since independence. Punjab and Andhra had to fight for their rights to get a language-based state. Only after a lot of struggle could we get the Punjabi-Speaking State. But, another injustice was meted out to Punjab.

Many Punjabi Speaking areas remained outside Punjab. Chandigarh, which rightly belonged to Punjab, was not given to Punjab. Unfortunately, Punjab is the only State whose capital is a Union Territory.

Another point that has been emphasised in the President's address is water. It has been called a national resource. As far as the river-water of Punjab is concerned, Haryana and Rajasthan are not riparian States and hence, they have no right over the river-water of Punjab. But, in 1955, an agreement was signed. At that time, the World Bank was breathing down our neck. I want to quote this instance. Shri Kanwar Sen, was the architect of this agreement. I want to quote a Statement given by him in 1982:-

> "Shri Kanwar Sen, former Chairman of the Central Water and Power Commission, feels that the Akali demand for the reopening of the river water issue is fully justified as the State was not given its due share. Mr. Sen was the architect of the 1955 Agreement reached between Punjab and Rajasthan on the utilisation of surplus waters of Ravi and Beas rivers. He had drafted the Agreement. Mr. Sen was consulted by the Union Minister of State for Irrigation, Mr. R.N. Murad, on Wednesday on this issue. He told ENS that though he had a soft corner towards Rajasthan and Haryana, he felt that the Akalis demand was justified. He said that the entire issue should now be referred to the Inter-State River Water Tribunal for their view. Even the 1955Agreement should be reopened, he said. Mr. Sen said, the 1955 Agreement was done in a hurry because of certain pressures. A World Bank team was to come for inspection of the areas. The Project of the Rajasthan Canal was also prepared in a hurry to overcome certain issues, Mr. Sen said in the 1955 Agreement. He had given a note stating that the realities about the assessment of the requirement may be different. This was done because decisions had to be taken before the arrival of the World Bank team, therefore, this Agreement should be reopened."

So, this statement was given by a person who had drafted this agreement.

Mr. Deputy Speaker Sir, I want to give two more instances. When Madras was divided between Andhra Pradesh and Tamil Nadu, then the water of rivers Krishna, Godavari and Cauveri was not divided between these two States. The riparian principle was followed when Bombay was divided between Gujrat and Maharashtra, then also, the water of rivers Narmada, Mahi, Tapti and Sabarmati was not divided. So, only Punjab suffered injustice in the matter of river water.

An honourable member talked about the condition of the farmers. Sir, what is happening to the farmers of Punjab? Prior to 1966,foodgrains were imported from Australia and U.S.A. Then the Punjabi farmers rose to the occasion and ushered in the Green Revolution. Sir, Punjab comprises of just 1.5% land of India but we provide more than 50% food grains in the Central pool. Earlier, we were begging for food-grains from foreign countries. Later on, our granaries were over-flowing with food-grains. Instead of providing facilities to Punjabi farmers, even his share of river water was snatched away from him. So, honourable Prime Minister Sir, kindly put an end to the injustice that has been meted out to Punjab.

Honourable Shri Ram Gopalji has rightly pointed out that after the assassination of Shrimati Indira Gandhi, thousands of Sikhs were killed in riots but none was punished for this crime. For three days continuously, this massacre of Sikhs continued. Army was called in but it was not given orders to control mob-violence. Police officials were asked not to lodge any F.I.R. Sir, over 4000 innocent Sikhs were butchered in Delhi alone. These were not riots. These were beastly and barbaric killings and nobody was punished. How can the Sikhs think about justice in such circumstances? The earlier Government did nothing. Later on, the NDA Government constituted the Nanavati Commission to give justice to Sikhs. Sir, the report of the Commission probing the Gujrat riots was published and made public the day it was submitted. I do not oppose it. But the Nanavati Commission report has not seen the light of the day. Why? I demand that this report be made public, so that justice is done to the Sikhs. Prime Minister Manmohan Singh is a Sikh. So, we hope that he will put an end to this injustice and provide justice to Sikhs.

Sir, how much time is left for me?

16.00 hrs.

MR.DEPUTY-SPEAKER : Please wind up. Please conclude within two-three minutes.

SARDAR SUKHDEV SINGH DHINDSA : Sir, recently, elections were held in Punjab. The State Government indulged in booth-capturing, and rigging with the help of its muscle-men. When Sardar Parkash Singh Badal, accompanied by his MLAs, wanted to meet the Honourable Governor to lodge a complaint, the Punjab Government ordered the police to resort

to water-cannons and lathi-charge. These responsible people were insulted. Their turbans fell down. Such was the state of affair. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Ranaji, take your seat. Please conclude.

SARDAR SUKHDEV SINGH DHINDSA : Sir, another point I want to raise is regarding the young men of Punjab. They want to migrate to foreign countries for employment. The miserable condition of Punjab is before all of us. Economy is in shambles. Sir, hundreds of our young men are rotting in the jails of Pakistan. They should be released. The Government should talk to Pakistan. Some time ago, the Chief Minister of Pakistani Punjab was here. He had said in my presence that the Pakistan Government is ready to run a bus from Nankana Sahib to Amritsar. Our Government should talk to Pakistan on this issue. If a bus can ply to Muzaffarabad, it should run for Nankana Sahib also.

Sir, another important matter is the issue of ban on wearing of turbans imposed on Sikhs in France. A law has been passed in France forbidding Sikh students from wearing turbans. Sir, turbans are an integral part of Sikh religion. We have brought this issue to the notice of our Prime Minister also. We should raise this matter with the French Government.

Sir, in 1984, when Blue-Star Operation took place, the sentiments of Sikhs were hurt. A lot of young men gave inflammatory speeches. They were incited by others. Many of them were blacklisted. They were residing in foreign countries. We want that this list should be reviewed. Many young men were not even Khalistanis. Those who are innocent should be dropped from this list.

I want to make another request. We want that the Rs.8500 crore burden on Punjab that was waived off by Shri I.K.Gujral in principle, should be implemented. The Centre is responsible for implementing this. Centre should bear this entire cost, not Punjab. … (*Interruptions*)

SHRI GURJEET SINGH RANA (JALANDHAR) : I agree to what he has stated just now only regarding waiver of Rs.8500 crore.

उपाध्यक्ष महोदय : ढींडसा जी की स्पीच के अलावा और कुछ रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

(Interruptions) *

* Not Recorded

SARDAR SUKHDEV SINGH DHINDSA : We welcome all steps taken in this direction. Mr. Deputy Speaker, Sir, it is our good fortune that the Prime Minister is present here today. Injustice that was done to Punjab should be removed. Justice should be done to Punjab. Our demands should be met. This is my humble request.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, अभी मुझे बिजनेस एडवाजरी कमेटी की बैठक में जाना है । चेयरमैन के पैनल का कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं श्री किन्जरपु येरननायडु से अनुरोध करता हूं कि वे सदन की कार्यवाही को संचालित करें ।

1608 hrs. (Shri Kinjarapu Yerrannaidu *in the Chair*)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Thank you, Mr. Chairman. After losing some valuable time, we are now resuming our discussion on the Motion of Thanks on the President"""""""

Taking the plea of Godhra incident, they started massacre in Gujarat under the leadership of the Chief Minister of Gujarat. I would not call it a situation of riot. I would say that they resorted to genocide in Gujarat. As per the Report of Justice Banerji, what happened in Godhra is a clear and transparent incident.

Our hon. Rashtrapatiji has mentioned in his speech that his Government is determined to extend a good relationship with the neighbouring countries like Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and other countries. He has also expressed

that the UPA Government will continue the foreign policy of peaceful co-existence in the world started by the earlier Government headed by Pandit Jawaharlal Nehru. Just now, my distinguished colleague Dr. Chinta Mohan mentioned during the course of his speech about the two great leaders, that is, the CPI General Secretary Shri A.B. Bardhan and the CPM General Secretary Comrade Harkishan Singh Surjeet. They had visited Pakistan and met the President Pervez Musharraf, the External Affairs Minister and other Pakistani leaders. They had a very good deliberation and fruitful discussion with them. As a result of that, a large number of Indian prisoners were released. We welcome this type of peaceful mission with the neighbouring countries.

After the Independence, when the Government was formed under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, we, the Communist Party of India, had certain differences with the Congress Government. We had fought in the streets against the misdeeds and misrule of the then Congress rule. But we wholeheartedly supported the foreign policy of the then Government, the policy that was initiated by Pandit Jawaharlal Nehru. He was the leader of the world peace movement along with President Sukharno and President Nasser. We salute Pandit Nehru because he was the leader of peace movement of the world. We are proud of his policy as a nation and as a citizen of India. It is not only that. When the British and the French imperialism attacked Egypt taking the plea of Suez Canal, our Indian Government took the bold stand against this attack when the Americans attacked Vietnam. They tried to destroy the mankind of Vietnam. The Indian Government took the bold stand and protested against the barbarism of the American imperialism. But, I am sorry to say that during the regime of the NDA Government headed by Shri Atalji, when the Iraq was attacked by American imperialism headed by President Bush, our Government did not raise any protest against this barbarism, against this attack. I am sorry to say that our Prime Minister always bowed down and was always ready to appease the American imperialism. He always bowed down before President Bush. Mr. Chairman, Sir, you can recollect from your memory that we failed to adopt any resolution unanimously condemning the American attack on Iraq. This was the role played by the NDA Government headed by the BJP and its leader Shri Atal Bihari Vajpayee.

Sir, we are supporting this Government. We are not part and parcel of this Government. We, the Communist Party of India and other Left parties are supporting this Government on the basis of some Common Minimum Programme. This UPA Government will implement and execute the Common Minimum Programme. If they fail to implement the Common Minimum Programme or shift from the Common Minimum Programme, certainly, we shall protest both within the House and outside the House.

In his Address, hon. Rashtrapati-ji has mentioned so many aspects of our country, from Rural India to the cities, from the farmers to the workers. He has mentioned different aspects of lives in our country. But I am sorry to say that some matters have still been left out in his Address. For example, he did not mention a single word about the agricultural workers, who are the most downtrodden people of the country. Thirty-seven per cent of the total population of the country is the agriculture workers. But they do not have their own land, they are working on others' land, and, they are not getting their remunerative wages. They are not getting jobs throughout the year. They are very much deprived even after 50 years of our Independence.

Mr. Chairman, Sir, we observe our Independence very gloriously but I am sorry to say that we have failed to bring any comprehensive legislation for the welfare of the agricultural workers, for the downtrodden people of our country. Not only that, there is not a slightest mention about the workers in the unorganised sector, about the persons who are working as bidi workers, who are working as construction workers and who are working as rickshaw pullers. In his Address, the workers of the unorganised sectors have been totally neglected.

Sir, there is one more thing which has been totally left in the Address of the hon. Rashtrapati-ji. It is about the 33 per cent reservation for women, that is Women Reservation Bill. Insofar as I recollect my memory, I have gone through 60-page long Address of the hon. Rashtrapati-ji, and there is not a slightest mention about the Women Reservation Bill. Yesterday, we all observed the Internatioal Women's Day. We, the Left parties, even the Congress party, even the BJP, and even, Mr. Chairman, Sir, your party have expressed giving the unconditional support to the passing of the Women Reservation Bill giving 33 per cent reservation to women. But I am very sorry to say that, we have not been able to pass this Bill up till now. I am really very sorry that there is no mention about the Women Reservation Bill in the Address of the hon. Rashtrapati-ji.

Now, I come to another very important point, which has not been covered in the Address of the hon. Rashtrapati-ji. It is the jute industry. The jute industry is one of the age-old and the biggest industries of our country. It is not only the West Bengal, but there are many States, namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Tripura, Orissa, which are the major jute growing States of our country. But I am sorry to say that the jute growers of our country are not getting any remunerative prices.

Sir, there are a large number of jute industries in West Bengal at both the banks of the Ganges near Kolkata where thousands of workers are coming for employment from various parts of the country including Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Tripura and Andhra Pradesh. But all these jute industries are closed now, and due to their closure, thousands and thousands of workers have been thrown out of their jobs. They are living under a blue sky. Even some of them have committed suicides due to frustration and due to hunger. They cannot provide food to their children and their inmates. But I am sorry to say that nothing about the jute industries has been mentioned in the Address of the hon. Rashtrapati-ji.

Mr. Chairman, Sir, I am happy that the hon. Prime Minister is also present in the House. As we have told earlier, we are supporting this UPA Government on the basis of the National Common Minimum Programme. But if this Government invites the FDI, we are strongly opposed to this move. Our viewpoint may differ with some others viewpoints, I do not know. But we oppose it.

Sir, our telecom sector, our banking sector and our oil sector are the pride of our nation. BSNL is the largest telecom sector of India. It has the largest network in comparison to other telecom sectors of the country. It is earning huge profits also. Similarly, our public sector banks and the oil sectors are also earning huge profits. We are all proud of all these sectors and they are the pride of our nation. But in spite of all this, this UPA Government, I am sorry to say, is violating and defying the National Common Minimum Programme. They are trying to invite the FDI in these sectors. About the FDI, we the Left parties – and I hope many other like-minded parties -- will oppose this move on the floor and outside the floor of the House.

The working class of this country, the employees of this country in different sectors have decided to launch movements against this anti-people policy. In spite of my very many reservations, I convey my gratitude to the hon. Rashtrapatiji, and with reservations, I support the Motion of Thanks on the President's Address.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Respected Sir, it is for the first time perhaps in Indian parliamentary democracy that we are discussing the Motion of Thanks on the President's Address, after the General Budget has been read out to us in this House. Seldom this has happened earlier.

What led to the exigency is not left to anybody's imagination. A mini referendum has been conducted after the UPA Government has come to occupy the seat of power here at the Centre, and that reflects the situation that is at hand. However, I am reminded about the centuries old colourful evolution of the Westminster, where the Joint Session of two Houses of Parliament is a defining parliamentary event and it has been enshrined in Article 87 of the Constitution of India. Through this Article 87, the President of India addresses both the Houses of Parliament assembled together and informs the Parliament of the causes of the summons.

More importantly, Article 87 (2) provides that the Parliament shall discuss the matters referred to in the President's Address and it entitles us to discuss what is referred to in the Address by the President. The Joint Session of two Houses of Parliament is conventionally the only occasion when the President is in the Parliament and the President's Address is a substantive document, a blueprint of the plan and programmes of the UPA Government. But I am disappointed and I am sad. I will give you my reasons.

First is the tsunami tragedy which struck us like a thunderbolt. Tragic losses of human lives and destruction of property have left a scar. Despite advancement of science, flow of information was so slow that thousands of people perished in the mainland hours after it had struck the islands of Andaman and Nicobar and the coastal areas of South East Asian countries.

There is no mention about the human error that occurred in deciphering the little information that trickled in, nor was there any attempt to understand the impact of the earthquake which was followed by tsunami, which occurred nearly four hours after the quake. There is a mention to convert this tragedy into an opportunity and to modernise the maritime economy and to protect the coastal ecology. But how? There is no direction to that purpose. Rather, it seems to me, it is just a wishful thinking. A Central legislation on disaster management is mooted, and an Authority is to be formed through that legislation. Creating another Authority, to my mind, will not serve the purpose. Rather empowering the State apparatus and better coordination at the Union level would be more helpful.

If the Meteorological Department, Science and Technology plus Ocean Development Ministry could not coordinate among themselves, how would one authority serve that purpose? Does the Government intend to bring a Disaster Management Authority which would directly deal with the affected people overriding the States? If it can only function with the cooperation of the State apparatus, then what is the meaning of a Central Authority? My apprehension is, there is a tendency to encroach upon the basic aspects of the State and thereby weaken the federal structure of the country. Different States, no doubt, ask for help, support from the Centre when calamity strikes. But this should not become an excuse to trample upon the right of the States that are enshrined by our forefathers in the Constitution.

I would like to raise another point and this refers to the fiscal position of my State and also to other States which are weak financially. In Para eight of hon. President"""""""

At the same time, I would like to mention here how others view us. India is emerging as a centre of knowledge and international magazine of repute like, New Scientists are publishing cover stories on India's advances in science and technology. There has been a dramatic change in the way India is perceived. One still comes across reports which states immunization kills infants because due to lack of fire-wood or electricity, sterlisation of needles were not done.

Yet India's achievements have changed the Westerner's concept about us. It was decades ago that Indian scientists and medical doctors exposed the West to our skills in universities, hospitals and key institutions, ranging from NASA to the National Institute of Health.

When India exploded the nuclear bomb for the second time, we attracted serious attention. When five years ago, the then ISRO Chairman, Dr. K. Kasturirangan talked about India's moon mission, some in the West saw it as an ill-advised foray by an uppity developing country that cannot provide clean drinking water to its people.

But should we forget that the UK developed the bomb when Britons were queing up for breads and eggs and America took up even more expensive scientific projects when the high infant mortality in Harlem could have been brought down with one-millionth of that money? But one is amused not to find a single reference to India's moon mission in the President's speech. Has *Chandrayan* been abandoned or is it intentionally not mentioned? When there is a marked attitudinal change in the Western media, what is happening to the Government? Does the Government intend to build *Bharat* by this type of selected insomnia?

Madam, Chairman, I would conclude in two to three minutes time. Orissa has been neglected for last many decades. The BJD Government in the State is striving hard with the whole-hearted support from others to improve the situation. Our contention is that we have all the criteria to get a special category status. The basic idea of Five Year Plan and yearly budgetary allocation is to provide adequate support to the weak States in order to enable them to come forward and be developed. But what special steps have been taken for States like Orissa where people living below the poverty line is 47 per cent as compared to the nation-wide average of 26 per cent? I do not feel elated to mention these figures, rather I am ashamed and so also, I believe, all the other Members who are sitting on the other side. The rate at which poverty has been decreasing is also one of the slowest across the Indian States. The per capita income in real terms is roughly half the national average. The incidence of chronic poverty is also pathetic. Close to 40 per cent of poor come under the `very poor category' – below three-fourths of the poverty line – while close to 50 per cent of the `non-poor' have incomes that place them marginally above the poverty line. I do not find any reference in his Address about how to tackle this problem.

Madam, Chairman, I would like to draw the attention of the House, through you, about spending of Government money. I say this with full responsibility. The KBK region has been a recipient of aid from bilateral agencies for development work and so also the North-Eastern States and the State of Jammu and Kashmir. A lot of money has been provided and is being provided but this has little impact on poverty rates. Is it not necessary to identify wasteful expenditures in a sound and analytical way before spending this money? But there does not seem to be any urgency in this. Nobel prize winning Economist Ed Prescott recently said that good Government policies come from experience and experience comes from poor policy.

When will this Government recognize their policy? Unless they do that, they can never get experience and, without experience, we cannot have good policies.

With these words, I conclude my speech.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है, उसमें संशोधनों के लिए मेरी ओर से मोशन क्रमांक 160 से 189 तक दिए गए हैं। महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण में अनेक बातों का उल्लेख हुआ है और सामान्यतः इसमें केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का वर्णन किया जाता है। जनगणना के ताजा आंकड़ों का विभिन्न दृटिकोण से मनन करने से एक गंभीर चिन्ता का विाय उभर कर सामने आता है।

आज देश के सामने जनसंख्या नियन्त्रण सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस अभिभााण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि सरकार की ओर से जनसंख्या नियत्रण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस बात को देश के बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लोग मानते हैं कि हम कितने भी विकास के कार्यक्रम, आवास और रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं क्यों न बनाएं, उनकी सफलता के लिए जनसंख्या पर नियन्त्रण किया जाना आवश्यक है। अनेक माननीय सदस्य अपने निजी विधेयक लाते हैं, मेरा भी सोचना है कि जनसंख्या पर नियन्त्रण करने के लिए उपाय होने चाहिए, लेकिन मुझे सरकार की ओर से इस दिशा में कोई प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एक विाय आया है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते मेरा भी मानना है कि जनसंख्या नियन्त्रण के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ा 2004 के चुनावों के दौरान अपने घोाणा पत्र और दृटिकोण पत्र में इसका उल्लेख किया था।

हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को निर्मित किए जाने का उल्लेख किया है। वह देश के हित में है और इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भिन्न-भिन्न समय पर निर्देश दिए हैं। सरला मुद्गल के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। जब तक देश में समान नागरिक संहिता नहीं होगी, विशेाकर उत्तराधिकार और विवाह के विाय में यूनिफॉर्म विधान नहीं होंगे, देश में जनसंख्या नियन्त्रण को पूरी तरह से सफल बना पाना संभव नहीं होगा। जब हम चाइना मॉडल की बात करते हैं और एक परिवार-एक बच्चा का आदर्श अपनाने की बात करते हैं तो बिना एक समान नागरिक संहिता के यह कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पत्नियाँ हों चार और बच्चा हो एक या दो। चूंकि यह देश का सर्वोच्च सदन है, यही वह उपयुक्त स्थान है जहाँ पर इस विाय पर चर्चा की जा सकती है और मुझे आशा है कि यूपीए सरकार इस दिशा में कुछ गंभीर कदम उठाएगी। इस दिशा में कोई ठोस कार्यक्रम और नीतियाँ तभी सामने आ सकती हैं जब इस पर गंभीर राजनीतिक चिन्तन हो। आपने जितने कार्यक्रमों का उल्लेख किया है, उनमें से कुछ भी नया नहीं है।

सभापति महोदया : आपस में चर्चा मत कीजिए। आपसी चर्चा रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी।

*(Interruptions) **

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :सरकार की जितनी भी योजनाएं आज कार्यान्वित की जा रही हैं, उनमें से कोई भी नई योजना नहीं है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना हो सकती है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो सकती है, नार्थ-साउथ-ईस्ट-वैस्ट कॉरीडोर योजना हो सकती है या किसानों और गरीबों के लिए एनडीए की सरकार ने सोचा था कि ग्रामों का उत्थान होना चाहिए, गांवों का विद्युतीकरण होना चाहिए और वहां पर सड़कों के लिए ग्राम सड़क योजना भी शुरू की थी, इन सब योजनाओं को अगर आपकी सरकार ने आगे बढ़ाया होता, तो देश में विकास होता हुआ दिखाई देता। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह दिखाई नहीं दे रहा है।

अभी एक गम्भीर मामला हम लोगों के ध्यान में आया है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म दिन पर कुछ राज्य सरकारों ने विज्ञापन प्रकाशित किए और सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्य सरकारों को नोटिस दिया है कि वे बताएं कि राजकीय कोा का पैसा कैसे इसमें लगाया गया है। इस पर सुनवाई हो रही है और अगली तारीख पड़ी है।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होने की बात कही गई है कि हम इसको नियंत्रण में ले आए हैं। लेकिन मार्केट में जो फुटकर के भाव हैं, उनमें हमें कोई कमी नहीं दिखाई देती। आम जरूरत की चीजें दोगुने भाव पर मिल रही हैं। चीनी के दाम दोगुने हो गए हैं। मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है। किसान के लिए गुड़ एक

*Not Recorded.

अहम उपभोग की चीज है, उसके दाम भी काफी बढ़ गए हैं। इस सरकार के नौ महीने के शासन में चीजों के दाम दोगुने हो गए हैं और फिर यह कहना कि हमने भावों पर नियंत्रण किया है, समझ में नहीं आता है।

अंत्योदय स्वास्थ्य योजना और अंत्योदय अन्न योजना एनडीए की सरकार ने शुरू की थी। लगता है इन योजनाओं के नाम बदलकर पुराने कार्यक्रमों को चलाने का प्रयास मौजूदा सरकार द्वारा हो रहा है।

मैंने संशोधन दिया है कि जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेा राज्य का दर्जा दिया गया है। नार्थ-ईस्ट के विकास के लिए भी अलग से एक परिाद बनी हुई है। देश के बजट का दस प्रतिशत हिस्सा वहां खर्च हो रहा है। केवल दो राज्य बचते हैं उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश, जिनको मध्य हिमालय का क्षेत्र कहा गया है। लेकिन उनके लिए कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है और न ही उन्हें विशेा आर्थिक पैकेज दिया गया है। मेरी मांग है कि इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए और वहां के विकास के लिए अलग से कार्यक्रम बनाना चाहिए।

बायो फ्यूल के बारे में भी इस अभिभााण में उल्लेख किया गया है। लेकिन उस दिशा में कार्यक्रम क्या होगा, यह पता नहीं है। एनडीए सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 1430 करोड़ रुपए की योजना आयोग से संस्तुति की थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने उस सारे कार्यक्रम को ठप कर दिया है। मेरी मांग है कि देश के लिए वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में काम किए जाने की आवश्यकता है।

राट्रीय बागवानी विाय का भी उल्लेख हुआ है। लेकिन इसके लिए कोई नीति तय नहीं की गई है। नेशनल हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन पहले से है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। नदियों को जोड़ने का एक कार्यक्रम एनडीए सरकार ने चालू किया था। देश में सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, पर्यटन के लिए, बाढ़ और सूखे से राहत के लिए यह कार्यक्रम हमारी सरकार ने शुरू किया था। उसे भी रोक दिया गया है। मैं समझता हूं आने वाले समय में उस ओर होने वाली प्रगति में रुकावट डालने का काम मौजूदा सरकार द्वारा किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन उसके लिए धनराशि जो पहले निर्धारित हुई थी, उसमें बढ़ोत्तरी करने के बजाय कटौती की जा रही है। सन् 2007 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य जो पिछली सरकार ने निर्धारित किया था, उसे दो साल बढ़ाकर 2009 तक लाया जा रहा है। लगता है कि उसके लिए धन के आबंटन में ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनीज देश के अंदर रिजर्व बैंक की गारंटी से कार्यरत हैं। उनमें लोगों द्वारा विशेाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा अपना धन जमा किया जाता है। बाद में ये कम्पनीज भी चिट फंड कम्पनीज की तरह लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर गायब हो जाती हैं। उस दिशा में भी सरकार द्वारा जिन लोगों का

पैसा डूब गया है, उन लोगों राहत देने का कोई काम नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए कि भारत सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती।

मेरी मांग है कि इस दिशा में विचार होना चाहिए और छोटी बचत करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

साम्प्रदायिकता और सेक्युलरिज्म की बात की गयी है। सेकूलर स्टेट का जो संशोधन आया है, यह आपातकाल की देन है और साम्यवादी विचारधारा के लोगों के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में इसे जोड़ा गया है। लेकिन क्या पहले यह देश सेकूलर नहीं था या सेक्युलरिज्म केवल सरकार के निर्माण के बाद हुआ। हम लोग जो सांस्कृतिक राट्रवाद की बात पर विश्वास करते हैं और जहां हिंदुत्व का विाय आता है तो मेरा कहना यह है कि जैसे ही हम संसद के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो सामने लिखा है कि

" अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम,

उदार चरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्"

हम तो "सर्वे भवन्तु सुखिनः" पर विश्वास रखते हैं। हमारा देश पांच हजार साल पुराना है। आपके कहने से हम कम्युनल नहीं हो जाते हैं, विाय यह नहीं है। हमारा जो हिंदुत्व का विचार है वह तो अपने आप में सेक्युलरिज्म ही है। लेकिन आप अपने हिसाब से चर्चा करके, खरीदः-फरोख्त करने का काम करते हैं, तुटिकरण का काम करते हैं, समुदाय विशेा को खुश करके, उसका वोट हासिल करने का काम करते हैं। कांग्रेस की नीति फूट डालो और राज करो की नीति है। लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी सदन की है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : रावत जी, उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। please address the Chair. Do not listen to all these things.

… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: There should be no cross-talk in the House.

… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Bachi Singh Rawat 'Bachda'.

(Interruptions) *

***Not Recorded.**

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है कि झारखण्ड में नॉमिनेटिड एंग्लो-इंडियन वोट नहीं कर सकता। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है क्योंकि लोकतंत्र की हत्या होने जा रही थी, इसलिए न्यायपालिका ने संरक्षण दिया है।...(व्यवधान) एक उद्योग-पैकेज एनडीए की सरकार ने उत्तरांचल और हिमाचल राज्य को दिया था। दाता के तीन रूप होते हैं। देता है या नहीं देता है या छीन लेता है। यूपीए की सरकार ने दिया तो कुछ नहीं लेकिन जो 10 साल का पैकेज एन.डी.ए. सरकार ने दिया था उसमें से 6 साल का छीन लिया। उत्तरांचल और हिमाचल के साथ यह बहुत अन्याय किया गया है। हमने पुनः बल देते हुए, संशोधन में इस बात की मांग की है कि आप अपनी नीति को सुधारें। यह संवेदनशील क्षेत्र है और नेपाल से लगा हुआ है, माओवादियों की गतिविधियां वहां चल रही हैं और ऐसे में वहां के उद्योग-पैकेज को काट देना अन्याय का कार्य है। दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें है। एनडीए की सरकार पूरे देश का विचार करती है लेकिन आपने अपने स्वार्थ के कारण यह पैकेज काटा है। वहां की जनता की मांग है कि उसे पुनः बहाल किया जाए।

अंत में मैंने जैसे उल्लेख किया है कि हमारा सांस्कृतिक राट्रवाद का एक मोटो है और एकात्मवाद हमारा राजनैतिक चिंतन है। उल्टे-पुल्टे एलाइंस का न कोई चिंतन है, न दर्शन है, न नीति है और न दिशा है। इनके लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और इस बात पर यह विचार करें कि " इदं न ममः, राट्राय स्वाहा" और यह राट्र के लिए कार्य करें। पूरे देश में संचार की व्यवस्था ठीक हो। जो कार्य एनडीए ने शुरु किये थे, उन्हें आगे बढ़ाने में आप सफल हों - यही निवेदन करते हुए धन्यवाद और जो संशोधन मैंने दिये हैं, उन पर मैं बल देता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रजीडैंट एड्रैस की ताईद करता हूं और इसकी ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। देश में आज जो हालात हैं और सुनामी की वजह से जो हालात पैदा हुए, तबाही और बरबादी हुई, उसके लिए पूरे देश और देश वासियों ने पॉलिटिशियन्स ने बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के मदद की। मैं इसके लिए उन लोगों को मुबारकवाद देता हूं जिन्होंने यह सारा कार्य किया। हम इस त्रासदी को भूले भी नहीं थे कि रियासत जम्मू कश्मीर में एबनॉर्मल स्थिति आई, स्नो फॉल हुआ, बारिश हुई। मैं अभी की बात बताना चाहता हूं। वहां आज भी बारिश हो रही है। आप अभी पता करके देखें। जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में और डोडा में अब भी बर्फ गिर रही है। वहां हालात बहुत खराब हुए। बड़ी तबाही और बरबादी हुई। मैं आर्मी पर्सनल, पैरा मिलिट्री फोर्सिज, एअर फोर्स और सिविल गवर्नमैंट का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल कर बड़ी मेहनत और लगन से काम किया और हमारे कुछ लोगों की जान बचायी। उन्होंने कइयों को कनैक्टिविटी देकर घरों में पहुंचाया। यह अंडर दी प्राइम लीडरशिप ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी के हुआ। वह यूपीए गवर्नमैंट की चेयर पर्सन हैं। उनकी चेयरमैनशिप के अन्तर्गत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, अरबन डैवलपमैंट मिनिस्टर साहब ने काम किया। हमारी रियासत के सारे लीडर्स वहां पहुंचे और वहां के हालात देखे। उन्होंने वहां के लोगों को राहत दी। हमारी रियासत के लोग आज भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देश में कभी खराबी आई, चाहे हमारी कांग्रेस की सरकार थी

या नहीं, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि चाहे चट्टीसिंहपुरा का हादसा हो, चाहे पठानकोट का हादसा हो, चाहे गूजरों, सिखों और हिन्दुओं पर हमला हो, हमारी जम्मू-कश्मीर रियासत में जब भी हालात खराब हुए, जान-माल का खतरा या तबाही हुई तो मैडम सोनिया गांधी और उनकी टीम ने हमारा दामन थामा और हमें आशीर्वाद दिया। अगर आज मैं इस जगह उनका शुक्रिया अदा न करूं तो यह भी बेइंसाफी होगी। इसलिए मैं मैडम जी का, मनमोहन सिंह जी का जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी सारी टीम का शुक्रिया करना चाहता हूं।

हमारे पास डिजास्टर मैनेजमैंट है। हिन्दुस्तान में जब कोई प्राबलम खड़ी होती है चाहे वह नेचुरल हो या अननैचुरल हो, उस समय हम सोचते हैं कि क्या करें? डिजास्टर मैनेजमैंट कमेटी हमारे यहां होनी भी चाहिए ताकि कभी हालात खराब हों तो उसका मुकाबला कर सके। वह आर्मी की भी होनी चाहिए, पुलिस की भी होनी चाहिए, सिविल की भी होनी चाहिए। ऐसे तीन-चार कोर ग्रुप बनाने चाहिए जिससे यह सिलसिला ठीक हो सके।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र हिन्दुस्तान में लार्जैस्ट निर्वाचन क्षेत्र है। डोडा 12 हजार स्केवअर किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट है। बाकी बात छोड़ें। दो और जिले हैं। मैं उसी की अकेले बात करना चाहता हूं। आज तक जो भी पैसा आया, वह लोगों तक नहीं पहुंचा। हमारे यहां चार किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट भी है और 12 हजार किलोमीटर का भी डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो फंड आते हैं वे हमारे यहां नहीं आते हैं। हमारे यहां डोडा डिस्ट्रिक्ट में दो-तीन डिस्ट्रिक्ट इस बार बढ़ा देने चाहिए ताकि उसके साथ इंसाफ हो। जम्मू में जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट बनते हैं उनको इसमें इनक्लूड किया जाए। हमारा एक साथी जो कह रहा था मुझे वह सुन कर अफसोस हुआ। वह कह रहे थे जम्मू-कश्मीर को पैकेज मिला है। पैकेज मिलने से वह दुखी हो गए। हमारे 70 हजार वीर नौजवान मृत्यु के शिकार हुए। आप जानते हैं कि बड़ी तबाही और बरबादी हुई। कुछ देशभक्त चले गए और कुछ देशद्रोही चले गए। अगर देशद्रोही चले गए तो हमें कोई गम नहीं।

17.00 hrs.

देशभक्ति को बचाना हमारा फर्ज है । मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से उसे लिया है इसे भी लेना चाहिए। यह अजीब बात लगती है कि अभी भी तीन जेनेरेशन्स में वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं । वे जम्मू-कश्मीर में बैठे हैं, वहां आज भी रिफ्यूजिओं को असेम्बली में वोट डालने का अधिकार नहीं है । आज भी उनको जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है । उनको नौकरी का अधिकार भी नहीं है । राट्रपति के अभिभाण में आदिवासियों को, जो जंगल में रहते हैं, जिनकी जेनरेशन वहां पैदा होती है, उनको एडजस्ट करने का सवाल है । आज जम्मू-कश्मीर के वेस्ट पाकिस्तान को एडजस्ट करने का सवाल है, इसे भी इसमें इन्क्लूड किया जाए । पीओके के पाक आक्यूपाई मुजफराबाद को आपने खोला है, इसके लिए धन्यवाद देता हूं । जब देश की अखंडता और देशभक्ति की बात आती है तो इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए । यह चैक किया जाना चाहिए कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है क्योंकि हमें पूरे देश को संभाल कर चलना है । हमारी मांग है कि जो 20 किलोमीटर का सेफ डिस्टेंस है, मुजफराबाद 500 किलोमीटर है और स्यालकोट से आर एस पुरा 20 किलोमीटर है, इसे जल्दी ही इसमें इन्कलूड करके खोला जाना चाहिए ।

हमारी रिक्वेस्ट है कि कश्मीरी पंडित, जो लाखों की तादाद में यहां आए हैं, उनका आज तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया है । आज कश्मीरी पंडितों को कश्मीरियत खत्म हो रही है । वह एक पढ़ीलिखी कम्यूनिटी थी और कश्मीर की शान थी, उनको निकालने से वहां डेमोक्रेटिक फील्ड खत्म कर दिया गया है। आज हम कम्यूनल और सैकुलर की बात कह रहे हैं । जिस आदमी का जन्म जहां होता है वह वैसा ही बनता है । जो आरएसएस में पैदा होगा क्या वह हमें सैकुलर की बात बताएगा, वह कभी भी सैकुलर नहीं हो सकता ।...(व्यवधान) इसलिए आपको यह कहना शोभा नहीं देता है । कांग्रेस का कल्चर हिंदुस्तानी है, सैकुलर है ।

अभी मेरे एक साथी ने हिंदुत्व की बात कही । आप जानते हैं कि हिंदुत्व कब आया ? ऊँ सर्वे ऋग्वेद - क्या यह हिंदुत्व गीता में नहीं है, ऋग्वेद में नहीं है । वे आर्यन थे, सनातनी थे । पहले आप इसे समझिए । आप समझते हैं कि आप बड़े सनातनी हैं, आप अपने धर्म की कद्र करते हैं । कांग्रेस हर धर्म की कद्र करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भी कद्र करती है । आप कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी हाऊस नहीं चलने देते हो । आप अनडेमोक्रेटिक हो । मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस देश के बहुत कुर्बानियां दी गई हैं । किसानों के लिए शास्त्री जी ने नारा दिया था " जय जवान, जय किसान" । उन्होंने किसानों के लिए विदेश से राशन मंगवाया, उन्होंने देशवासियो को मैसेज दिया और साथ ही सब्सिडाइज्ड बीज, पेस्टीसाइड्स, खाद, फर्टीलाइजर्स सब कुछ दिया ।

आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार , इन्दिरा गाधी की सरकार, राजीव जी की सरकार - इन सब ने किसानों को फायदा दिया था। किसानों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, उन्होंने जमीन पर काम किया और कुरबानी की और वे देश के लिये हरित क्रान्ति लेकर आये। लेकिन जब इन लोगों की सरकार आई, ये लाले लोग थे, सरमायेदार थे, व्यापारी लोग थे, किसान नहीं थे। इसलिये इनके आने पर किसानों की खुदकुशी शुरु हुई। स्व. इन्दिरा जी के जमाने में एक किसान ने खुदकुशी नहीं की। जो हुई, इनके जमाने में हुई। इन्होंने देखा कि अन्न के भंडार भरे हुये हैं, जहां किसानों को शाबाशी मिलती, लैटर ऑफ एप्रिसिएशन मिलता, वहां उन्हें मौत दी, ज़हर दिया और फांसी दी। यह उसी का नतीजा है कि इनको पाप लगा और ये उधर बैठे हैं। यह उन लोगों का कुसूर है, हमारा नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये लोग मैडम सोनिया गांधी की बात करते हैं। ...* क्या एक लाख 21 हजार में कफन बनता है, केवल तीन फट्टे हैं। इस मामले की इक्वायरी होनी चाहिये...(व्यवधान) आप क्या बात करते हैं, जरा पेशंस रखिये...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स रिकॉर्ड में नहीं रहेंगे।

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : लाल सिंह जी, अगर आपकी हिम्मत है तो श्री जॉर्ज फर्नान्डीज जी ने जो भाण में चैलेंज किया है, उसकी इंक्वायरी करा कर देखो कि उसमें क्या है? सभापति जी, माननीय सदस्य अनपार्लियांटरी वर्ड्स बोल रहे हैं, वे रिकार्ड में से निकाल दें।

*** Not Recorded**

सभापति महोदया : मैंने पहले ही ये शब्द निकालने के लिये कह दिया है। लाल सिंह जी, आप चेयर को अड्रेस करिये और थोड़े शब्दों में मर्यादा से बोलें।

चौधरी लाल सिंह : सभापति जी, मैं आपकी ओर देखकर ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदया : लेकिन ज़रा ठीक शब्दों का उपयोग कीजिये।

चौधरी लाल सिंह : सभापति जी, मैं कोई बुरा शब्द नहीं कह रहा हूं जो अनपार्लियामेंटरी होगा। मेरे पास एक किताब है जिसमें अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स लिखे हुये हैं और मैंने उन्हें देखा है। इसलिये आप चिन्ता न करें। मैं जो कुछ बोलूंगा, अपनी लिमिटेशन में बोलूंगा। मैं कह रहा था कि हमारी सरकार में किसानों के लिये समझदारी है। अभी ' मिड डे मील' की बात कही गई। मैं भी इस स्कीम में इंटरैस्टेड नहीं हूं। मैं जम्मू की बात बता रहा हूं। मैं दो टीचर्स की बात बताता हूं। एक दाल लाने के लिये भेज दिया, दूसरा चावल लेने के लिये चला गया, क्या इससे स्कूल चलेगा। वह मैस बन जायेगी। जो आदमी अपने बच्चे स्कूल नही भेज सकता, वह दो रोटी कैसे खा सकता है? वह कैसी मदद कर रहे हैं? मेरी सरकार है जिसे मैं कहूंगा कि ऐसा मत करें। इस देश में मजबूत बच्चे पैदा करो, सड़क पर भिखमंगा बनने के लिये बच्चे मत पैदा करो। मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि कहीं ऐसा न करें और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा न करें। हम बहुत ही खुद्दार लोग हैं।

सभापति जी, मैंने देखा है कि प्लान बनता है। मैंने बजट में देखा है कि लम्बी-चौड़ी बातें कही गई हैं। हर वर्ा स्टेट्स को लाखों नहीं, करोड़ों-अरबों रुपया जाता है लेकिन उस रुपये पर कोई चैक है या नहीं कि कहां जाता है? करप्शन कैसे रोकी जाये? मेरी रिक्वैस्ट है कि जब देश में करप्शन रुकेगी, बड़े पैमाने पर कैपिटलिज्म रोकी जायेगी। यह क्या बात हुई कि कभी कहा जाये कि हिन्दू बन जाओ, कभी कहा जाये कि मुसलमान बन जाओ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अब आप समापन की तरफ आइये।

चौधरी लाल सिंह : आप वन ऑफ दि पार्लियामेंटरियन बन जाओ। हिन्दू बनकर आओ, देशभक्त बनकर आओ। मेहरबानी करके मेरी इन बातों पर ध्यान दिया जाये।

अंत में दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। हमारे यहां विडो पेंशन स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है और हैन्डीकैप्ड के लिए भी स्कीम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें बहुत बढ़ाने की जरूरत है। हमारी स्टेट में बर्फबारी के कारण बेहुत सारे मकान डैमेज हो गये हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 15 हजार मकान तो सरकार ने लिखे हैं, जबकि अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है। कठुआ और ऊधमपुर में ही कम से कम बीस हजार मकान ढह गये हैं। मेरा निवेदन है कि आई.ए.वाई. में एक पैकेज बनाकर उस एरिया को दिया जाए, ताकि वह एरिया बच सके। हमारे यहां हॉर्टीकल्चर पूरी तरह से खत्म हो गई है और क्रॉप भी पूरी तरह से खत्म हो गई हैा इल पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे राज्य में हाइडल प्रोजैक्ट्स काफी पैन्डिंग पड़ी हैं। पानी के लिए हमारी पाकिस्तान के साथ ट्रीटी हुई थी, हम कुछ नहीं कर सकते, उसे वापस लिये जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा उस तरफ भी ध्यान दिया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया ।

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Madam, I rise to support the Motion. At the outset, I would mention a sentence from para 28 of the speech of the hon. President. He said :

"My Government wants India to shine, but it must shine for all. "

This indicates the vision of this Government. I and my party support this Government to implement the national Common Minimum Programme. This national Common Minimum Programme is the agenda for the governance of this Government. In the National Common Minimum Programme, it is declared that the main thrust is not to disinvest the public sector of our country. The soul of our democracy and the existence of our country is secularism. That is our soul.

People of our country are very much vigilant. They are so vigilant that they have not allowed the communal forces to come back to power. That is their main task and the people are very much vigilant on that area. At the same time, the spirit and the contents of the national Common Minimum Programme should be highlighted. It is said that my party is blindly opposing the FDI, but we have certain opinion on that area. We are not blindly opposing it. We say that if FDI is coming and is needed for the development of infrastructure of our country, it should be creating new job opportunities, and it should be for the new ventures and not to purchase our existing public sector. If it is purchasing the existing public sector, then it is only the change of ownership. It is not creating any new job opportunities and it will not be a new venture. So, I want to make this also clear.

Madam Chairperson, if we go into the details of the policy declared by the hon. President for the Government, the main thrust is on the rural empowerment of our country.

I would like to mention another very important point, namely, with regard to the unemployment situation in our country. Everybody is aware about the problem of unemployment nowadays being faced in our country.

I would like to draw the attention of this august House, and the hon. Members on a news item, which was published in a few national news dailies 10 or 15 days back. In my opinion it was a pathetic news item. In Maharashtra, a Police Commissioner in Thane office invited applications for the recruitment of Police Constables. Thousands of applications were received for the same. Hundreds of applicants were Engineering Graduates, and more than 22 applicants were MBBS

Graduates for the post of Police Constables. This news item appeared 15 days back in a few important news dailies of our country. … (*Interruptions*)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : यह तो यूपीए का कमाल है। …(व्यवधान)

SHRI N.N. KRISHNADAS : No, it was done during the time of NDA Government. In the last 6 years you have spoiled this country.

MADAM CHAIRMAN : Please, no cross talking in the House. Please address the Chair.

SHRI N.N. KRISHNADAS : Madam, I am addressing the Chair only.

MADAM CHAIRMAN : It is a good practice.

SHRI N.N. KRISHNADAS : This news item indicates the pathetic situation of unemployment in our country. The main thrust of the Government in our country should be to look at the serious issue of unemployment in our country.

We welcome the Employment Guarantee Scheme in our country, but our demand is that it should not be limited to 150 selected districts only. It should be extended to all the rural areas in our country.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : It was a promise in the manifesto.

SHRI N.N. KRISHNADAS : Yes, it is. Thank you for reminding me about it.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : It is in our manifesto.

SHRI N.N. KRISHNADAS : Now, it has been decided to implement the Employment Guarantee Scheme in 150 selected and identified districts only. I come from Kerala, and, unfortunately, not even a single district from Kerala has been included in this list of 150 districts. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI DAYANIDHI MARAN): The people there are not poor, and are employed. … (*Interruptions*)

SHRI N.N. KRISHNADAS : Thank you for the compliments, but the feeling in Kerala is that it has been neglected as a result of this measure. Madam, through you, I would like to demand from the Government that, at least, three backward districts of Kerala, namely, Palakkad, Wayanad, and Idukki should be included in the Employment Guarantee Scheme.

The Government also gave sufficient thrust to the issue of water conservation. Madam, I will only take another 10 minutes or so.

MADAM CHAIRMAN : No, I cannot give you 10 minutes, but only 2 minutes. I think, another hon. Member of your party has already taken more than 45 minutes.

SHRI N.N. KRISHNADAS : Okay, Madam. Water conservation is another very important issue. Madam, I would like to mention that there is a serious lack of laws to prevent ground water exploitation in our country.

Therefore, a powerful law should be there to check and protect our groundwater resources from exploitation.

As I mentioned earlier, I come from Kerala. In my State, today, the Assembly is in Session, and the Opposition is on a hunger strike.

DR. CHINTA MOHAN : You should not mention about Assembly here.

SHRI N.N. KRISHNADAS : I am referring to a very serious situation.

MADAM CHAIRMAN : You should mention only the points and conclude your speech in two minutes.

SHRI N.N. KRISHNADAS : The demand is about procurement of paddy. The farmers who are harvesting paddy -- wheat is not produced in our State and paddy is the main food grain in our State -- are not getting any profits because nobody is there

to procure paddy from them. Therefore, I strongly demand the Central Government, through the Chair, to see that FCI takes care of the procurement in the State of Kerala, as is the case all over the country.

One more thing that I would like to mention is… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: I think, you have finished your points. Please conclude now.

SHRI N.N. KRISHNADAS : I shall obey your direction and conclude my speech now.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, मुझे आपने राट्रपति के अभिभााण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । अभी तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विद्वान सदस्यों ने अपनी-अपनी बाते रखी हैं । राट्रपति जी के अभिभााण में मैंने पाया कि तमाम बिंदु ऐसे थे जिन पर चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे गरीबों की समस्या हो या अनुसूचित जाति या जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों की समस्या हो, उन सभी बिंदुओं पर प्र ाकाश डाला गया है । कुछ बातें ऐसे रहती हैं जो सामान्य भााण में या अन्य जगहों पर दर्शायी जाती हैं । सही मायनों में महामहिम राट्रपति महोदय के अभिभााण में सुनामी त्रास्दी पर बड़े विस्तार से जिक्र है और उसके लिए हम लोगों ने दोनों सदनों में शोक व्यक्त किया है । लेकिन आज मैं इस अभिभााण में, जो हमारी सेना से, विदेश से, राज्यों की सरकारों से या केंद्रीय सरकार से तथा तमाम समाजसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने मदद की है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद अदा करते हैं । लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि तमाम लोग जो गरीब थे, जो रोज़ कमाने वाले लोग थे, उनका बहुत नुकसान हुआ है । उनका जीवन और आजीविका दोनों एक तरीके से नट हो गई है । उनका बिलकुल नामोनिशान मिट गया है । हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, वे नहीं मिली हैं । खास कर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि रोजी, रोटी और मकान उन्हें मुहैया कराए । हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पीड़ितों समस्याओं के समाधान के लिए एमपी लैड के बजट से पैसा देने का प्रावधान किया है । सांसदों ने ज्यादा-से-ज्यादा अपना सहयोग प्रदान किया है । पीड़ितों को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए ।

दूसरी बात, मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और खास कर अल्पसंख्यकों के लिए जो कहा गया है उनके कल्याण और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान की बात कही गई है ।

सभापति महोदया, आज भी हम देखते हैं कि खासकर उनके कल्याण के लिए केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक तमाम आयोग बने हैं, लेकिन उन्हें सं वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। तमाम ऐसे पद हैं, जिनकी रिक्तियां सदैव बनी रहती हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पर उन्हें भरा नहीं जाता। पदोन्नति के लिए भी लोगों को संर्घा करना पड़ता है।

महोदया, अभी हाल ही में, पिछले हफ्ते मैंने अखबारों में पढ़ा कि राट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक, डॉ. शीतल प्रसाद, जो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अनुसूचित जाति से हैं, उन्हें जबर्दस्ती उनसे चार्ज लेकर उनका चार्ज किसी जूनियर को दे दिया गया। वे बड़े विद्वान हैं। उनकी काफी सेवा बाकी है, लेकिन अनुसूचित जाति के होने के कारण उन्हें अपने पद से अवमुक्त कर दिया गया। आज हम लोग इस संबंध में माननीय श्री एस. जयपाल रेड्डी जी से मिले और कहा कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। अब स्थिति यह है कि वे यदि आयोग में जाते हैं, तो चूंकि आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए चाहे पदोन्नति की बात हो या आरक्षण की बात हो, आयोग के निर्देश का पालन नहीं किया जाएगा। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि यदि आरक्षित पदों को भरने हेतु विभागों के प्रमुख या अध्यक्ष जिम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

महोदया, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले बजट सत्र में इस विाय पर चर्चा हुई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्रीमती मीरा कुमार जी के मंत्रालय पर चर्चा के समय इस विाय पर विस्तार से चर्चा की गई थी। सरकार की भी मंशा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ेवर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक आरक्षण की सुविधा मुहैया करानी चाहिए, फिर इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है, यह बात मेरी समझ से परे है। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
महोदया, राट्रपति अभिभााण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हो रही बहस में महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा बहुत जोर-शोर से उठा है। महोदया, आप आज सभापति की पीठ पर आसीन हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग महिलाओं के आरक्षण का विरोध नहीं बल्कि समर्थन करते हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल में संशोधन की हम मांग करते हैं क्योंकि देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं, उन्हें भी आरक्षण देना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि महिला आरक्षण विधेयक को यहां पारित कीजिए। उसे पास कराने की प्रक्रिया में हमारा दल पूरा सहयोग करेगा । महोदया, आज देश के किसानों की हालत बहुत खराब है। उन्हें अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। खासकर मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से इलाहबाद और पूर्वान्चल जिलों की बात कहना चाहता हूं। उस संपूर्ण क्षेत्र में बहुत अच्छी खेती होती है। किसान दिन-रात मेहनत करता है, जिसके कारण वहां बहुत बड़े पैमाने पर आलू का उत्पादन होता है। इलाहाबाद क्षेत्र में बहुत ज्यादा अमरूद पैदा होता है, लेकिन उन्हें रखने के लिए कोल्डस्टोरेज में जगह भी नहीं मिलती है। फलों के अनुसंधान हेतु कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। यदि वहां रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाए, तो उस क्षेत्र में पैदा होने वाले फलों को विदेश भेजने अथवा देश में जहां जरूरत है, वहां भेजने की व्यवस्था हो सकती है।

आज हम बाजार में देखे हैं कि अंकल चिप्स के नाम से जो पैकेट बिक रहे हैं वे 20 या 25 रुपए से कम में नहीं मिलते हैं, लेकिन आलू पैदा करने वाले किसान को कुछ नहीं मिलता है। सारा पैसा बिचौलिए या बड़े-बड़े उद्योगपति, जो इस प्रकार की फैक्ट्रियां लगाते हैं, वे ही खा जाते हैं। किसान को मेहनत से उपजाए अपने उत्पाद का लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। इस विाय पर सदन में बैठे लोगों को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। भारतर्वा कृाि प्रधान देश है। अगर यहां का किसान खुशहाल होगा, तो पूरे देश का विकास होगा।

महोदया, मैं अपनी सीट से नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपनी सीट पर कुछ पाइंट्स लिखकर रखे थे, लेकिन चूंकि समय कम है, इसलिए जो महत्वपूर्ण पाइंट थे, उन्हें और अपने जिले की बात मैंने आपके माध्यम से सदन में कही है। राट्रपाट्टेति महोदय के अभिभााण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की ओर विशेा ध्यान आकर्ति करते हुए कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की हालत बहुत बदतर है। वहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि केन्द्र सरकार की ओर से उसे पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। इसलिए मैं माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में वे विशेा रूप से विचार करें। उत्तर प्रदेश का दुखदर्द वे समझते हैं क्योंकि वे कानपुर से आते हैं। कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां तमाम इंडस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विशेा पैकेज केन्द्र सरकार की ओर से दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश विकास कर सके। यदि उत्तर प्रदेश का विकास होगा, तो पूरा देश विकास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राट्रपति महोदय के अभिभााण पर सदन में प्रस्तुत वि गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

LT. COL. (RETD.) MANABENDRA SHAH (TEHRI GARHWAL): Madam Chairperson, the need for National Disaster Management Authority is a very welcome proposal made by the President in his Address. But it is little disappointing to me because he has confined himself to the coastal areas and Jammu and Kashmir. Uttaranchal is an area which has been receiving repeated damages annually, not only in one aspect but also in many aspects. We face heavy rains; we face avalanches; we face landslides; we face floods; and we face umpteen types of disasters. It is true that we are very well aware of the damages and the human lives are saved to a great extent but nevertheless, disaster is there also. Therefore, I am little disappointed that the Address is confined to coastal areas and Jammu and Kashmir and has ignored the damages that have been taking place in the mid-Himalayan region. Mid-Himalayan region is a very important part in India"""""""

सकारात्मक रूप से सरकार का विरोध करते हैं और कोई सुझाव देते हैं तो निश्चित रूप से सरकारें और देश उससे लाभान्वित हुआ करते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि एक नई परम्परा बनी है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना। यह जो विरोधी दल का और विरोधी पार्टियों का नकारात्मक स्वरूप है, उसे सुनने के बाद यह महसूस होता है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, यह लोकतंत्र की अच्छी परम्परा नहीं कही जा सकती।

इस सरकार के गठन के बाद जो एक त्रासदी हिन्दुस्तान के अन्दर हुई, हिन्दुस्तान में सम्भवतः किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह का समुद्री तूफान भी आ सकता है, जिससे मिनटों में एक हजार से ज्यादा लोग तबाह हो सकते हैं, वे मर सकते हैं। हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं और पूरे हिन्दुस्तान के लोगों ने सरकार को बधाई दी कि सरकार ने सिर्फ इसका मैनेजमेंट ही नहीं किया, बल्कि जो लाखों लोग गरीब थे और जिनकी रोजी-रोटी का सहारा मछली पकड़ना और मछली बेचना था,

उनके लिए सरकार ने तेजी से प्रयास किए। योजनाओं व ऋणों के द्वारा उनकी आर्थिक सहायता की जिससे हफ्ते-दस दिन के अंदर वे फिर से रोज़गार करने लायक हो सके। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय क़दम है। सरकार ने सिर्फ अपने कर्तव्य की पूर्णता इसी में नहीं समझी कि जिस समय यह घटना घटी और उस घटना में जितनी दिक्कतें आईं, उसका हम प्रबन्धन कर लें, बल्कि सरकार ने उससे दो क़दम आगे बढ़कर आपदा प्रबन्धन का गठन किया और उस पर तमाम शोध कराए कि यदि इस तरह का कोई तुफान आने की आशंका हो तो हमें पहले से कैसे उसकी जानकारी प्राप्त हो और उस जानकारी के बाद उसका प्रबन्धन किस तरह से किया जा सकता है। सरकार की यह जो पहल है, जो प्रयास है, यह निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन कट होता है कि उधर की बैन्चों से इस पर भी प्रश्न किए जा रहे थे कि ऐसे प्रबन्धन हुए, ऐसे प्रबन्धन नहीं हुए। हम समझते हैं कि इस सदन के अंदर इस विाय पर तो बहस हो सकती है कि प्रबन्धन हुए या नहीं। लेकिन सम्भवतः हिन्दुस्तान के हजारों-करोड़ों लोग सरकार के इस प्रबन्धन पर उंगली नहीं उठाएंगे। जनता के बीच में जो संदेश गया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है।

राट्रपति जी के अभिभााण में यूपीए का जो कॉमन मिनीमम प्रोग्राम है, उसको किस तरह वर्तमान सरकार कार्यान्वित करेगी, उस एजेन्डे को कैसे फुलफिल करेगी और उसमें सरकार ने कौन-कौन सी पहल की है, उसकी रूपरेखा और भावना बनाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, कम है। इस सरकार ने साझी अर्थव्यवस्था के प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाई है। कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तीन महीने के अंदर जिस तरह से यूपीए की सरकार ने अपने कायक्रमों में अपने प्रयास किए, वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।

महोदया, धार्मिक और भााायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए इस सरकार ने कहा कि हम एक आयोग का गठन करेंगे। सम्भवतः इसके पहले किसी भी सरकार के द्वारा इस तरह की पहल नहीं की गई थी। हिन्दुस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, उसमें जो पिछड़े और अतिपिछड़े हैं उनके लिए कौन से सुधार और प्रयास किए जाएं जिससे आने वाले दिनों में उनके अंदर भी खुशहाली पैदा हो। इस सरकार ने उसके लिए प्रयास किए हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार ने एक सकारात्मक सोच रखी है कि किस तरह से अल्पसंख्यकों में जो पिछड़े लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सकता है।

महोदया, यह सरकार जब से आई है, तब से हमारे विदेश व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। उसका यह नतीजा हुआ है कि हमारा देश सिर्फ कलैन्डर में ही इक्कीसवीं सदी में नहीं खड़ा है, बल्कि हकीकत में इक्कीसवीं सदी में खड़ा है। मैं जॉर्ज साहब को सुन रहा था। वे बहुत ही वरिठ सदस्य हैं, लेकिन उनको सुनने के बाद यह महसूस हो रहा था कि जिस समाजवाद की ओर हम लोग बढ़े हैं, शायद उस समाजवाद की जॉर्ज साहब ने पिछले दस सालों में कोई परिभाा लिखी है।

हम लोगों ने आचार्य नरेन्द्र देव को पढ़ा है, श्री राम मनोहर लोहिया को पढ़ा है लेकिन जिस समाजवाद की बात जार्ज साहब आज की तारीख में कर रहे हैं, शायद उनकी समाजवाद की जो किताबें हैं, उन किताबों में इसकी परिभाा दिखाई नहीं पड़ती। श्री जार्ज साहब चर्चा कर रहे थे कि कोई व्यक्ति एनडीए छोड़ता है तो वह सेक्युलर हो जाता है और यदि कोई व्यक्ति एनडीए में चला आता है तो वह साम्प्रदायिक हो जाता है। श्री जार्ज साहब ने आज बोलते समय यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में भी कहा था। उन्होंने कहा कि वे असत्य बोल रही हैं। यदि हम नये लोग किसी असंसदीय भाा का इस्तेमाल करें तो बात समझ में आ सकती है लेकिन जो इतने सीनियर मैम्बर हों, वे हाउस के अंदर इस तरह की बात करें तो मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले जार्ज साहब ने टी.वी. के एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी का हाल हुआ था, वही हाल श्रीमती सोनिया गांधी का होगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से इस वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, हम लोग तो उस समय यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी थे। हम लोग और हिन्दुस्तान की अवाम जब अखबारों में पढ़ती थी तो लोगों के दिल और दिमाग में यह आता था कि हिन्दुस्तान की बाहर की ताकतें श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कराने की साजिश में शामिल नहीं हैं। यदि श्रीमती सोनिया गांधी का भी वही हाल होगा जिसकी कल्पना श्री जार्ज साहब करते हैं तो हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि यदि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में किसी बाह्य ताकत का हाथ रहा है और श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी वही हाल हो सकता है जिसकी जानकारी जार्ज साहब को है तो इसकी इंक्वायरी वर्तमान सरकार, यूपीए सरकार कराये कि क्या इस तरह की जो बाह्य ताकतें हैं जिनके लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं, उनमें कहीं ऐसे लोग तो नहीं हैं जो लोग इस तरह से टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे हैं। इसको हम कोई भवियवाणी नहीं कह सकते। हो सकता है कि उस पार्टी में चले गये हैं ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप आज के विाय पर आइये। अब आप कन्कलूड कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा : महोदया, आज हाउस में इस विाय पर चर्चा हुई है इसलिए मैं कह रहा हूं। ...(व्यवधान) आज ही उन्होंने महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण पर चर्चा की है, इस नाते स्वाभाविक है। मैंने कहा कि वे बहुत सीनियर मैम्बर हैं। जब उन पर डायनामाइट कांड का आरोप लगाया गया, उस समय हम यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी थे। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप अपना प्वाइंट बोलिये। अब आप कन्कलूड कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा : मैं कहना चाहता हूं कि उस समय इस तरह के आरोप उन पर लगे थे जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। यदि आज वे इस तरह की भवियवाणी कर रहे हैं तो मुझे शक है कि कहीं न कहीं उन्हें इसकी कोई जानकारी है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह का वाक्य क्यों इस्तेमाल किया ? क्या इसके पीछे कुछ सत्यता है और क्या उन्हें इसकी जानकारी है ? ...(व्यवधान) मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं चेयर से कह रहा हूं। ...(व्यवधान) आप चेयर नहीं हैं। ...(व्यवधान) आप बैठिये। ...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं ? ...(व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा : मैं चेयर से कह रहा हूं। ...(व्यवधान) आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। ...(व्यवधान) आपको क्यों बुरा लग रहा है ? ...(व्यवधान) जब उन्होंने टेलीविजन पर ऐसा कहा तब आपको बुरा नहीं लगा। अब मैं बोल रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अगर इस तरह से यह चलेगा तो किसी की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। ...(व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा : महोदया, मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं तो इन्हें क्यों बुरा लग रहा है ? ...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : हाल का मतलब हत्या नहीं है। इसका मतलब चुनाव में हारना है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अब आप कन्कलूड कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा : इस सदन में श्रीमती सोनिया गांधी पर वे लोग आरोप लगाते हैं ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप एक मिनट में अपना भााण कन्कलूड कीजिए। बहुत समय हो गया है। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेना है।

...(व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा : मैं माफी मांगूंगा कि सब लोग 20-25 मिनट ले रहे हैं। मैं सिर्फ दस मिनट ही बोलूंगा। ऐसे लोग यूपीए की चेयरपर्सन पर आरोप लगाते हैं ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अभी और भी लोग बोलने वाले हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा : जिन्होंने पूरी दुनिया में त्याग और बलिदान की एक मिसाल दी है। वे लोग उन पर आरोप लगाते हैं,

महोदया, वे लोग आरोप लगाते हैं जिन लोगों ने जीवनभर की नीति और दर्शन को सिर्फ एक कुर्सी के लिए आरएसएस के साथ मिलकर न्यौछावर कर दिया। वे लोग आरोप लगाते हैं उस यू.पी.ए. की चेयर पर्सन पर जिसने हिन्दुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में त्याग और बलिदान की मिसाल कायम की है और उनके ऊपर वे लोग आरोप लगाते हैं जिनके ऊपर भ्रटाचार के मामले में, जब वे स्वयं सरकार में रहे हैं, जिनके ऊपर गलियों-गलियों में नारा लगता रहा है फिर चाहे वह ताबूत घोटाला हो या तहलका कांड हो,...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के बाकी साथी भी बोलेंगे। सबको बोलना है।

डॉ. राजेश मिश्रा : मैं अपनी पार्टी के समय से ही बोल रहा हूं। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर शायद पहली बार भ्रटाचार का एक ऐसा तहलका का केस हुआ जिसे हिन्दुस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर देखा था और उसकी नींव जार्ज साहब के घर से ही रखी गई थी और वे श्रीमती सोनिया गांधी जी पर आरोप लगाते हैं। महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का आरोप लगाने के पहले ऐसे लोगों को जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।...(व्यवधान) जब ऐसे लोग पत्थर फेकेंगे तो उनके घरों की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूटेंगे। वे लोग डैमोक्रेसी की बात करते हैं।...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: You will have to conclude now.

डॉ. राजेश मिश्रा : महोदया, मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बहुत लोग गोवा का उदाहरण देते हैं। लोग लोकतंत्र का उदाहरण देते हैं। बहुत लोग गोवा और झारखंड का उदाहरण देते हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गोवा से महामहिम राज्यपाल जी की केन्द्र सरकार के पास रिपोर्ट तक नहीं आई थी और केन्द्र सरकार ने विधान सभा भंग करके वहां राट्रपति शासन लागू कर दिया। शायद इसके पहले कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं रहा होगा। लोग झारखंड की बात करते हैं। जिस दिन झारखंड में वहां शिबु सोरेन मुख्य मंत्री बनाये गये और उसी दिन से, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो पांच निर्दलीय एमएलएज हैं, उनका अपहरण करके उनको जयपुर घुमाया जा रहा है लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भले ही उनका अपहरण नहीं किया गया हो लेकिन उन्हें लालच और प्रलोभन देकर तथा जितने तमाम तरीके उनको अपने साथ रखने के हो सकते हैं, उन सारे अपने साथ रखने के तरीकों को रखकर उनको वहां घुमाया जा रहा है और ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं।...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Please conclude now.

डॉ. राजेश मिश्रा : महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान यू.पी.ए. की सरकार आज जनता की आशाओं पर खरी उतर रही है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास यह यू.पी.ए. की सरकार कर रही है और हम चाहेंगे कि सारी पार्टीज इसमें सहयोग करें। जो प्रदेश की सरकारें हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, वे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उनको लागू करें। जो पैसा जिस मद में जाता है, यदि आप उस मद में पैसे को खर्च नहीं करेंगे तो वहां पर भ्रटाचार होगा। सारा पैसा यदि एक जिले में या एक गांव में भेज दिया जाएगा तो विकास नहीं हो सकता। इसलिए प्रदेश की जो दूसरी सरकारें हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो वर्तमान केन्द्र की सरकार है, जो पैसा जिस प्रदेश में जिस मद में जा रहा है, उसका सही मायने में सदुपयोग करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण का मैं समर्थन करता हूं।

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Madam Chairperson, we have been discussing the Motion of Thanks on the President"""""""

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : I am not yielding… (*Interruptions*). I have not taken any name.… (*Interruptions*). I am not yielding.

MADAM CHAIRMAN: He is not yielding. How can I allow you?

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Madam, I am talking about internal security. The fundamental right is the subject of Government of India.

18.00 hrs.

Fundamental Rights have been enshrined in our Constitution. This is a matter of right of our citizens. I am talking about my rights… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : Please wait for one minute. It is six o'clock now.

… (*Interruptions*)

SHRI N. JANARDHANA REDDY : Madam, law and order is a State subject… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: You please listen to me. I am on my legs. It is already six o'clock and we have to extend the time of the House. If you all agree, then we may extend the time of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Madam, we have to complete the discussion on this Motion according to the list of speakers that has already been submitted to the Chair. The reply to this debate would be tomorrow.

MADAM CHAIRMAN: So, we may extend the time of the House till the discussion on this Motion is completed.

… (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Madam, I know that law and order is a State subject… (*Interruptions*) From 1951 till this date… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Shri Swain, please do not interrupt. He is capable enough to put forward his views.

… (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : From 1951 till this day, 114 times article 356 had been applied on the State of Andhra Pradesh dismissing popular Governments on the pretext of failure of law and order in the State… (*Interruptions*) The Congress Party was in power and if law and order is a State subject then why article 356 was imposed for over 100 times in the State on the pretext of failure of law and order in the State?… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Are you yielding to Shri Janardhan Reddy?

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : No, Madam. I am not yielding to him… (*Interruptions*)

SHRI N. JANARDHANA REDDY (VISAKHAPATNAM): Madam, you should not allow him to raise this matter here. Law and order is a State subject. The Andhra Pradesh Assembly is in Session. Enough discussion on it has already taken place there. The Leader of the Opposition, Shri Chandrababu Naidu himself has said in the House… (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : I am not contradicting anything… (*Interruptions*) It is my duty to mention it on the floor the House… (*Interruptions*) The State Government has failed to protect the rights of the people in the State… (*Interruptions*) The Central Government should intervene in the matter… (*Interruptions*)

SHRI N. JANARDHANA REDDY : When Ramanna Reddy was killed, what noise did he make?… (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : A sitting MLA of our party, Peritala Ravi has been killed… (*Interruptions*) This is a State-sponsored murder… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: I will not allow you to go on like this.

… (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Madam, we should not kill people. The Government should not take the law in its own hand. The Government should not sponsor all this… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

*Not Recorded.

MADAM CHAIRMAN: You can reply when your turn comes. Shri Yerrannaidu, you may please conclude now.

… (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Madam, that is why I am urging through you that there is no law and order in the State. Party workers are being killed everyday in the State and that is why the Centre should intervene in this matter.

Madam, before the elections, the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi visited the State of Andhra Pradesh to console the families of the farmers who committed suicide. After the UPA Government came to power, in the last ten months around 2500 farmers have committed suicide, but not once she visited the State to console their families. Before the elections, she did not go to Karnataka but she went to Andhra Pradesh to politicise the issue. What has happened in the last ten months? She has not visited Andhra Pradesh to console the families who have suffered during this period… (*Interruptions*)

18.04 hrs (Shri Arjun Sethi *in the Chair)*

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : The Chairperson of the UPA has not visited Andhra Pradesh to console the families who have suffered. This is Congress party… (*Interruptions*)

SHRI N. JANARDHANA REDDY : Farmers' suicide is not because of the policies of the present Government… (*Interruptions*) This is because of the policies pursued by the previous NDA Government… (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : No. This is not because of the policies of the NDA Government.

MR. CHAIRMAN : He is not yielding. Please sit down.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Why don't you prevent all these things? Why have they not prevented these suicidal deaths for the last ten months? Sir, I am asking a straight question to them. Now he is saying about the NDA Government and the Telugu Desam Party. After the Government came to power, they criticised for one or two months. But even for ten months, you are criticising them. They are saying that they are doubling credit to the farming community and they are issuing Kisan Cards. They are talking all these things. But why have they not stopped suicidal deaths in our country? This is my question. This Government is ineffective in controlling suicidal deaths in the country.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Chinta Mohan, please sit down. You have already spoken.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is speaking for the last ten minutes and he will conclude now. Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, the third point is scrutiny of the manifesto. What do any political party give in their manifesto? They have mentioned about free power in their manifesto. It has been endorsed by the Prime Minister and the UPA Chairperson. What have they promised in Punjab and Maharashtra and what has happened after they have come to power? They have withdrawn all these things. The Chief Minister of Maharashtra told the media, "Normally they put all these things in the manifesto but after coming to power, who will take cognisance of the manifesto?"

My Party is demanding that the manifesto should be legalised. If any political party issues a manifesto, there should be a legal sanctity for it. If any violation occurs, then that party should be recalled. The Congress Party has made all these promises everywhere. But after they came to power, they cheated the people. This has happened in Punjab, this has happened in Maharashtra, and now, it is happening in Andhra Pradesh also.

The fourth point is about categorisation of the Scheduled Castes. Among the Scheduled Castes, there are 59 sub-communities. The Andhra Pradesh Government has categorised them as 'A', 'B', 'C' and 'D'. After two years, the Supreme Court struck down the GO. Then, the Legislative Assembly of Andhra Pradesh passed a resolution unanimously to make a new legislation in the Parliament. So, through you, I urge the Union Government to overcome the Supreme Court judgement and bring a new legislation in this Session itself.

DR. CHINTA MOHAN : What about the Constitution?… (*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : This Resolution has been passed unanimously by the Andhra Pradesh Legislative Assembly. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded except the speech of Mr. Yerrannaidu.

*(Interruptions)**

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : The Chief Minister and all political parties have endorsed it. The Supreme Court has also given its judgement. You have to amend the Constitution. That is why, I am demanding this Government to do it. This is the promise of the Congress Government and other political parties. We have to amend the law in the ensuing Session. Sir, there are other issues also…… (*Interruptions*) How can you control me when the hon. Chairman has allowed me to speak?

I would mention about major issues as regards the Address of the President to the Parliament. Everywhere, they are talking about women reservation. This is the policy of the Government. On the eve of the International Women's Day, the Chairperson told the media that this is their prime concern. But where is it mentioned in the President's Address? Fifty per cent of our population constitute women but there is no empowerment. They are saying something and putting it in their manifesto but they are not doing anything.

*Not Recorded.

When Mr. Chandrababu Naidu was the Chief Minister, the Andhra Pradesh Government passed a resolution thrice..… (*Interruptions*) We have given 33-1/3 per cent reservation for women in the local bodies even before the 73rd and 74th amendment of the Constitution. The Andhra Pradesh Government has given reservation for women. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : For *Bharat nirman* and development of rural India, interlinking of rivers is important and is a major issue. The NDA Government had taken it as a prestige, appointed a Task Force and did some work on it. They had put it in the Common Minimum Programme of the NDA. They have mentioned about the interlinking of rivers there.

There is no mention about it in the President"""""""

There is a mention about OBCs in the President"""""""

श्री वीरेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, कश्मीर घाटी में आज भी घुसपैठ जारी है। हत्याएं हो रहीं हैं। आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं। इन पर नियंत्रण करने की बात पर बल देने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ कश्मीर में इस तरह का वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिस के कारण कश्मीरी पंडित वापस घाटी में आ सके। वे आज भी दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। जिस दिन कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में जाकर अपने घरों में रह सकेंगे, अपनी जमीन पर खेती कर सकेंगे, उस दिन देश की जनता में यह विश्वास का भाव जागृत होगा कि हमारी सरकार कश्मीर में सद्भाव का वातावरण बनाने में सफल हुई है। यह सारे देश के लिए प्रसन्नता की बात होगी। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने की बात का उल्लेख किया है लेकिन हमारे देश में पिछड़ा समुदाय भी है। सामाजिक समरसता की दृटि से उन पिछड़े समुदाय की स्थिति पर भी श्वेत पत्र जारी करने की बात सरकार द्वारा नहीं की गई जबकि सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्षता की बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है।

विपक्ष से कोई भी बोलने के लिए खड़ा होता है तो धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि सारे समुदाओं के बारे में इस तरह का श्वेत पत्र जारी करने की बात सरकार द्वारा कही जानी चाहिए । एक बात का उल्लेख किया गया है कि अनेक क्षेत्रों में आदिवासी असुरक्षा का जीवन बिता रहे हैं । इस बात को राट्रपति अभिभााण में स्वीकार किया गया है लेकिन वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने और आदिवासियों को भूमि का अधिकार देने की बात नहीं कही गई है । आज भी आदिवासी अशिक्षा का प्रतिशत ज्यादा है जिसके कारण आदिवासियों को गांवों में बंधुआ मजदूर बना कर रखा जाता है । इनके नाम पर बैंकों से लोन लिया जाता है, जिसके बारे में इनको जानकारी नहीं होती । जब बैंक से वसूली का नोटिस आता है तब उन्हें जानकारी होती है । उनको ऐसी दुविधा से बचाने के लिए इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

आज भी कई राज्यों में सिर पर मैला ढोने का कार्य जारी है । सन् 2005 तक इसको दूर करने के लिए लक्ष्य प्राप्त किया जाना था, लेकिन जो राज्य सन् 2005 तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ऐसे कर्तव्यों के प्रति उदासीन राज्यों पर केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की कार्रवाई करने का उल्लेख नहीं किया गया है। निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है लेकिन समूह ने कोई कार्य नहीं किया । इसी तरह दलित कार्य संबंधी मंत्री समूह का गठन किया गया । सरकार ने मंत्री समूह का गठन तो किया और कई बार समितियां भी बनाईं लेकिन मंत्री समूह और समितियों ने कुछ नहीं किया ।

राट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मेरे मित्रों ने उल्लेख किया है । सरकार ने इस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा कि राट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके साथ शामिल सभी दलों ने कहा कि इस कार्यक्रम के द्वारा देश में सिंचाई सुविधाओं, शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे । लेकिन इनकी घोाणाओं में से एक चौथाई अंश भी उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया । राट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का सिर्फ एक आश्वासन बन कर रह गया है। जैसा मेरे दोस्त श्री नायडू ने किसानों के संबंध में उल्लेख किया । एनडीए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई थी । इस योजना से किसानों में आशा का संचार हुआ । इस योजना के संबंध में सरकार मौन है । इस योजना की गतिशीलता में कमी आई है । कई राज्यों में गलत नीतियों और असहयोग के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं । यह बात सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है । किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं ।

एनडीए सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृटि से सारे देश में एम्स सरीखे के छः अस्पताल और बारह और अन्य अस्पतालों का विकास करने का निर्णय लिया था । यूपीए सरकार के आने के बाद एनडीए सरकार द्वारा छः अस्पताल बनाने की बात थी, इस संबंध में समय सीमा निर्धारित करके इन अस्पतालों को पूर्ण किया जाएगा, इस तरह का उल्लेख नहीं किया गया है । एक बात और कही गई है ग्रामीण भारत को नई पहल देने का वचन दिया गया था । लेकिन प्र धानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो गांव के लिए जीवन रेखा के समान है, इसकी गतिशीलता में कमी आई है । इसकी गति धीमी हुई है । जनता में विश्वास जागृत हुआ था कि सड़क बनने से सीधे बाजार से चीजें उठा सकेंगे, स्वास्थ्य के लिए केंद्रो में पहुंच सकेंगे, जिला केंद्रों में पहुंच सकेंगे, इससे गांव का विकास होगा । गांव के लोगों के विश्वास में कमी आई है ।

सिंचाई सुविधाओं में पिछड़े राज्यों के आर्थिक विकास की बात कही गई है । इसे कैसे किया जाएगा इस संबंध में नहीं बताया गया है । स्वर्णिम चतुर्भज सड़क योजना देश के विकास की महत्वाकांक्षी योजना है । इस संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस संबंध में सरकार मौन है । नदियों को आपस में जोड़े जाने के संबंध में श्री सुरेश प्रभु और मित्रों ने विस्तृत रूप से कहा है । आज हमारे देश के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर वर्ा नहीं होने के कारण सूखा पड़ता है । कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे बिहार, जहां वर्ा होने के कारण बाढ़ आती है और ऐसे राज्यों में पानी का सदुपयोग करने के बारे में एनडीए सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी । नदियों को आपस में जोड़ने की योजना पर सरकार मौन है ।

रोजगार गारंटी विधेयक के संबंध में 100 दिन के रोजगार देने की बात कही गई है । अभी चार दिन की छुट्टी थी । मैं गांव गया था वहां मुझे सीधे साधे व्यक्ति ने मुझे कहा - हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यह सरकार 100 दिन का रोजगार देने की बात कह रही है ।

यह सरकार 100 दिन का रोजगार देने की बात कर रही है लेकिन वर्ा के 365 दिन में से 100 दिन तक रोजगार देने के बाद गांव का आदमी 265 दिन क्या करेगा? क्या एक दिन खाकर वह तीन दिन तक भूखा रहेगा? मैं इस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं दे पाया। एक सामान्य व्यक्ति कितनी बड़ी बात कह रहा है, यह सोचने की बात है।

सभापति महोदय, हमारे देश में 26-27 करोड़ की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है लेकिन सरकार द्वारा केवल 50 लाख अंत्योदय कार्ड वितरित किये गये हैं। करोड़ों की जनसंख्या में से केवल 50 लाख कार्ड दिये जायें? इसको बढ़ाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, इलाहाबाद, मणिपुर विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की बात की गई है। मैं सागर, मध्य प्रदेश से आता हूं। देश के प्राचीन विश्वविद्यालयों में नालन्दा और अलीगढ़ आते हैं लेकिन सागर विश्वविद्यालय भी उनमें आता है। सागर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के लिये लम्बे समय से मांग की जाती रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिये प्रति वेदन प्राप्त करते हुये अनुकूल कार्यवाही करनी चाहिये।

सभापति जी, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों - बीड़ी क्षेत्र, हथकरघा क्षेत्र, बुनकर क्षेत्र, चमड़ा उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले और वनारोपण करने वाले मजदूरों की संख्या 93 प्रतिशत है। इनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन के संबंध में विचार किया जाना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है। हमारा

देश विशाल जनसंख्या वाला देश है। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जायेगा, तब तक सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये जब तक जाति, धर्म, भाा और लिंग की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी राजनैतिक दलों को - पक्ष और विपक्ष - को एक स्वर से जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिये सहमति नहीं होगी, मैं समझता हूं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा। इस दृटि से सरकार का यह पन्ना के वल राजनैतिक पर्चा बनकर रह जायेगा और विकास की कल्पना करना एक स्वप्नमात्र रह जायेगा जो इसमें लक्ष्य का अभाव दिखाई देता है।

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to support the Motion of Thanks on the President's Address.

On 26.12.2004, it was a shock and surprise to the entire nation, particularly to the people of Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry and Andaman & Nicobar Islands, due to Tsunami. The UPA Chairperson, Respected Madam Sonia Gandhi, our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh and other hon. Ministers visited the entire area and immediately took all the measures to safeguard the interests of the affected people and other victims.

The hon. Prime Minister also announced that we would not accept any foreign assistance in any way, either in kind or cash. This was a bold and welcomeable step taken by this Government. This Government also took immediate steps for the benefit of those people who are affected in Jammu & Kashmir due to recent avalanches.

The Government has also decided to constitute a National Disaster Management Authority. In this regard, the Government has also decided to bring forward a Central legislation. This was announced by our hon. President in his Address to the nation.

Sir, in this country lakhs of youths are not getting any jobs, particularly youths belonging to SC/STs and OBCs. The Government has already decided to constitute a Group of Ministers to have a dialogue with the industry in this regard, particularly with the private sector for giving job opportunities to these youths. With regard to SC/STs it has also been mentioned in the President's Address, but I would request the Government to consider OBCs also in this regard. The present Reservation Bill is under consideration of the Committee on Home Affairs for giving reservations to SC/STs and OBCs in the civil services. I would request the Government to expedite the matter.

Now, the Government has decided to give a new deal to rural India to expand health care, education, promoting rural electrification and rural roads. The hon. President has also announced setting up of a North-East Valley Authority to find out permanent solution to the problem of seasonal rains in the Brahmaputra Valley.

India have to divide the southern part and the northern part. The entire northern part is affected due to water. The southern part is suffering due to lack of water. So, the Government has to take steps for inter-linking, at least, the peninsular rivers in southern States and solve the problem of the people of the southern part of the country.

Also, to develop the Panchayati Raj institutions, to give more powers to the Panchayati Raj institutions and to solve the problems in the rural areas, the UPA Government has created a new Ministry of Panchayati Raj. The Ministry has drawn up a 150-point Action Plan covering 18 aspects of Panchayati Raj.

I want to mention another important thing. The UPA Government is committed to providing electricity to all the villages by the year 2009.

Another particular important aspect is that our hon. Prime Minister had inaugurated the National Food-for-Work Programme in 150 backward districts. It was launched in Andhra Pradesh on the birthday of our hon. former Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. The Government had decided to issue Antyodaya Cards to benefit two crore people and 50 lakh additional families.

With respect to education, during his Address, our hon. President announced the policies of this Government, particularly about the Education Cess which will form the *Prarambhik Shiksha Kosh.* This will enable better funding of the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, the Mid-day Meal Scheme and Nutrition Programme for Adolescent Girls. Also, the National Mission for Sarva Shiksha Abhiyan has been constituted for the first time. Further, a very important scheme announced is EDUSAT, an educational satellite, and Doordarshan's Direct-to-Home television facility to develop education. In this regard, I want to mention that in all the Kendriya Vidyalayas throughout the country, the student and teacher ratio is 1:30. The student and teacher ratio in thousands of schools in the villages, at the panchayat level, is 1:40. Like in Kendriya Vidyalayas, this has to be modified to 1:30 in all the panchayat schools to develop rural education. Also, the teachers who are working in the rural areas, in primary schools throughout the country, want to travel from the southern part to northern part and from the northern part to southern part of India for Education Tour. But they are

getting concession in the Railways only up to 25 per cent. The Government has to increase this to 50 per cent for those teachers who are attending seminars or going on education tours.

Also, based on the Report of the Commission headed by Prof. D.B. Chattopadhyaya, the Indian Education Service is to be constituted to develop education in this country. I want to mention particularly about the minority institutions, unaided and self-financed institutions where the teachers are not paid salary. They are giving them only Rs.500 or Rs.1000. That malady has to be removed. A Tribunal has to be constituted to hear the grievances of the teachers working in the minority, unaided and self-financed institutions. Then only the problem of those teachers who are suffering in the rural areas will be solved.

Also, the minority educational institutions in this country are misusing article 30(1) of the Constitution. That provision has to be suitably amended to protect the interests of the students as well as the teachers. Those who are running the minority institutions, the owners from the linguistic minorities or minority community, are admitting one other than minority students. They are not giving importance to the minority students. Also, the students will have to pay huge money. So, this provision has to be amended.

Also, our Government has decided to launch a National Rural Health Mission involving Panchayati Raj institutions to take health care to villages, to reach the goal of 'Health for All'. So, all the Gram Panchayats have to be given power. At least, the Primary Health Centres should be under the control of the Panchayati Raj institutions. Particularly in Tamil Nadu and even in my constituency, if we go to the Government hospitals, no Government hospital is having doctors.

MR. CHAIRMAN : Please wind up.SHRI S.K. KHARVENTHAN : I will conclude in two minutes.

Not a single doctor is available in the Government hospitals. The Government is not appointing any doctor in the Government hospitals. There is no staff. There is no medicine. No doctor is attending the Primary Health Centres. In the morning, even if 150 patients are waiting outside the hospital, doctors are not comin$_{n}$g. In$_{n}$ my constituency, there is a 52-bed hospital at Natham and another 52-bed hospital at Kangeyam. For a number of years, there are no doctors in these hospitals. So, to achieve this goal, the Government has to allocate funds and appoint doctors to solve the problems. With respect to the issue of farmers, I would like to mention that the Government had announced in the last Budget also that in respect of those who received loans from co-operative institutions up to 2004, the interest and capital amount would be added and they would be given further five years' time for repayment. For example, if a person takes a loan oRs. 1 lakh, the has to pay an interest of Rs. 48,000. In this case, Rs. 1.48 lakh would be treated as capital for two years and then interest would be added and payable within 3 years after 2 years period. So, after three years, he has to pay Rs. 2,10,000. How it will help the poor farmers? At least the interest and penal interest have to be waived in respect of farmers who have received loans from the co-operative institutions.

For the people residing in hilly areas, there are no road facilities. In Tamil Nadu, in Natham taluk, there are hilly areas in L.Malaiyur and P.Malaiyur where thousands of people are living but there are no roads. Sometimes when pregnant women from these hilly areas are taken to hospitals in carts, they feel it very dangerous and a number of people have chied. A lot of people have died because there are no road facilities to reach hospitals in these hilly areas. The Ministry of Environment and Forests must take steps to get roads built for the benefit of people living in these areas.

The Government is implementing the RSYV and SGRY schemes. These schemes are now in a pathetic situation. In the implementation of these schemes our hon. Members of Parliament are not at all consulted. The officers are allocating work, particularly of digging tanks, canals, etc., according to their whims and fancies and the money is given out by the State Government. The implementation of these schemes has to be regulated by the Union Government so that the benefits reach the poor people living in the villages.

With these words, I support the Motion thanking the hon. President for his Address to both Houses of Parliament.

SHRI A.V. BELLARMIN (NAGERCOIL): Sir, I rise to thank the President. I also thank the Chair for this opportunity to speak on this occasion.

His Excellency the President of India began his Address with a poetic expression, reminding us to listen to the call of the people. He said that the people want us to enrich their lives and lead them to a bright future.

The President has mentioned that the UPA's vital contribution to the nation has taken us back to the path of secularism and economic growth with equity and social justice. We, the Left Forces, want to believe that the Government has spelt out these through the President. We hope, equity and social justice would be the watchwords to give social security and

protection even to the last man in the social ladder. I think, this is what the President said when he said that caring policy and sharing economy are the of the hour.

"Where are we?" was the question mooted by the President when he started his Address. We must be on the righteous path to safeguard the voiceless masses which are left behind in the era of globalisation.

The very first concern of the President was the Tsunami tragedy. I come from Tamil Nadu, which had larger number of casualties in the tragedy. My constituency, Nagercoil, is amongst the worst hit. Let me record in this august House that rescue and relief operations were 'nil' or negligible in the first two or three days in that part of our country. The immediacy was not at all there in rushing help to the affected. The Government of India might have that there is a State Government in place but unfortunately the State administration did not make its presence felt immediately.

The fishermen are looking for immediate grants to rebuild their lives. They are not in a position to take loans or subsidies. Their livelihood stands shattered now. Grants to buy catamarans, *vallams*, boats and nets could be an effective assistance. That could be an immediate and also a long-term benefit.

There are many NGOs that come forward to help people to rebuild their washed away houses but there is a lack of co-ordination. Before the initial enthusiasm could wean, the Government must ensure their participation. So, I urge upon the Centre to formulate an effective co-ordination mechanism to avoid delay, to avoid misuse of funds and to avoid duplication of rehabilitation work. Corruption sharks are more dangerous than even the Tsunami. Further, permanent rehabilitation measures must be taken up with farsightedness to be both productive and employment generative.

Agriculture is the mainstay of our economy, but irrigation is still a problem in many parts of our country. Do we pay enough attention to water required for agriculture? The hon. President in his Address says water is a national resource. There are water sharing problems and disputes even in small rivers and canals running through neighbouring States. Neyyar Idadhukarai canal issue is a very simple example in my constituency. So, the sources for irrigation have to be renovated considering the increased need. Proposed irrigation projects, small and big, must be taken up.

The land reforms that were carried out in the Left-ruled States like West Bengal and Kerala are yet to be carried out in many other States. There must be a vigorous approach. Or else, we may not be able to uplift the poor and downtrodden, especially the Scheduled Caste and Scheduled Tribe masses.

The hon. President's observation about rejuvenating the cooperative sector is welcome. This must be pursued to strengthen the cooperative societies. This will also help village industries.

Public sector needs to be strengthened. The number of unemployed is on the increase and this fact cannot be ignored at a time when consumerism spreads fast.

I would also like to make an important point about the plight of Indian migrant workers. This is an area which needs to be looked into. Our Indian labour who earn foreign exchange reserves for the country through their remittances are not taken care of. Especially in the Middle-East, our Indian workers suffer a lot even with valid visas and work permits. Proper health care and work conditions are not there. The death rate of such workers is increasing. Even after death, their ordeal is not over. There is enormous delay in sending dead bodies to India. Even now there are many bodies lying in the mortuaries of the Arabian counties for months. Why do both countries ignore them when they render their sweat and labour to benefit the economy of both the countries?

The health care in India is far from being satisfactory. Increase in private sector medicare suggests the failure of the Government agencies. We need to strengthen research facilities to fight diseases like diabetes and cancer. The increase in such killer diseases must be controlled. If it is due to modern pesticides and fertilisers, there must be an effective monitoring mechanism to control them. As an alternative, Indian traditional medicine systems must be given a boost. Time-tested herbal treatment to diseases like cancer and diabetes must be pepped up.

Education system must be uniform throughout the country with stress on mother tongue in every region. The importance of mother tongue was well emphasised by the Father of our Nation. Ensuring quality higher education to the under-privileged is a step in the right direction. This is an essential investment to enhance skilled manpower.

At this juncture, I would like to urge upon the Union Government to start a Minorities' University in Nagercoil constituency on the pattern of Aligarh Muslim University. This can be a Central University that can be nodal to all minority institutions in that part of the country, which is considered as `Cradle of Education.'

With this, I conclude my speech, expressing our support to the Motion of Thanks to the President for his Address.

*SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): Hon. Chairman, let me thank the Chair for giving me an opportunity to speak on the occasion when the house is deliberating on the Motion of Thanks the President for his Address to the House.

Our President in his address has enlisted several welfare schemes meant for the betterment of the people especially the underprivileged sections. I would like to point out that the address incorporates almost all that has been stated in our election manifesto brought out by our leader Dr Kalaignar Karunanidhi. We welcome this on behalf of DMK.

Our President unfailingly expressed his deep concern for the huge loss of life and property due to tsunami tragedy. My Nagapattinam constituency has got the worst affected coastal areas devastated by the tsunami. More than ten thousand people have been found missing of which 8000 have been found to have been dead in my constituency alone. Our President referred to this tragedy and appreciated the role of the armed forces and paramilitary forces like army, navy, airforce and coastal guards for their extending timely help. I also want to express my gratitude to their service at the hour of need. I was a witness myself who saw these selfless soldiers carrying dead bodies from the debris, removing petrified bodies from the muds and rescuing the last of the survivors in that tragedy. But to the contrary, ignoring their invaluable service, the Chief Minister of Tamil Nadu has misrepresented the fact in the Legislative Assembly of Tamil Nadu that the army did not extend timely help to the affected people and failed to protect people. It reflects the arrogance of those who have made the irresponsible travesty of truth.

Union Government has set apart and put at the disposal of State Administration huge funds aiming at the relief and rehabilitation of the affected

_____* Translation of the speech originally delivered in Tamil.

people. Immediately after the tsunami tragedy, our Prime Minister Dr Manmohan Singh and UPA leader Smt. Sonia Gandhi must ahead of their personal visits took steps to send our Communications Minister Mr Dayanidhi Maran and Petroleum Minister Mr Mani Shankar Aiyar to the affected areas. Till then no Minister from the TN Council of Ministers visited those areas. As a follow up of the visit of Union Ministers of the UPA Government, many of the public sector undertakings of the Union Government rushed to the affected areas and extended a helping hand along with the personnel of the defence forces and security forces. The funds that have been released are not reaching the really affected people. Even in this relief work corruption had shown its ugly head in Tamil Nadu. I can cite an instance to prove my point. In a village called Kodiakkarai in my constituency Rs 3.5 lakhs was reported to have been disbursed to people who have never lived there and were not affected by tsunami. Our leader Dr Kalaignar also pointed out this. As a result of which the District Administration woke up and has announced two days back that the money disbursed there would be collected back. Not only this, in a neighbouring village called Vellapallam four thousand rupees was reported to have been given on record to one Pethannaswamy son of Siva Rao. If we verify that address we could only find a worship place there. Thus we find rampant corruption resorted to by the State Government led by the Chief Minister Jayalalitha. In another village called Pushpavanam a beneficiary's name is given as Manikandan son of Dhanapal. It is reported that he was paid Rs 2000 as relief assistance. On verification we find that the child who has been recorded as a beneficiary has not even completed 3 years of age.

While referring to tsunami tragedy our President has appreciated the role of all those who come forward to help the affected. Not only the armed and security forces but also the local people have been appreciated for their valiant role in rescue and relief measures.

Even when he was indisposed and was admitted in the hospital our leader Dr Kalaignar handed over one crore of rupees on behalf of DMK party to Smt. Sonia Gandhi. Thus our party took part in the efforts of the Government to wipe out the tears and ease the sufferings of thousands of tsunami hit people. Donation towards tsunami relief on behalf of DMK was handed over to hon. Prime Minister also.

In the President's Address it has been stated that a National Disaster Management Authority would be set up soon. This is an essential one. Our tropical country is always subject to the vagaries of weather. On one side you will find floods on the other you will find drought conditions. Uniform climatic condition is alien to our country. Had there been an authority already in place, it might have given forewarning at least in advance. Better late than never. At least after the tsunami disaster we must ensure that this authority is established at the earliest.

Our President has dwelt upon secularism and social harmony. I would like to point out here that at least a hundred 'social harmony colonies' styled as Samathuva Parrams were constructed by our leader Dr Kalaignar Karunanidhi when he was the Chief Minister of Tamil Nadu between 1996-2002. In order to promote brotherhood and social harmony and above all equality, he had constructed about hundred residential colonies called 'Samathuva Puram' in many rural and urban towns. Through this unique visionary project he enabled people from various communities to live together in harmony in such residential clusters. He had stated in our election manifesto that we would create a new history of communal harmony and ensure the return of secularism. This address fulfils those social ambitions for a good social ambience. 'Food for work' is another effective scheme that is sought to be implemented in selected 150 districts all over the country before it could be spread all across the country. I urge upon the Government to set right the lacunae in implementing that scheme. Nagapattinam district in my constituency has also been selected to implement that scheme. Though it is a Central scheme fully funded by the Union Government, the MPs of the local area are in no way involved in overseeing the implementation of the

scheme. There is no transparency in identifying the beneficiaries. It is not clear as to who is implementing. Hence I urge upon the Union Government to issue proper guidelines in this regard because there is corruption even in identifying the beneficiaries and implementing this scheme.

Our President has mentioned that water is a national resource. At this juncture I would like to urge upon the Centre to resolve vexing inter-state river water disputes and find viable means to implement the Cauvery water tribunal award at the earliest.

The President of India has also spelt out that reservations in jobs in the private sector for the people from SC and ST communities would be ensured through deliberations. It is a step in the right direction. I welcome this move. To establish an egalitarian society it is essential. Spreading midday meals scheme has been pointed out in the President's Address. I would like to point out that real nutritious noon meal scheme was in place during the tenure of our leader Dr Kalaignar Karunanidhi as our Chief Minister of Tamil Nadu. I wish Government of India takes this right message all over the country providing nutrient food to our needy children who are the future of our country.

Before I could conclude, while welcoming the increased allocation for public health, I would like to refer to the inadequate short supply of Rabbis vaccine in many parts of the country especially in Tamil Nadu. Arrangements must be made in this regard. People from the underprivileged sections of the society need effective financial assistance for surgical treatments for terminal ills like heart ailment. I urge upon the Government to ensure that the really needy people get financial help when they need it the most.

I would like to put on record my appreciations to the encouraging growth pace and new strides witnessed in the IT sector of which portfolio is held by hon. Minister for Communications and Information Technology Shri Dayanidhi Maran. His dynamic handling of the affairs of IT sector ensures a quality service comparable to models set by countries like the US in the field. He introduced recently on Pongal Day the Broadband Internet Connectivity to the subscribers. It is a welcome step.

The President in his address has mentioned about the creation of a body for the welfare of workers in the informal and unorganised sector. I would like to point out that a Board was constituted by the Tamil Nadu Government when Dr Kalaignar Karunanidhi was at the helm of affairs as Chief Minister for workers in the unorganised sector. Washermen, construction workers, hair dressers, hawkers, were all benefited after his forming a body for agricultural workers who could get Rs 1 lakh on death by paying Rs 10 as annual premium like. This scheme has been done away with in Tamil Nadu in the new regime.

Now, the Government of India is to take it up again all over the country and I heartily welcome and thank the President for his Address to the Parliament. Expressing my support to the Motion of Thanks, let me conclude.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Paras Nath Yadav. Kindly try to conclude your speech in less than five minutes.

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने महामहिम राट्रपति जी के अभिभााण की चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया। महामहिम राट्रपति जी का अभिभााण सरकार की नीति और उसके क्रियाकलापों का एक दस्तावेज, एक दर्पण हुआ करता है।

देश की आजादी के 57 सालों में एक सपना देखा गया था कि हिन्दुस्तान विभिन्न जाति धर्मों का देश है और खेत, खलिहानों और गांवों का देश है, इसका स र्वांगीण विकास कैसे होगा। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इस देश में एक दस्तावेज लिखकर, जिसे हम संविधान कहते हैं, दिया गया और जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी विधानसभाओं और हमारी पार्लियामेंट में लोकहित, जनहित कल्याणकारी कानून बनाकर देश के सर्वांगीण ि

वकास का सपना उन मनीीियों और चिन्तकों ने देखा था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि देश की आजादी के 57 सालों में, जो गांवों का देश रहा हो, कृि प्र ाधान देश रहा हो और हमारे उस दस्तावेज संविधान में यह बात निहित भी हो कि जब तक इस देश की खेती विकसित नहीं होगी, तब तक हम देश की तरक्की नहीं कर सकते। यह बात भी कही गई हो कि देश के विकास का मुख्य साधन खेती होगा, लेकिन खेती के विकास के लिए देश में सरकार जो भी आईं, हम यह नहीं कहना चाहते कि एक ही दल की सरकार रही, लेकिन जो भी सरकारें थीं, खेती के विकास के लिए कितना काम किया, इसका जब लेखा-जोखा लिया जाता है तो दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क हैं, अमेरिका जो इस समय विकसित देश माना जा रहा है, जो दुनिया में अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, वहां चार प्र ातिशत लोग खेती करते हैं। लेकिन अमेरिका अपने किसानों को प्रतिर्वा 31 हजार डालर सब्सिडी दिया करता है, चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, लेकिन इस देश में कृि प्रधान देश मानकर भी हम किसानों की माली हालत ठीक नहीं कर सके।

किसान को पानी, खाद, कीटनाशक दवाओं को देना तो दूर रहा, हम उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं कर सके हैं । जब देश आजाद हुआ तब 35 करोड़ आबादी देश में थी और आज एक अरब पांच करोड़ की आबादी हो गई है । जब 35 करोड़ की आबादी देश में थी, इसी संसद में 1963 में तत्कालीन प्र ाधानमंत्री, जब गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने और गरीबी मिटाने का कानून बना रहे थे तो डॉ. लोहिया ने कहा था कि मान्यवर गरीबी मिटाने का आप कानून बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि बेरोजगारी से गरीबी आती है । गरीबी से बरोजगारी नहीं बढ़ती है, बेरोजगारी से गरीबी आती है इसलिए पहले बेरोजगारी खत्म करनी होगी। गरीबी खत्म करना है तो बेरोजगारी खत्म करने का कानून बनना चाहिए।

महोदय, लेखा-जोखा बताते हैं कि गरीबी मिट गयी है और गरीबी इस देश में नहीं है। उस समय के तत्कालीन नेता रहे डॉ. राम मनोहर लोहिया की बात मान ली गयी होती और इस देश में बेरोजगारी खत्म करने का कानून बन गया होता तो आज गरीबी न होती, यह मेरा मानना है। किसानों की हालत को ठीक कर लिया गया होता और लोगों को शिक्षित कर लिया गया होता तो आज हिन्दुस्तान दुनिया का शक्तिशाली देश होता। क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, जिसे देखने के लिए विदेशी लोग तरसते रहे, जहाँ दूध-दही की नदियाँ बहती थीं, जिसने विश्व बंधुत्व का सपना देखा। आज वही भारत है, लेकिन हम भारत के साथ इस 57 साल की आजादी पर बहस करते हैं। पक्ष-विपक्ष की आलोचना करते हैं। बहुत से हमारे विद्वान साथी बोल रहे थे कि अकेले 57 साल में चार दशक से ऊपर हुकूमत करने वाले लोग यह कहते हैं कि जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ हम हवाई जहाज बना रहे हैं, ये सब बातें कोरी कल्पना हैं। हम लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सके हैं। जनता की मूलभूत आवश्यकताएं शिक्षा और स्वास्थ्य है। दुनिया के बहुत-से मुल्क जिन्होंने शिक्षा का विकास कर लिया है, आज वे विकास की पराकाठा पर हैं परंतु हम उसी जगह खड़े हैं। हम 58 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को शिक्षित नहीं कर सके। अपने बजट को शिक्षा और खेती पर खर्च नहीं कर सके। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। इस पर बहस होनी चाहिए और वह सकारात्मक होनी चाहिए। किसने गलत किया, किसने सही, इस पर चर्चा होती है। लेकिन जो भी सरकार बनी उन सरकारों ने इस देश की 57 सालों की

आजादी में, चार दशक तक हुकूमत करने वाले लोगों ने क्या नीति और कार्यक्रम बनाए, उनको इस पर चिन्तन करना चाहिए। यह बात स्पट है कि धर्मनिरपेक्ष संि वधान दस्तावेज हमारा था और इसके विरोध में आज जो जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता के लालच में लोगों ने कुर्सी पायी, चाहे इधर के बैठे हुए लोग हों या उधर के, अगर एक मन्दिर का ताला खुलवाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो दूसरा मूर्ति लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस देश में उत्तर प्रदेश, जहॉ से मैं चुनकर आता हूँ, देश का ह्रदय कहा जाता है। आबादी में सबसे बड़ा यह प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है। उतर प्रदेश में सरकार चल रही है, जिसका मुखिया समाज वादी व्यवस्था के आधार पर देश का विकास करना चाहता है क्योंकि हमारे विद्वानों ने कहा था और खास तौर पर डा0 लोहिया जी ने कहा था कि जब तक इस देश में समाजवाद नहीं आएगा तब तक हम इस देश का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं । चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत-खलिहान से हो कर जाता है । अगर एक महीने सूखा पड़ जाता है तो सरकार फसल सींचना तो दूर पीने के पानी का इंतजाम नहीं कर सकती है । तीन दिन मुसलाधार वर्ा हो जाए तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर सकती है।

महोदय, सुनामी लहर आई और तमाम लोग उसमें मर गए। उनकी सहायता के लिए सरकार बधाई की पात्र है । हमारी जनता बधाई की पात्र है । विदेशियों ने मदद की, हम उनको बधाई देते हैं लेकिन 57 साल में हमारी योजनाएं क्या हैं? हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं? हम इसका विकास कैसे करना चाहते हैं? इसके लिए नीतिया बनानी चाहिए ।

19.00 hrs.

इसीलिए हमारे विद्वानों ने कहा है हमारी आलोचनाएं होती हैं। जितनी भी सरकारें बनीं, हमारे देश में जितने भी नेता हुए, नीतियां तो बढ़ियां बनाईं, नेता भी बढ़िया रहे, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी, तब तक हम इस देश की तरक्की नहीं कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उत्तम प्रदेश बनाने का एक सपना देखा है। आज बिजली हमारी आवश्यक आवश्यकता हो गई है। हमारे बिजली उत्पादन के जो घर हैं, उनकी उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है अथवा बन्द पडे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चार हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए बिजली घर बनवा रही है और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है। लेकिन देश की सरकार उसे ऐसा कोई पैकेज नहीं दे रही है। नीयत खराब है। बदले की भावना से काम करने से गांव की तरक्की नहीं होगी, खेत-खलिहान की तरक्की नहीं होगी। महामहिम राट्रपति जी का अभिभाण जो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का लेखा-जोखा होता है, उसमें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनी। इसलिए हम चाहते हैं कि समान गति से जो सरकारें बनें, वे देश की सरकारें हैं, वे किसी दल की सरकारें नहीं हैं। इस देश में कांग्रेस सरकार दो-तिहाई बहुमत पर 42 साल तक चली है। 42 साल के अपने कार्यकाल में केवल यह कहकर कि जहां सुई नहीं बनती थी, वहां हम हवाई जहाज बनाने लगे हैं, यह बात संतोाजनक नहीं होगी। जब तक पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पिछली पंक्ति में बैठने व्यक्ति के होंठों पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक हम इस देश की तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए हम महामहिम राट्रपति के अभिभाण को धन्यवाद देते हैं लेकिन चाहते हैं कि सरकार समान गति से पिछड़े प्रदेशों की तरक्की के लिए, वहां की जनता की खुशहाली के लिए काम करे।

इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं महामहिम राट्रपति द्वारा प्रस्तुत अभिभाण पर इस सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करने के लिए मजबूर हूं। मान्यवर, महामहिम राट्रपति के मुखारविंद से यूपीए

सरकार ने जो अपना गलत गान करवाया है, मैं समझता हूं कि यह वास्तविकता से सर्वथा परे है। जब से यूपीए की सरकार आई है, लोग कहने लगे यूपीए - यू मायने उल्टा, पी मायने पुलटा और ए मायने आराम करो। उल्टा, पुल्टा, आराम करो या उखाड़ो, पछाड़ों, आराम करो। इसके अलावा इनका तीसरा कोई काम नहीं है क्योंकि इस सरकार के आने के बाद सारी सरकार का जो संयुक्त दायित्व होना चाहिए, सारी सरकार की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, पता नहीं लगता प्रधान मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी कुछ और कह रही हैं, लालू जी कुछ और कह रहे हैं और पासवान जी कुछ और कह रहे हैं। उनकी हां में हां मिलाने वाले वामपंथी लोग अंदर जाकर कुछ और कहते हैं और बाहर आकर पब्लिक में कुछ और कहते हैं। जो दो-मुंहापन चल रहा है, एक नीति, एक गति, एक मति और एक रीति जो सरकार की होनी चाहिए, वह बिल्कुल नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल शासन को उल्टो, पलटो, उखाड़ो, पछाड़ो और आराम करो और जनता जाए जहन्नुम में। इस प्रकार की स्थिति इस सरकार की हो गई है। इसलिए मैं इस सरकार की नीतियों का, जिसका महामहिम राट्रपति जी के मुखारविंद से गुणगान करवाया गया है, पुरजोर विरोध करता हूं।

जब एनडीए की सरकार थी, देश के अंदर साम्प्रदायिक अमन और चैन था। छः साल तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही, देश के अंदर कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। इस सरकार के आते ही इनकी नाक के नीचे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिया और सुन्नी का विवाद, अन्यत्र महामहिम राट्रपति के मुखारविंद से अल्पसंख्यक आयोग की बात कहलवाना, अल्पसंख्यकों के लिए अलग विश्वविद्यालय की बात करना, एक प्रकार से सारे देश की जनता को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बांटने वाली बात यह सरकार करने जा रही है। जब एनडीए की सरकार थी, वह भी आतंकवादियों और अलगाव वादियों से बात करती थी। लेकिन उसके साथ ही राट्रहित को सर्वोपरि मानती थी। जब से यूपीए की सरकार आई है, इन्होंने तेलंगाना समिति के प्रभाव में आकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रभाव में आकर अपने आपको दुर्बल मानते हुए नक्सलवादियों से बिना हथियार रखवाए हुए बातचीत करने की आज्ञा दे दी। इसे राट्रहित में अच्छा नहीं कहा जा सकता।

नक्सलवादियों के प्रभाव में जितने राज्य हैं, चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो या झारखंड हो, इन सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने कहा कि नक्सलवादियों से बातचीत करने से पहले उनका जो हिंसा का रास्ता है. उनके जो हथियार हैं, उन्हें पहले रखवाओ, उनसे समर्पण कराओ और उसके बाद ही उनसे बातचीत करो। लेकिन इस सरकार ने उनके वोट लेने के लिए आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए नक्सलियों के आगे घुटने टेक दिये। परिणामस्वरूप माओवादियों ने नेपाल में जो किया, वह तो नेपाल की बात है लेकिन हमारे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में आये दिन कभी पुलिस वालों की हत्या तो कभी निर्दो जनता की हत्या करने का जो वातावरण चल रहा है, उसे राट्रीय एकता की दृटि से कभी उचित नहीं कहा जा सकता।

मान्यवर, जब तक एनडीए की सरकार थी तब तक महंगाई ने बढ़ने का नाम नहीं लिया। उन्होंने विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कर दिया था कि देश में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से चीजों के मूल्य बढ़े हैं, मुद्रास्फीति बढ़ी है। गांवों में नारा लगता है कि--कांग्रेस का देखो खेल, खा गयी शक्कर और पी गयी तेल। आम जनता के काम में आने वाली जो चीजें हैं, जैसे शक्कर, जिसे गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है, वह राशन की दुकानों पर मिलनी मुश्किल हो गयी है। उसके भाव बाजार में बढ़ गये हैं। मिट्टी का तेल जिसे जलाकर बिजली के अभाव में किसान अपनी झोंपड़ी में रोशनी करता है, उस मिट्टी के तेल का कोटा भी केन्द्र सरकार ने राज्यों का कम कर दिया है। इसी प्रकार जो खाने का मीठा तेल है, जिसमें पकाकर गरीब बेचारा सब्जी खाना चाहता है, वह मीठा तेल भी इस सरकार ने महंगा कर दिया है। परिणामस्वरूप इस सरकार की एकमुंही नीति नहीं होने के कारण देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है।

मान्यवर, सरकार ने शिक्षा के नाम पर इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। जब हमारी एनडीए की सरकार थी, उन्होंने बड़े-बड़े विद्वानों को बैठाकर इतिहास को सही परिपेक्ष्य में रखने का काम किया था, लेकिन यूपीए सरकार ने आते ही भगवाकरण के नाम पर जैसे लाल कपड़े को देखकर सांड भड़कता है वैसे ही यह सरकार भगवाकरण, जो इस देश में त्याग और बलिदान का प्रतीक रहा है, के नाम पर राट्रीय नेताओं के बारे में, हमारी आजादी की लड़ाई के इतिहास के बारे में या अन्य हमारे जो राट्रीय मूल्य हैं, उन सबके बारे में इतिहास में जो गलत तथ्य पढ़ाया जाता था, एनडीए सरकार ने उन् सबको दुरस्त कराया था, उसे इस सरकार ने आकर बदलवाने और कम्युनिस्टों की विचारधारा के लोगों को शैक्षिक संस्थानों में बैठाने का कार्य किया है।

मान्यवर, इसके अलावा राज्यपालों के माध्यम से गैर-कांग्रेसी सरकारों को अस्थिर कराने का काम भी इस यूपीए सरकार ने किया है। झारखंड में उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है। गोवा में लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का जो प्रयास किया गया, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज बिहार में जब इनकी सत्ता छिन गयी, उनके समर्थक लोग जो आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन लोगों की मानसिकता क्या है ?

सभापति महोदय, राज्यपाल जैसी संवैधानिक सत्ता को कमजोर करने का काम, उन्हें कठपुतली बनाने का काम भी इसी यूपीए सरकार ने किया है। इन्होंने सत्ता में आते ही बहुत से राज्यों में राज्यपालों को बदल कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है। इसके अलावा बहुसंख्यक वर्ग के किसी भी सही काम को गलत ठहराने और अल्पसंख्यक वर्ग के गलत काम को सही ठहराने का काम भी इसी सरकार ने किया है ताकि माइनोरिटी के वोट इन्हें मिल सकें। वोट की राजनीति के अंदर ये लोग तमिलनाडु में कांची-कामकोटि पीठ, जो दो हजार साल पुरानी संस्था थी, वहां कोर्ट अपना काम करती, न्यायालय अपना काम करती, लेकिन जिस ढंग से उस संस्था का अपमान करने का प्रयास किया गया, उसके कारण लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा। इस कारण सारे देश में लोग उत्तेजित हो रहे हैं। जब केन्द्र सरकार से शिकायत की, तो यहां से एक शब्द कहा गया कि यह राज्य का मामला है। जब उनके हित का मामला हो तो फिर राज्य कुछ नहीं है और संविधान को तोड़-मरोड़कर...(व्यवधान)

और जब उनके हित का मामला नहीं हो तो संविधान को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करते हैं।...(व्यवधान)

SHRI S.K. KHARVENTHAN : It is a matter pending in the Court. Where is the question of raising it here? … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You can refer to it when your turn comes.

… (*Interruptions*)

SHRI A.V. BELLARMIN (NAGERCOIL): The AIADMK is their alliance partner. The Central Government is nowhere connected. Law and order is a State subject.… (*Interruptions*)

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, राट्रपति जी के अभिभाण में जो करोड़ों विदेशी घुसपैठिए, बंग्लादेशी घुसपैठिए हिन्दुस्तान के अंदर आ गये हैं, उनको यहां से वापस भेजने के लिए इस सरकार ने कोई संकल्प तक नहीं किया है। क्यों ? इस सरकार को समर्थन देने वाले वामपंथी लोग जो कि इस सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी है और प्रधान मंत्री जी दिन में कितनी बार राट्रीय सलाहकार परिद की अध्यक्षा सोनिया गांधी से पूछते हैं, इससे प्रधान मंत्री का पद कितना कमज़ोर हो गया है। मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हिन्दुस्तान के लिए यह कोई गौरव और स्वाभिमान की बात नहीं है।

मैं आपके माध्यम से अंतिम बात कहना चाहता हूं। जब से यह सरकार आई है, हमारे राजस्थान राज्य के साथ भेदभाव की नीति बरती जा रही है। राजस्थान को रिफाइनरी प्राप्त होने वाली थी लेकिन इस सरकार ने वह रिफाइनरी पंजाब के अंदर भेजकर राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है। एन.डी.ए. की सरकार ने नदियों को राट्रीय सम्पदा मानते हुए एक योजना बनाने का प्रयास किया था कि नदियों को जोड़कर उनके पानी को एसे इलाकों में पहुंचाया जाए जहां पर अकाल पड़ता हो। लेकिन यह सरकार सत्ता में आते ही इस काम को भूल गई और इसके परिणामस्वरूप यह अकाल वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे कैसे निपटा जाएगा, इसके बारे में इस सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रधान मंत्री ग्राम सम्पर्क सड़क योजना की राशि यू.पी.ए. की सरकार ने रोक दी है। यह सरकार गैर-कांग्रेसी सरकारों को बिजली देने के मामले में भेदभाव की नीति बरत रही है। इसलिए मैं राट्रपति जी के अभिभाण पर इस सरकार द्वारा प्रस्तुत धन्य वाद प्रस्ताव का डटकर विरोध करता हूं।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, I stand before you to support the Motion of Thanks on the President's Address moved by Shri Pawan Kumar Bansal. Actually, we are very grateful to the hon. President for his Address, which he has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament.

Just now, we heard our friends. It looks like a good debate. I would propose to put it this way that the Address given by His Excellency in the Central Hall is one of the best Addresses we have heard in the history of Indian Parliament because it has covered almost all the aspects that this UPA Government wants to do. He had mentioned about Tsunami tragedy. I will add to Tsunami, cyclone, earthquake, flood, famine and all sorts of natural calamities. We are going to have the National Disaster Management Authority for this. Last month when we toured Gujarat, we met the authorities of the Indian Institute of Management, Ahmedabad. I myself had proposed that we could start a course on Disaster Management. We have done very well in the field of management. We propose that we should have a permanent authority to look into all these natural calamities because in India, there are very big rivers. We have recently come across floods in Assam, cyclone in Gujarat and earthquake in many places.

We require to have such an authority, which is a must.

Coming down to the sense of humanity in the President's Address, I would like to quote a few lines of para 10, which, of course, belongs to the State of Manipur as well as the State of North-Eastern India and Jammu and Kashmir. Para 10 says:

> "My Government has infused a new sense of belonging among various disaffected groups, especially in the North-Eastern States and among the tribal communities across the country. The handing over of the historic Kangla Fort to the people of Manipur was not just a glorious moment in the history of the Manipuri people, it also symbolised my Government's commitment to all segments of our society that they have a right to live a life of dignity and self respect."

Here, I emphasise because this Kangla Fort is the place where on April, 27 that the Union Jack was hoisted replacing the Manipur flag when Manipur lost its Independence in 1891. This has been the bone of contention for many years. It is in this particular time, and we are very fortunate under the leadership of the UPA leader, Madam Sonia Gandhi and the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, that this fort has been handed over to the people of Manipur. We are very much grateful for that. I will be failing in my duty unless I rise and mention this in this august House.

Coming to other points, there have been a good number of good things going on. I would try to be very brief because of paucity of time. The hon. Members must be remembering the moment when the President of India stood up and delivered his Address. He started with a poem, a poem, which he had himself written. That shows his humanity.

At the same time, the National Common Minimum Programme has seven priority areas. The first priority area, very rightly so, is the Agriculture. It is because a very large section of India belongs to agriculture. Next priority area is Education. Education is the one area where the investment we do today do not give its result immediately. We have to wait long years. It is a very long-term investment. Since I belong to the community of teaching for many years, we feel that education should be given top priority next to agriculture. It is quite fine, because ours is a land of agriculture, which we have to develop side by side.

The next priority areas are: Employment, Healthcare, Infrastructure – Urban Renewal, and Water. I would come to that. We have a "New Deal to the Rural India". Of course, that is a very important area.

Regarding water management, of course, I do fully agree with my hon. friends of the Treasury Benches that we have to have an integrated water management for the entire country because this is an area where a lot of thought is required to be given. A scientific temperament is to be meted out.

Sir, one interesting thing is that Manipur, of course this time, has been given all the privileges. Our Manipur University has been made a Central University. It was a long standing demand because we do not have enough money even to pay to our faculty members. During my time as the Education Minister of the State, we proposed to the then NDA Government to make Manipur University a Central University but we could not succeed. But now with the change of Government here, with the new Government here, we could convince them, and the hon. Prime Minister has very rightly declared it as a Central University. He has very graciously fulfilled our demand.

Sir, here I would like to mention one more point. It was mentioned by one hon. Member on the other side that there was no mention in the President's Address about the development of the National Highway Authorities of India, about the greater autonomy being given to it. But let me remind my friend that it was mentioned in the President's Address. It is there at para 37. My friend also said that there was no mention about the Golden Quadrilateral. But it is very much mentioned there that 'the rate of completion of road construction under the national highways programmes, especially the Golden Quadrilateral and the North-South and East-West corridors, has been speeded up.' I am sorry, we have to go through the entire speech very minutely, otherwise we may be misleading the people.

Now, I would come to the development of khadi and village industries in the country…

Manipur is one of the States where we have a history of handloom and handicraft, and everyone knew it well. We were having a lot of cotton growing areas, but now it has come to such a bad shape that not a single seed of cotton is available. We are now selling clothes purchased from other markets, and living on marginal profits.

At the same time, I would like to draw your attention to the fact that the three main areas of challenge to our national security have been identified as cross border terrorism in Jammu and Kashmir, insurgency in the North Eastern Region, naxalite violence in some States. Of course, we have addressed the problems quite rightly and it is right time that the Government of India initiate talks with our insurgent-friends in the North Eastern India. They are ready to come and perhaps with this, we have a political solution to the longstanding problems. … (*Interruptions*) I would request you to give me some more time to speak.

We have the DONER, the Department Of North Eastern Region, being made a Ministry now and we are very very thankful for that.

I would like to quote paragraph no.49, at page 17 of the Address where it has been mentioned that there is no issue or problem which we cannot solve through a patient and constructive dialogue. It says:

> "In the final analysis, power in India can only flow from the ballot box, never from the barrel of a gun."

I would now come to the last point by quoting the last but one paragraph of his Address. It is very important. President is very humane in telling this. I will quote that. Since I am a first-timer in this Parliament, I am keenly observing the proceedings of the House very painfully and here, this paragraph is very relevant. It says in para 72:

> "Honourable Members, you have the heavy burden of legislative work pending before you. This session will discuss the Union Budget and other Legislative business. There are several important bills at various stages of deliberation awaiting your consideration. The people of India anxiously await your views and your decisions on these crucial economic and social legislation. I urge you, Honourable Members, to repay the trust and confidence that the people have reposed in you by dedicating yourselves to the orderly consideration of these Bills. Every minute of Parliament's time is precious and every citizen and taxpayer values it greatly. I sincerely hope you will make the most effective use of the time at your disposal and meet the citizens' expectations and fulfil their aspirations."

We have to remember this. With these words, I thank you very much for having given me some time to speak and support the motion.

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारांगल) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राट्रपति जी के अभिभाण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हो रही बहस में बोलने का मौका दिया। मैं 14वीं लोक सभा में चुनकर आया हूं, तो मैंने सोचा था कि हम लोग यहां कुछ सीखेंगे। यहां पर पर भुखमरी पर, बेरोजगारी पर, अनरैस्ट पर और पीने के पानी जैसी समस्याओं पर हमें भी बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन दुख की बात है कि करीब दस महीने हो गए, लेकिन हमें अभी तक इन वियों पर चर्चा करने का मौका नहीं मिल सका। इसके साथ ही जिन लोगों ने हमें यहां चुनकर भेजा, उनकी हालात पर भी बात करने का मौका बहुत कम मिला। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपनी तेलंगाना राट्र समिति पार्टी की ओर से भी आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

राट्रपति जी ने अपने अभिभाण में कई चीजों पर प्रकाश डाला है। पिछले 57 साल से इस देश में जो उन्नति हुई और उसमें कहां कमी रही, उसको कैसे दूर करना है, इस पर भी उन्होंने फोकस किया। मैं अपनी तेलंगाना राट्र समिति पार्टी के अध्यक्ष चन्द्र शेखर राव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे रिजर्व कैटेगरी का होते हुए भी जनरल सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं उस सीट से जीतकर लोक सभा में पहुंचा और आज मुझे राट्रपति जी के अभिभाण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिला है।

मैं माननीय चन्द्रशेखर राव जी को धन्यवाद देता हूं। उसी तरह से हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और यूपीए की चेयरपर्सन माननीया सोनिया जी को भी धन्यवाद देता हूं कि यूपीए की सरकार ने तेलंगाना का ध्यान रखा है। तेलंगाना पिछड़ा हुआ इलाका जहां पर साढ़े तीन करोड़ लोग रहते हैं। उनकी समस्याओं को सोच-समझकर यूपीए के एजेंडा में, अलग तेलंगाना बनाने के तहत लिया गया है। उसके लिए भी मैं केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं।

सभापति जी, टीआरएस पार्टी से मैं अकेला सदस्य हूं। आज हिंदुस्तान में जो अशांति फैली हुई है, उसका कारण क्या है? जो गरीबी है, बेरोजगारी है, सप्रेशन है, इनको दूर करने के लिए सरकार को सोचना होगा। पिछले 57 सालों से बजट का जो भाग इन लोगों तक पहुंचना चाहिए था वह नहीं पहुंचा है। इस सिस्टम को ठीक करना होगा। माननीय राट्रपति जी ने महिलाओं के बारे में, बैकवर्ड क्लासेज के बारे में, यूथ, माइनोरिटीज, आदिवासी, शैड्यूल्ड कास्ट और बुनकरों के बारे में अपनी सोच को अपने अभिभाण में शामिल किया है। दस सालों के बाद आज बहुत अच्छा बजट हमारे सामने आया है और इसे हम सही दिशा में ले जाने का कार्य करें। जहां पर राज्य सरकारें इस कार्य में सफल नहीं होती हैं, वहां पर केन्द्र सरकार को आगे आकर कुछ करना होगा। माननीय राट्रपति जी ने अपने अभिभाण के पैरा 12 में, आदिवासियों के बारे में जो कहा है, बहुत दुःखद बात है। अब तक हजारों करोड़ रुपये आदिवासियों पर खर्च किये गये हैं लेकिन उनकी दशा में सुधार नहीं आ पाया है। माननीय राट्रपति जी का कमिटमेंट है लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं वह बनी हुई हैं क्योंकि इनके जो अधिकार हैं वे इन्हें मिल नहीं पाये हैं। यह बहुत दुःखद बात है। पिछले 57 सालों में इनको साढ़े सात प्रतिशत रिजर्वेशन मिलना चाहिए था लेकिन केवल एक प्रतिशत ही पूरा हुआ है। यह भी आदिवासियों की अशांति और समस्या से जुड़ा हुआ सवाल है। इस बात को सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को देखना होगा। यह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक समस्या से जुड़ा प्रश्न है। आदिवासियों को विश्वास में लेकर ही हम इस दिशा में हम आगे आ सकते हैं। उनके लिए जो योजनाएं बनती हैं वे एयरकंडीशन कमरों में बैठकर बनती हैं, इसलिए वे योजनाएं फैल हो जाती हैं और उन योजनाओं का फायदा बिचौलिये उठा लेते हैं। तेलंगाना इलाके में आदिवासी अपने बच्चों को बेच रहे हैं, मार रहे हैं, इस पर सरकार को सोचना और ध्यान देना होगा। गरीब आदमी अपनी रोजी के लिए दूसरे शहरों में माइग्रेट करते हैं और वहां पर मिडिल मैन उनका और उनकी महिलाओं का शोाण करते हैं और महिलाएं कई प्रकार की दुर्घटनाओं और व्याधियों का शिकार हो जाती हैं और मर जाती हैं। रॉयल सीमा जैसी जगहों पर यह ज्यादा हो रहा है और इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। हमारी जो व्यवस्था है, नीति है और जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें गवर्नर को जो फिफ्थ शैड्यूल में पावर है कि माननीय राट्रपति जी उनसे डायरेक्ट डील कर सकते हैं। आदिवासियों की उन्नति के लिए जो कार्यक्रम हैं, अगर राज्य सरकारें उनको नजरअंदाज करती हैं तो वहां के राज्यपाल व्यवस्था ठीक करके, वहीं पर उन्हें सुविधा दे सकते हैं, यह प्रावधान है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री गणेश प्रसाद सिंह - उपस्थित नहीं।

DR. R. SENTHIL (DHARMAPURI): Hon. Chairman, Sir, on behalf of my Party – Pattali Makkal Katchi and the beloved founder leader, Dr. Ramadoss, I support the Motion of Thanks to the President's Address. As mentioned by the hon. Members, the President's Address has never been so good. It has comprehensively approached and addressed every sphere of developmental activity. It is a blue-print of the new Government for governance.

Tsunami had been a very big tragedy. The Government did extremely well with regard to handling the crisis. But there are a few things which I would like to say with regard to the disaster that hit our shores. Disaster was managed reasonably well. I went to the area affected by Tsunami immediately after the Tsunami struck the coast. What I found was, there were people from the Department of Revenue like Tehsildars, RDOs and even some clerks from the Collectorate. Were there any technical person present there who was exclusively trained for disaster management and rescue work? There were none. There was a miserable failure with regard to having a technically professional body to tackle any disaster. It was very surprising. When I went through the web, I found that there is a Disaster Management Team constituted under the leadership of the Collector and it was supposed to do the mock drills, etc. But I do not think that it had every happened and it was a failure. Let us admit that there was a failure in tackling a disaster. We do not have a technical disaster management team. We have disaster administrative team but we do not have a disaster management technical group. It is our duty to constitute such a team.

Our hon. President has congratulated the local people for taking immediate action at the time of disaster. They had been extremely helpful. I know this because I saw that local people have been of great help but what I found was that those

people were not trained in disaster management. They were unorganised. So, there was a lot of wastage of energy and resources. At the time of any disaster, the first responder is the local community. The Government proposes to have a Disaster Management Authority. It is a welcome step. But there are two things in that. One is the Disaster Management Authority. The Government is committed to a scientific approach. Therefore, the Disaster Management Authority must be headed by a scientific person and not by an IAS officer whose basic degree is something like an MA (History) or who had been working in the archaeological department for 10 years therefore he is made the Head of the Disaster Management Group. Disaster management is a science. Therefore, it must be headed by a scientist. Then, the disaster management must be cultivated to the common man because common man is the first one to respond to disaster and also it must be a curriculum in every school and college.

This Government has again and again stressed that it is committed to OBCs. As a representative of the OBC, I wholeheartedly believe that this Government will really do some good work for the OBCs. The Government had said that it will initiate a dialogue with the private industry owners for providing reservation for the Dalits. I would only request that the reservation for OBCs should be extended to private industries also. The private industries must be made to realise that when they are using the resources of the land, they should have some commitment to serve the people of the land at any cost.

With regard to the development of the rural areas, the Government proposes to introduce so many schemes. But I want to say that there are only two very important things that are essential for the development of rural areas and they are water and education. Of all the things, these are the most important things. The Government had mentioned about various schemes for promoting intensive crops and methods to conserve water. What I want to say is that there must be a National Ground Water Policy and the ground water must be nationalised. The ground water should be preserved at any cost. Likewise, nationalisation of the rivers should be done to prevent things such as what we saw in Tamil Nadu because of Cauvery. The Karnataka Government does not seem to heed to either the Supreme Court or the Tribunals or any other body. In this situation, we must seriously start a dialogue to nationalise all the rivers.

If water is provided to the rural areas, then the rural areas will automatically develop.

The second aspect is education. The *Sarvasiksha Abhiyan* scheme has been extremely helpful for rural education. Buildings have been put up. But at the end of the day, education is a State subject. Are the States really providing sufficient teachers? Are they really committed to the education of rural people? That is the moot question. In this regard I would like to request this UPA Government to commit themselves to rural education and provide financial assistance to the States in order to provide education to the rural poor.

Sir, the beauty of India lies in its unity in diversity. This has to be understood. In India we have hundreds of languages and thousands of cultural identities. That is the beauty of India. There was a time when there was a deliberate attempt to unify India by making one language and one religion for all. It was an attempt like in a class if there was one tall boy and one short boy, then chopping off the legs of the tall boy to bring about an uniformity. Such a deliberate attempt was made by some people. But now people of this country have very clearly said that they do not want such unity. They want unity in diversity. This environment of encouraging all cultures and all languages to flourish should be allowed to continue and this has to be done. Our hon. President has started this talk by citing a poem in Tamil. That is the spirit of the mother tongue. Everybody should be allowed to develop their own mother tongue. Tamil is one of the most beautiful languages in the world and is believed to be one of the most ancient languages as well. It has a history of more than 3000 years. It is a classic language and it should be given all the benefits of being a classic language.

Sir, rural health is a big priority of the Government. This Government has given a mission approach to rural health. This is a very welcome step. The hon. President in his Address has mentioned that this Government is committed to developing a scientific temper. He even mentioned that this is the hundredth birth anniversary of Albert Einstein who gave the world the theory of relativity and from this year we should make an attempt to make our administration scientific in its approach. I would like to request the Government to make the administration scientific in its outlook and approach.

Time has come when we should try and train our scientists to be managers rather than creating a set of managers who are anti-people and this gap between the bureaucrats and the technocrats should be bridged. Time also has come to introduce the Indian Medical Service where doctors could be trained for managerial tasks and they can be managers by themselves. Likewise, an All India Education Service should be introduced. They should be trained in a manner so that they could be able to make our administration scientific and sympathetic to the cause of the scientists. Such a step would help our Scientific Institutions to grow.

Sir, with these words, I once again support the Motion of Thanks on the President's Address.

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव) : मैं राट्रपति के अभिभााण में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उनमें तथ्यों का अभाव है । तथ्यों के साथ इधर-उधर की बातें उल्लिखित करके "वचनम् किम् दरित्रम्" बात यहां कही गई है । सुनामी त्रासदी के बारे में अभिभााण में उल्लेख किया गया है । पूरे देश में सुनामी तूफान में दिल खोल कर मदद की गई । देश में पिछले छः-सात साल से कई दलों की सरकारें रही हैं । आज तक इसके बारे में क्या उपाय किए जाएंगे, क्या प्रबंध किया जाएगा इन सारी बातों का उल्लेख हुआ है लेकिन इस दिशा में ठोस पहल सरकार द्वारा नहीं की गई है । सरकार ने जो घोाणाएं की, उनके द्वारा वर्ग विशेा को आकर्ति करते हुए वोट बैंक की दृटि से योजनाएं बनाई गईं । निश्चित रूप से इस समाज में वर्ग संर्घा पैदा होगा और यह एक सुनियोजित तरीके से किया कार्य है । सरकार ने अपने अभिभााण में महामहिम के माध्यम से इस बात का उल्लेख कराया है कि हम राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करेंगे । एक तरफ कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार राजनीति स्थायित्व प्रदान करने की बात कहती है,

दूसरी तरफ गोवा, झारखंड में प्रजातंत्र की हत्या करके सरकार द्वारा सारे देश को इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि हमारा प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है और हम पुराने इतिहास को दोहराने का काम करना चाहते हैं। जैसा आपातकाल में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। उसी तरह का कृत्य श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी घटनाओं को जन्म देने का काम किया जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। यह कहना कि हम राजनैतिक स्थायित्व देंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। कथनी और करनी में जिस तरह की असमानता को प्रदर्शित किया है, उसे न केवल यह देश बल्कि सारा विश्व देख रहा है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी और यू.पी.ए. की सरकार ने निर्लज्जता के साथ इस घटना को अंजाम दिया है।

19.41 hrs (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

यह शर्मनाक बात है। इस अभिभााण के माध्यम से राजनैतिक स्थायित्व की बात कहना 100 प्रतिशत बेईमानी है...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing to be recorded except the speech of Mr. Pradeep Gandhi.

*(Interruptions)**

श्री प्रदीप गांधी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्द्र सुनिश्चित करने का दावा किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 साल तक राज किया। उनके शासनकाल में केवल एक घटना को छोड़कर कुछ नहीं हुआ। अगर पिछले 40-45 साल का इतिहास उठाकर देख लिया जाये तो मालूम होगा कि देश में इतने साम्प्रदायिक दंगे हुये, उनका दोा किस सरकार पर है? इसलिये इस बात की चर्चा करना केवल एक वर्ग विशेा की तुटिकरण की राजनीति की ओर ले जाने का प्रयत्न है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यह कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की बात कही गई है। यह इस गठबंधन को समर्थन देने वाले एक दल विशेा के दबाव में किया गया कार्य है

* Not Recorded

जिसका ठोस परिणाम आने वाला नहीं है। सरकार उस दिशा में सकारात्मक प्रयत्न नहीं कर पा रही है। सरकार द्वारा एक मंत्रिमंडल समूह का गठन कर दिया गया है जो कार्यवाही कर रही है लेकिन उस दिशा में इसके द्वारा कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभााण के माध्यम से कीमतें स्थिर रखने की बात कही गई है...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Whatever he says is not to be recorded.

*(Interruptions)**

श्री प्रदीप गांधी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार उस दिशा में सकारात्मक कदम नहीं उठा पा रही है। सरकार कागज़ी घोड़े दौड़ा रही है। पिछले 9 महीने में देश के गरीब आदमी, झोंपड़ी में रहने वाले आदंमी से पूछे। यू.पी.ए. सरकार के समय में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और सरकार महामहिम के अभिभााण में इस बात का उल्लेख करके जो बात कह रही है, मैं उसके लिये स्पट करना चाहूंगा कि महंगाई पूरे देश में बढ़ी है। 150 पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज योजना शुरु की गई है। यह कार्यक्रम देश के अन्य पिछड़े जिलों में लागू किया जाना चाहिये। लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं राजनैतिक दृटिकोण से सोची गई बात का स्मरण आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पोटा कानून को खत्म करने की बात कही गई है। इस कानून को समाप्त करने का जो तर्क दिया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। जब आतंक वादियों से निपटने के लिये पर्याप्त कानून व्यवस्था थी तो विधि विरुद्ध क्रिया-क्लाप अधिनियम, 1967 में संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब यह है कि सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राट्रमंडल खेलों का उल्लेख किया गया है। सन् 2010 में राट्रमंडल खेलों और सन् 2018 के लिये ओलम्पिक खेलों की दावेदारी प्रस्तुत करना कोई नई बात नहीं है। इसका उल्लेख पूर्व सरकारें करती रही हैं, इसका निर्णय पूर्व सरकार ने किया है और यह उनकी देन है। इन बातों का उल्लेख करके सरकार क्या दिखाना चाहती है, इससे कोई स्पट बात परिलक्षित नहीं होती है।...(व्यवधान)

* Not Recorded

SHRI C. KUPPUSAMI : Sir, he is misleading the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. Please sit down.

श्री प्रदीप गांधी : महोदय, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार ने जिन बातों का उल्लेख इसके माध्यम से किया है, उनमें भारत निर्माण जैसे बड़े नाम का भी उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी प्राथमिकताओं को नये नाम से प्रस्तुत करना, जैसे भारत निर्माण की बात का उल्लेख किया गया है, इस तरह से पुरानी बोतल में नई शराब भरकर प्रस्तुत करने से इस देश की जनता यू.पी.ए. सरकार पर कोई भरोसा करने वाली नहीं है। जिन बातों का उल्लेख इस दस्तावेज के माध्यम से किया गया है, इसमें कहीं न कहीं, उस दल के लोग जो सरकार में बैठे हैं, उनके दृटिकोण में छिपा हुआ एजेंडा परिलक्षित होता है। मैं इस बात का उल्लेख आपद्वके माध्यम से करना चाहता हूं कि बिहार को एक विशेा पैकेज देने की बात कही गई है। आपको स्मरण है कि छत्तीसगढ़ सहित तीन राज्यों का निर्माण आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। तीन राज्यों के निर्माण के पीछे उद्देश्य भी यही था कि उन राज्यों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था। पूरे देश की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य का 44 प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित क्षे है। वहां पर 32 प्रतिशत आदिवासी हैं। 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। वहां की 44 प्रतिशत आबादी हरिजन और आदिवासियों की है। वहां पर तीव्र गति से औद्योगीकरण हो, इसके लिए सरकार ने एक संकल्प पास किया और उसके लिए विशेा पैकेज देने की बात की। उत्तरांचल को विशेा पैकेज देने की बात की। देश के अंदर जिन नये राज्यों का निर्माण हुआ, उन नये राज्यों की भौगोलिक सीमा को देखते हुए, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए, वहां की जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों की बहुलता को देखते हुए केन्द्र सरकार यदि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या उस सरकार के साथ अलग व्यवहार करेगी और दूसरी जगह पर दूसरी सरकार है तो क्या उसके साथ अलग व्यवहार करेगी। केन्द्र में बैठी हुई सरकार को इस नीति पर चलने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए, वहां के लोगों को भी विकास के समान अवसर देने चाहिए। जिस तरह से उत्तरांचल में छूट दी गई है, वहां के उद्योगों को भी वैसी छूट देनी चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा समवेत रूप से सभी तरह के लोगों ने जो संकल्प पारित करके केन्द्र को भेजा है, उस संकल्प में सभी राजनीतिक दलों की इच्छाशक्ति का समावेश है। उसमें कोई कांग्रेस पार्टी या बी.जे.पी. नहीं है। उसका समवेत रूप से इच्छाशक्ति के द्वारा जो संकल्प यहां आया है, उस दिशा में केन्द्र की गठबंधन सरकार को नीति का पालन करना चाहिए और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य को विकास की श्रेणी में आगे बढ़ाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राट्रपति जी का जो अभिभााण सरकार के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसमें बहुत सी बातों का उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रबल रुप से विरोध करता हूं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे इसके जम्हूरिया के खुतबा पर बोलने का मौका दिया। मुझसे पहले सुबह से बहुत ही तजुर्बेकार और सीनियर मौअजिज मैम्बरान ने सदर जम्हूरिया के खुतबा पर अपने-अपने ख्यालात का इजहार किया है और जो खुतबा 24 सफात पर मुश्तमिल है, इसमें 73 नुकात को शामिल किया गया है। मैं इसकी ताइद करूं और सारे तबकाजात, हर सैक्टर और सारे मजमुईं तौर पर सारे भारतर्वा की जो तस्वीर बांधी गई है कि जो हमारी मौजूदा यू.पी.ए. सरकार आने वाले 2005-2006 में क्या करने जा रही है, इसका जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं अपनी तकरीर को भी रवायती तकरीर में शामिल करूं, मैं अपने लोगों और देश के लोगों से ज्यादती करूंगा, अगर मैं उलझ जाऊं, उस तरफ बैठे हुए मौअजिज मैम्बरान इस हाउस में जो सुबह से तकरीरें कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी सियाती बातें इस तरफ इशारे करके भी की हैं, जिनका जवाब देना मेरे लिए लाजिमी बनता है।

मुझे फ़ख है कि मैं एक ऐसी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिपाही हूँ जिसकी कयादत हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महरूम श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जैसे नेताओं ने की है और उन नेताओं ने इस मुल्क को सालों साल की जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया और आज से 56 बरस पहले आज़ादी हासिल करने के बाद इस देश के निर्माण और तरक्की के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से शुरूआत की। हमारे उस तरफ के कुछ साथी कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश पर 45 साल हुकूमत की। यह हमारी खुशकिस्मती है कि इस देश के गरीब अवाम 45 सालों के बाद आपके चंगुल और बहकावे में आए और उन्होंने एक परिवर्तन लाकर आपको पिछले आठ सालों के लिए मौका दे दिया। यह दुरुस्त बात है कि जो काम करता है, उससे गलतियां भी होती हैं। 45 साल एक उम्र होती है और एक पार्टी ने 45 साल इस देश पर हुकूमत की जिस देश की आबादी आज 100 करोड़ से भी ज्यादा है, जिस देश के मुख्तलिफ हिस्सों में इतनी रियासतें हैं, जिस देश में बसने वाले लोगों का न खाना-पीना मिलता है, न भाा मिलती है, न रंग मिलता है और न कपड़े पहनने का ढंग मिलता है। इस देश की यकजहती सलामती को कायम रखना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे विरोधियों के फिरकेवाराना भाण और तकरीरें हैं जो इस देश के अमन और इस देश की यकजहती सलामती और धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने वाली हैं, उनसे मुकाबला करने का आफ़रीन कांग्रेस पार्टी को है जिसकी तरफ ये अंगुलियाँ उठाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग हम पर अंगुलियां उठाते हैं, क्या जंगे-आज़ादी में उस तरफ बैठे हुए लोगों का कोई रोल है? कोई ऐसा नेता है जिसका नाम ये उठकर ले सकते हैं, चाहे उस वक्त की प्रजा परिद् हो, जनसंघ हो या आज की भारतीय जनता पार्टी हो, जिसका एक नेता भी हो जिसने इस देश की जंगे-आज़ादी के लिए कोई कुर्बानी दी है। हम उसमें नहीं जाना चाहते कि किसने जंगे आज़ादी लड़ी और देश को आज़ाद करवाया या किसने मुखबिरी का काम किया। मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता, मेरे साथी उमड़ पड़ेंगे। लेकिन यह बात कैसे भूल सकते हैं कि जिस पार्टी ने इतना कुछ इस देश के लिए किया और जिस परिवार ने एक के बाद एक कुर्बानी इस देश की यकजहती सलामती के लिए दी हो और आज उनके ऊपर आप अंगुलियां उठाते हैं और बातें करते हैं। आज सुबह ही मेरे मुअज्जिज़ मैम्बर और इस हाउस के बहुत सीनियर मैम्बर, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मैं उनकी तकरीर सुनने के लिए बैठा था। कोई वक्त था हमारे जार्ज साहब दो घंटे तकरीर करते थे। देश में बहुत सारे लोग उनको सुनने के इच्छुक होते थे और सारे लोग अच्छे ओरेटर नहीं होते हैं, लफ्ज़-बा-लफ्ज़ बात नहीं कर सकते लेकिन वह करते थे। लेकिन आज

वह क्या कह गए, मुझे दुख हुआ। उम्र का तकाज़ा भी हो सकता है। मेरा भी हो सकता है, उम्र का लिहाज भी है, तजुर्बे की कमी भी है। लेकिन उन्होंने कहा और अभी एक साथी कह रहे थे कि आज इस देश की यूपीए सरकार सोनिया गांधी के मशविरे के बगैर नहीं चलती। आप यह कैसे भूल सकते हैं, आपने भी तो 26 पार्टियों की मिली-जुली सरकार इस देश में पिछले सालों में चलाई और इस देश के लोगों के सामने आपकी करनी भी है। आज हमें भी फ्रैक्चर्ड मैनडेट मिला, मेजारिटी नहीं मिली तो सारी पार्टियों के नेताओं ने हमारी काबिल सोनिया गांधी को यूपीए का प्रधान चुना।

आज इस देश के गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दूर दराज के इलाकों के लिए, पिछड़ी हुई रियासतों के लिए, दबे कुचले तबके के लोगों के लिए, चाहे ये सरकार का मुर्तब किया गया खुतबा है । बजट भी ऐसा होता है, उसमें राय देना, आप भी तो मेनिफेस्टो से लोगों से वायदा करके आए हो, हम भी आए हैं लेकिन मुझे फक्र होता है आप अगर अपना जवाब भी देंगे उसके बाद भी मुझे कह देंगे कि कांग्रेस पार्टी कभी इलाके के नाम पर, भााा के नाम पर, मजहब के नाम से, मंदिर और मस्जिद के नाम पर पिछले 56 सालों से वोट नहीं मांगे हैं । बता दीजिए सारा चिनमंसूक हमारी कांग्रेस का, कोई भी चुनाव मेनिफेस्टो आप बता दीजिए ।...(व्यवधान)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Interruptions not to be recorded. Please take your seat.

...(Interruptions)

* Not Recorded

श्री मदन लाल शर्मा : मैं रियासते इलाकाई सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं । मैं मरकजी सरकार, जो सारे देश पर हुकूमत करती है उसकी बात कह रहा हूं । इलाकाई सरकारें क्या कहती हैं । कौन से मुद्दे ले कर लोगों के जज्बात भड़का कर क्या वायदे करके वह बरसर इक्तिदार आती है, वह आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है । मैं कह रहा हूं कि इस देश की सरकार बनाने में कभी कांग्रेस ने किसी को मजहब के नाम पर, भााा के वास्ते, मंदिर के वास्ते, मस्जिद के वास्ते कोई ऐसी बात कह कर वोट नहीं मांगे, चाहे वह इक्तिदार में आए या नहीं । मैं तो जम्मू-कशमीर राज्य से ताल्लुक रखता हूं। उसका मैंने जिक्र नहीं किया । भारतीय जनता पार्टी के वरिठ नेता होते, रियासतों में भी इन्होंने हुकूमतों में हिस्सा लिया होगा । मुझे भी 25 साल का अनुभव है लेकिन मोअज्जिज ऐवान में आपकी बसासत से मुझे पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है इसलिए मैं बहुत सारी बातें कहना चाहूंगा । अगर मुझे आधा घंटा मिल जाता, तो मैं इनकी सारी पोल खोल देता । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा हमने कभी नहीं किया है और न ही ऐसी बातें कही हैं । इस सदरे जमुरिया के खुतबे के अंदर क्या-क्या किया गया है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken more than 15 minutes.

श्री मदन लाल शर्मा : मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इनकी ज्यादा बातें करुंगा तो ये बोलते जाएंगे और मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा । मुझे दो-तीन बातें इस खुतबे में कमी लगती हैं । मैं राट्रपति साहब का मशकूर हूं । राट्रपति साहब ने इस खुतबे के अंदर साबका फौजियों के तबके का जिक्र किया है । उनके लिए अलग महकमे डिफेंस के अंदर बनाने का वायदा किया गया है । उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि साबका फौजी जो अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस मुल्क की खातिर दे कर आते हैं और अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं लेकिन जब वह 35-40 साल की उम्र के बाद वापिस आते हैं तो उनका रिहेब्लिटेशन दोबारा नहीं होता और मैं समझता हूं कि सारे देश के साबका फौजियों को गौरव होना चाहिए कि हमारी यूपीए सरकार ने उनके लिए आदर और मान रखा है और उनके लिए अलग महकमा बनाने का जो अहद कया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। इसी तरह मेरे माननीय सहयोगी चौधरी लाल सिंह ने 1947 के रिफ्यूजियों की बात कही है । एक बात जरूर है कि मैं रूलिंग पार्टी बरसर इक्तिदार पार्टी से ताल्लुक रखता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up your speech now.

श्री मदन लाल शर्मा : मैंने 1947 के रिफ्यूजियों का जिक्र नहीं किया है जो 56 वाॉं से पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में रहते हैं । उनको आज तक वे हकूक नहीं मिले जो देश के बाकी हिस्सों में रहते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को उनका इस मसले को भी अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए।

20.00 hrs.

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं लास्ट बात कहकर आपसे रुखसत चाहूंगा। आज हमारे मुल्क की गुजरात से लेकर करगिल तक सरहदें पाकिस्तान से लगती हैं। हमारे देश का सैकड़ों किलोमीटर बार्डर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है और लाखों की संख्या में हमारे लोग बिना वर्दी के सरहदों पर बसते हैं। उन्हें हर पांच-सात साल के बाद पाकिस्तान की गोलियों से दो-चार होना पड़ता है। सरहद छोड़कर भागना पड़ता है। अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ता है। हमारे बहुत सारे साथी जम्मू-कश्मीर में रिफ्यूजी कैम्पों में रह रहे हैं। पाकिस्तान से ताल्लुकात सुधर रहे हैं, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू हो रही है और आर.एस.पुरा से सुचेतगढ़ बस सेवा भी जल्दी ही चालू होने वाली है। हमारे एम्बैसेडर भी एक-दूसरे के मुल्क में पहुंच गए हैं, लेकिन सरहदों पर रहने वाले जिन लोगों को पाकिस्तान की गोलियों से दो-चार होना पड़ता है, जिन्हें वहां से भागना पड़ता है, उनकी रीहैबिलिटेशन का बन्दोबस्त करने की अभी तक सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं हुई है। मेरी इल्तिजा है कि उनका बन्दोबस्त हमारी सरकार को करना चाहिए। अन्त में, मैं सदरे जम्हूरियत के इस खुतबे का तहेदिल से सपोर्ट करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : शर्मा जी, आपने अभी अपने भााण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी या पुरानी पार्टी, भारतीय जनसंघ का कोई एक ऐसा नेता बता दें, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। मैं बताना चाहता हूं कि राट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक स्वयंसेवकों ने जम्म-कश्मीर की लड़ाई लड़ी। क्या आप उससे इंकार कर सकते हैं । .....(व्यवधान) **उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हé ? SHRI BIJOY HANQUE: Sir, I would like

to announce that dinner is now ready. I would request all the hon. Members to come. Sir, I would request you also, and the members of the Press and staff also to come.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास अभी 17-18 बोलने वाले मैम्बर्स की लिस्ट है। जैसे अभी तक भाणों में समय लिया जाता रहा और अपनी मर्जी के हिसाब से बोलते रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि रात के 12 बजेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रत्येक ऑनरेबल मैम्बर, पांच-पांच मिनट में अपनी स्पीच समाप्त करें।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई आप बोलिए। Please wind up your speech within five minutes.

*SHRI A. RAVICHANDRAN SIPPIPARAI (SIVAKASI): Hon. Deputy Speaker Sir, encompassing priorities like welfare of the farmers, boost to rural development, creating job opportunities, providing for public health and establishing the rights of the oppressed sections of the society, our President of India spelt out the UPA Government's plan of action in the Central Hall of Parliament interspersed with his poetic expressions in Tamil tinged with concern for the downtrodden masses. I welcome wholeheartedly on my behalf and on behalf of my party Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam and especially on behalf of our beloved leader Vaiko and thank H.E. the President of India and support the Motion of Thanks to the President for his Address to the members of the Parliament.

When tsunami tragedy engulfed the nation hitting hard our southern coastal areas, when thousands of people lost their lives, when hundreds of thousands of fishermen lost their property and livelihood, we witnessed a solidarity among all the people of this country rushing a helping hand to the affected people. The nation stood as one man behind the aggrieved people.

I only express my wish that such a deep sense of brotherhood and camaraderie is there in all of us in resolving several issues like inter-state river disputes pending for long in many parts of the country affecting our people in many ways. Agriculture is the basis of our economy with 60% of the people depending on agriculture as their occupation and livelihood. But their future appears to be bleak. As far as Tamil Nadu is concerned the disbursement of loan through co-op societies have been stopped forthwith. They have been showing on records as though new loans have been disbursed. But in reality, the existing debts

are adjusted against the new disbursements. So in effect there is no loan available

---

*Translation of the speech originally delivered in Tamil.

to be spent on cultivation. In Tamil Nadu the rural co-op societies are being choked to death. They are dying slowly. In Tamil Nadu the public sector banks are extending loans to the farmers as jewel mortgage loans though they are shown in their accounts as agricultural loans. This must be looked into and it must be ensured that the required loans for agricultural activities must reach the needy farmers in time.

Sir, at this juncture I would like to lay stress on agricultural research. There must be an effort to get on a time bound basis the research report from all the organisations. New strides have not been made in agriculture for many years now due to inadequate extension of research developments in the field. Such research reports must come before this House and effective method should be evolved to discuss them here in the House because agriculture development is necessary. Sir, in our President's Address it has been stated that in the next 5 years 2% of our GDP would be allocated to public health. I urge upon the Government to take care of the physically and mentally challenged people who are left to fend for themselves. Cancer, heart ailments, kidney failures are some of the dangerous terminal ills that afflict our society. Many in India especially in Tamil Nadu could not get adequate medical assistance due to heavy expenditure involved. Financial assistance that was coming to such patients from the PM's Relief Fund was a solacing one. But recently it is seen that number of such recommendations from the Members of Parliament to the Prime Minister's office are kept pending. May be the requests are on the increase. Some request have also been turned down. I urge upon the Government to make viable arrangements to ensure that all such deserving cases are extended with financial assistance from the PM's Relief Fund. It has been estimated that there are about ten thousand handicapped people in our Sivakasi constituency. Of them more than a thousand people have got surgical treatment while many of them have been given medical consultancy and needed treatment and good many of them have got necessary equipments needed by the physically challenged. Single handedly our leader Vaiko take efforts to arrange rehabilitation camps for them to bring about a revival in the lives of such hapless people.

When we deal with a Budget for more than 5 lakh crores of rupees, we must ensure that our deserving handicapped people get a better deal and proper care. Our Government must carefully monitor whether 3% reservation is available to our

physically challenged brethren.

In order to forge an alliance through a clandestine relationship for political motives, the erstwhile rulers here were turning a Nelson's eye to the actions taken by the present rulers of Tamil Nadu who went about misusing POTA to confine our leaders Vaiko for more than 550 days in prison. It is another matter that they had political set back as retribution to their double standards and that is why they find themselves on the other side of the House now. They were washed out in Tamil Nadu and they are in the opposition now. This is the lesson we obtain from history and this is how the ungrateful ones are dealt with.

I urge upon the Union Government to have proper watch on crores of rupees spent on employment generation programme. For instance the funds allocated for paying manual labour under 'food for work' scheme is spent on machines. That way the deserving poor labour could not get what is due to them. we must ensure that underdeveloped rural areas with people below poverty line must be gainfully employed to stir up the minimum required economic activity there. Such funds must reach rural labour as rightful wages. This Government accords priority to higher education. I would like to urge upon the Government that primary education in rural areas also must get the same priority or even much more.

Now we have a Government that has people and their welfare as a foremost thing in its action plan. We have a scientist at the helm of affairs as our President. We have a renowned economist as our Prime Minister. Under their able stewardship our country marches ahead towards a bright future. Hence I reiterate my support to the Motion of Thanks to the President for his Address to the Parliament.

With this, I conclude my speech.

*SHRI M. SHIVANNA (CHAMARAJANAGAR): Mr Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks to the hon. President of India. The President addressed the Joint Session of the Parliament and expressed his concern over 73 important items including the ghastly tragedy, tsunami. He expressed his views for one and a half hour while giving importance to relief measures taken up by the Centre.

The hon. President was kind enough to mention about reservation of vacancies to the SC and ST in private organisations. In fact, the Centre is keen to pass a Bill in the Parliament to provide reservation to the SC and ST in private organisations and I thank the President for this.

Panchayati Raj is functioning successfully throughout the country. Panchayat institutions have been given freedom and funds worth lakhs of rupees are being allocated to perform their duties.

I urge upon the Centre to give priority to the problems of farmers. They are committing suicide especially in my State, Karnataka. They have various problems related to sprinkling irrigation, marketing facilities etc. Agriculture is the backbone of India's economy and about 70% of our population are farmers.

Karnataka Government has an ambitious programme of providing midday meals to the school students studying upto 10^{th} standard. So far, this facility was available to students who are studying in class upto 5^{th} standard. Therefore, Karnataka Government has urged the Centre to increase its contribution to provide

---

*Tanslation of speech originally delivered in Kannada.

midday meals to school students. The present ratio of contribution between Centre and State is 50:50. Karnataka has already approached the Planning Commisison to this ratio as 85:15 in favour of the Centre. I hope the Centre will come forward to help my State.

Sir, for the first time ISRO is involving the students of 800 school to impart education through satellite. I am proud to mention this educational programme has started in my constituency, Chamarajanagar. A number of classes were held by ISRO during the first week of March 2005. I request the Centre to adopt this method to educate the children throughout the country.

The Ministry of Social Justice and Empowerment is helping the patients who are suffering from various diseases like cancer, kidney problems, etc. About 75% of the treatment expenditure is provided by this Ministry through Dr Ambedkar Foundation which has its office in New Delhi. Unfortunately under this scheme only 9 States are eligible for this financial

benefit. I request the hon. Prime Minister to intervene in this matter and to include all the States such that there will be no discrimination among States.

Karnataka is reeling under severe drought for the last 4 years. There are no rivers in my constituency. There are no irrigational facilities. Hence my humble request to the Centre is to link major rivers of our country. That is the only and ultimate solution for the problems of our farmers.

Nusi and Rootwilt are the diseases which have destroyed lakhs of coconut trees in Karnataka. Removal of these disease infected trees is another problem of farmers. The coconut grower gets a meagre Rs 25 to cut such trees. There should be a package for the coconut growers such that they can come out of this crisis.

Another major problem of the farmers of Karnataka is lack of marketing facilities for the agricultural produce. At present tomato growers are throwing tomatoes on the roads as there are no takers. It is being sold at Rs 2 per kg. Therefore, I request the hon. Minister of Agriculture to provide at least one cold storage to each district in Karnataka and save the lives of poor farmers.

Sir, I thank you once again and with these words, I conclude my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ganesh Singh, you may speak for five minutes only. You have to give suggestions only.

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैंने राट्रपति जी के अभिभाण में संशोधन हेतु सूची संख्या 24 में 517 से लेकर 533 तक जो संशोधन पेश किए हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें स्वीकार किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आज पूरे देश में विकास की असमानता के चलते दो तरह का भारत दिखाई दे रहा है। एक भारत जो शहरी क्षेत्र में है और दूसरा भारत ग्रामीण क्षेत्र में है। आज़ादी के 56 साल बीत जाने के बाद भी 60 प्रतिशत से भी अधिक ऐसे लोग हैं जिनको बुनियादी सुविधाओं के साथ आज तक नहीं जोड़ा जा सका है। योजनाएं बहुत बनी हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को आज तक नहीं मिल पायी है। इसी को आधार मानकर के राट्रपति जी ने यदि यूपीए सरकार का तैयार किया हुआ भाण पेश किया होता तो निश्चित रूप से हम लोगों को धन्यवाद देने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज यह कहा जा सकता है इस देश में जो विकास की असमानता है, यदि इसको हम इसी रफ्तार से चलाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि यह देश कहीं बंट न जाए। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग एक-एक बूँद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम सभी लोगों को पानी मुहैया नहीं करा सके हैं। बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि आज देश का नौजवान दिशाहीन हो चुका है ओर उसके सामने कोई कार्यक्रम नहीं है। किसान दिन-रात मेहनत करता है लेकिन उसे दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। स्थिति यहाँ तक पैदा हो चुकी है कि जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके बच्चों को कफ़न का कपड़ा उधार लेकर के उसको दफनाने का काम करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में देश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। कौन से ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से हम इस समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं? करोड़ों-अरबों का हर साल बजट तैयार हो रहा है। जिन्होंने यह देश बनाया, जिनके चलते यह देश पहचान में आया, आज हम उन्हीं की मदद नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत चिन्ता का विाय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के दृटिकोण से कोई भी देश बिना शिक्षा के मज़बूत नहीं हो सकता। लेकिन आज हमारे यहाँ जो शिक्षा है, उसमें व्यापक असमानताएं हैं। आज की शिक्षा ने इस देश को ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर दिया है, जिससे अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। आज तक हम लोग इस पर राट्रीय स्तर पर बहस नहीं कर सके। यदि हम एक निश्चित कार्यक्रम चलाकर देश में समान शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, जो आज के लिए बहुत जरूरी है, यदि उस शिक्षा पर बहस नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम बनाने का कोई औचित्य नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास का काम चल रहा है। यहाँ पर कहा गया कि हम 365 दिन में से सौ दिन का रोज़गार देंगे । मैं कहना चाहता हूँ कि वह रोज़गार नहीं, वह मजदूरी है। पढ़े-लिखे नौजवान से यदि हम कहें कि आप जाकर के सौ दिन के काम में अपना रोजगार चला लें, तो वह कभी नहीं जाएगा। मजदूरी करने वाले लोग जा सकते हैं। काम के बदले अनाज में कौन सा नौजवान काम कर सकता है? हम इस को रोजगार नहीं कह सकते।

मैं कहना चाहता हूं कि यह देश के बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज सरकारी सैक्टर में, प्राईवेट सैक्टर में सब जगह नौकरियों में प्रतिबंध लगा हुआ है, कहीं कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में नौजवान कहां जाएं। शहरों में थोड़ा-बहुत काम मिल भी जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा रहता है, नौजवानों से पूछा जाए कि उनके सामने क्या स्थिति है। आज उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय रोजगार के मामले में प्रशिक्षण देने का काम नहीं कर सकता? क्या वहां ऐसे कार्यक्रमों को लाने में दिक्कत हो रही है कि हम गांव-गांव में तकनीकी प्रशिक्षण दें, लोगों को स्व-रोजगार की ओर प्रेरित करें और लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, कृाि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करेंगे? उस दृटिकोण पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? आजादी का इतना लम्बा समय बीत गया, 40-42 साल तक देश में कांग्रेस का राज रहा लेकिन फिर भी सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ रहा हैं। हम 40-42 सालों में देश को कहां ले जा सकते थे। लेकिन हम देश को सही दिशा में नहीं ले गए। जब वाजपेयी जी एनडीए सरकार चला रहे थे तो उन्होंने कई समयबद्ध कार्यक्रम दिए थे। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि सन् 2007 तक हम देश के प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ देंगे। सन् 2005 - 2006 के लिए उन्होंने कहा था कि एक-एक गांव को शुद्ध पेयजल के साथ व्यवस्थित कर देंगे। लेकिन आज इस सरकार के सामने कोई समयबद्ध कार्यक्रम क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि दृटिकोण ठीक नहीं है। हम इस देश को कितने दिन धोखे में रखेंगे? इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है। अगर हम इसे सही दिशा नहीं दे सकते, सही कार्यक्रम के साथ नहीं जोड़ सकते तो लोगों के मन में निराशा बढ़ेगी। श्री वाजपेयी की सरकार में लोगों में विश्वास का वातावरण बना था। लेकिन आज हम फिर निराशा की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। बड़ी तेज गति से लोगों में फिर निराशा आई है क्योंकि ऐसा लगता है कि

सरकार हमारी मनोभावनाओं को पूरा नहीं कर पा रही तथा, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रही। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसे कार्यक्रम हाथ में लेने चाहिए और इस देश के लोगों, जो निराशा के द्वार पर खड़े हैं, उन्हें बाहर निकालने की तैयारी करनी चाहिए।

राट्रपति जी के अभिभााण में सामाजिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय कैसे होगा? जिस देश की आबादी का 52 फीसदी हिस्सा पिछड़ी जातियों का हो और उसे हर कार्यक्रम से अलग रखा जाए, चाहे महिलाओं के आरक्षण का प्रश्न हो, चाहे निजी क्षेत्र में सर्विस देने के लिए आरक्षण का प्रश्न हो, तो उसका िवकास कैसे होगा। सामाजिक न्याय तभी होगा जब 52 फीसदी लोगों को उसमें शामिल किया जाए, चाहे महिलाओं के आरक्षण के विाय में हो, चाहे निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का विाय हो।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के मामले में हमारे लोक सभा क्षेत्र में एक प्रकल्प शुरू हुआ है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी हमारे नेता हैं। उनकी कल्पना थी कि गांवों को समृद्ध बनाएं, गांवों को आत्मनिर्भर बनाएं, गांवों को स्वाभिमानी बनाएं। गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, गांव का पैसा गांव में रहेगा। ऐसी योजना इस सरकार ने अपने कार्यक्रम में नहीं दियें । क्यों?

श्री नानाजी देशमुख बहुत बड़े समाजसेवी हैं। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से चित्रकूट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में दो साल से काम शुरू किया है। उन्होंने दो साल में उस संस्थान को इस स्थिति में ला दिया है कि आज वहां 80 गांवों में एक भी व्यक्ति काम की तलाश में गांव नहीं छोड़ रहा है। गांव का एक-एक आदमी काम पर लगा हुआ है। जिन खेतों में दो फसल नहीं होती थी, वहां आज दो फसलें हो रही हैं। सिंचाई के साधन बढ़ गए हैं। वहां अब कोई घर ऐसा नहीं है जहां हाथ में रोजगार नहीं हो। पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में, गांव का पैसा गांव में, गांव में प्रत्येक परिवार के बैंकों में खाते खुल गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई निजी संस्था चलाने वाला व्यक्ति संकल्प ले के देश के कुछ गांवों को एक माडल के रूप में खड़ा कर सकता है, तो क्या हम उसे माडल मानकर उसी आधार पर समयबद्ध कार्यक्रम नहीं चला सकते? हम तय कर सकते हैं कि दस साल में इस देश को यहां ले जाएंगे। आज इस देश के 40 फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यह अलग बात है कि हम 29 करोड़ परिवार कह रहे हैं, लेकिन यदि उनका वास्तविक सर्वे करवाया जाए तो 40 फीसदी से ज्यादा लोग हैं। हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। हमें चिन्ता करनी चाहिए। हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, हमें इसकी चिन्ता करनी चाहिए। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमें इसकी चिन्ता करनी चाहिए। हमें इस बात की चिन्ता करनी चाहिए कि गांवों में स्कूल या अस्पताल नहीं हैं। गांवों में अभी तक टेलीफोन की व्यवस्था पूरी तरह नहीं हैं। शहरों में मोबाइल चल रहे हैं लेकिन गांव का आदमी आज भी 40 किलोमीटर दूर जाकर टेलीफोन कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि मोबाइल सैट आ गए लेकिन उनके सिगनल्स कहां गायब हो गए। ऐसा लगने लगा है कि बीएसएनएल का फुल फार्म "भीतर से नहीं लगता " है। आज यह स्थिति हो गई है। बीएसएनएल क्यों नहीं लगाता? मुझे लगता है कि निजी कम्पनियों के साथ कुछ सांठ-गांठ हो चुकी है ताकि बीएसएनएल फेल हो जाये और निजी कम्पनियां का एकछत्र राज्य पूरे देश में हो जाये। मै कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में जो वातावरण बना हुआ है, वह वातावरण किस दिशा में हमें ले जा रहा है ? मैं चाहता हूं कि यूपीए सरकार एक समयबद्ध निश्चित कार्यक्रम दे जिसमें इनका भी और इस देश का भी भला है। हम लोगों ने अपने समय में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चलाये थे, उन् कार्यक्रमों में गति देने की जरूरत है, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इससे आने वाले 10-15 साल में एक अच्छा भारत बन सकता है। जिस भारत के निर्माण की ये बात कर रहे हैं, वह तो दिशा-हीनता का भारत है। लेकिन जिस भारत का निर्माण करने के लिए एनडीए सरकार ने प्रस्ताव दिया था, उसी में असली भारत बनने का काम हो सकता है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*m34

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am extremely grateful for allowing me to speak on the Motion of Thanks to His Excellency the President of India for his Address to Parliament.

Examining the Address, one finds that the Address bridges the agrarian economy with the knowledge economy, and the aspirations of the hon. Members on the other side, which he has just illustrated. If we read the hon. President's Address, we would find that his aspiration have been addressed in the Address of the President of India.

The Address is visionary, is foresightful, is optimistic and is outcome-driven, and that is the beauty of the Address of the President of India. The Address links a new vision of rural India bridging the divides that have ridden the social order and it is this element of the Address of the President that is particularly significant.

I would like to take this opportunity to thank the UPA Government and the Prime Minister in particular for the manner in which the nation has been linked to one common striving consequent to the tragedies that took place in the South of the nation and in Kashmir. Never before has the nation exhibited one common commitment to a common striving so as to alleviate the hardships of the people of this nation. We have all contributed to the welfare that we want this nation to have. And it is the leadership of the hon. Prime Minister that has made this possible.

I would also like to mention that there is a new kind of politics that the Address of the hon. President of India defines: It is the politics of inclusion. Never before has the President of India spoken of the politics of inclusion -- the politics of integrating people to a common striving for togetherness, for participation on a common platform. He has very succinctly outlined that it is pluralism, diversity, flexibility and secularism that is going to make this nation move forward consequent to equity and social justice.

Never before has the President's Address outlined with such clarity the platform that the minorities, Schedules Castes and Scheduled Tribes would like to have as components of the common participative platform. Belonging to a minority

community myself, I would like to emphasize that participation is what all sections of the nation need in order to define that nationhood that we had envisioned when we had our 'Tryst with Destiny'.

It is this new paradigm of the nation we want to have that the Address of the President defines with such clarity and with such succinct boldness that we now require.

It is said in the Address that we would like all people to participate. It says that we would like a caring and sharing mechanism to operate in this nation. For this very purposeful intent, I would particularly like to thank His Excellency the President for his Address.

There is one more area, Mr. Deputy-Speaker, Sir, that I would like to particularly focus on. The kind of vision that the nation would like to have for the education of children of this country is of very great significance in the Address of His Excellency.

There is talk of social upliftment of Scheduled Tribes, Scheduled Castes and the *Dalits.* There is talk that the Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas would be located in those areas where normally there is no access for quality educational participation. This is an extremely important element of enabling the girl child in our country to raise the participation level above the present prevalent percentage of nearly 23.

I would also like to mention that there is a beginning to define, what the President called, the "National Knowledge Commission" which is proposed to be established. This is again an extremely important step and it is consequent to this that we will be able to see the benefits for the nation that we would like to have.

I would also like to endorse the agenda for 'Modernisation" that has been stated in the Address of His Excellency. A new code for governance is proposed. There is also a new facet of involvement in upgradation of the Armed Forces, an Administrative Reforms Commission is suggested. There is also the important dimension of public-private partnerships in promoting the goodness of this country.

These are extremely important elements to enhance the success-oriented nationhood developmental platforms.

Having said this, Mr. Deputy-Speaker, Sir, let me mention that we are extremely upbeat with this Address. We would like to say a great thank you to his Excellency.

With these words, I would like to support the Motion of Thanks to the President.

*SHRI HITEN BERMAN (COOCH BEHAR): Hon. Deputy Speaker Sir, I rise to support the Presidential Address on behalf of my party All India Forward Bloc. Through you Sir, I would like to draw the attention of the UPA Government towards certain issues. In the Common Minimum Programme of the Government, it was said that there would be uniform development in the entire country. I would like to mention that there is an area which is highly underdeveloped – it is the northern part of West Bengal. In 6 districts of North Bengal approximately 2 crores of people live. But in this year's Budget speech, North Bengal has been totally overlooked. Sir, the entire stretch of North Bengal is surrounded by three neighbouring countries viz. Nepal, Bhutan and Bangladesh. People in this part of the State mostly belong to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. Even after 57 years of independence, there is no adequate irrigation facility in the area. The Teesta Irrigation Project is still pending and the Budget has not mentioned it. Agro-based industries have not developed properly. There is an acute problem of unemployment among the educated youths. Thus they are easily attracted towards various terrorist organisations like the Maoist groups, KLO, Bodo outfits, etc. Soil erosion and flood are the two major problems of this part of the State. Most of the rivers have originated from Bhutan. To check soil erosion and flood, India-Bhutan Joint River Commission should be set up. But nothing has been said in this regard.

There is also no mention of a separate board which was to be set up to control flood.

The length of the area bordering Bangladesh is about 2200 kms. Wire fencing has been done here at a distance of 150 yards as a result of which 3 lakh acres of land has been encroached by Bangladesh. Therefore the farmers are

_____*Translation of the speech originally delivered in Bengali.

facing problems. The Home Ministry of Government of India has given the direction to keep the gate open for 12 hours but the BSF is opening it for not more than 3 hours. Through you Sir, I appeal to the Government that all these problems must be solved as soon as possible.

At the end, I would like to raise a very important issue. Cooch Behar is my constituency. In Shitalkuchi block of Cooch Behar, since 2 PM this afternoon, firings are taking place between BDR and BSF. People are deserting the area out of fear. This is a very serious problem. I urge upon the Government to take some steps immediately before the situation deteriorates.

I thank you for giving me the opportunity to speak.

SHRI ABDUL RASHID SHAHEEN (BARAMULLA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I have tabled many regrets which I will plead that the same be associated with the Motion of Thanks tabled by our hon. colleague, Shri Pawan Kumar Bansal. But before I talk about the regrets I have about the Address, I have some words of felicitation for the present Government for their achievement which they have made in succeeding to get through the agreement for opening the Baramullah-Rawalpindi Road, which falls in my area - as they have mentioned in the President"""""""

They are talking about ailing tourism industry of J&K. There is nothing concrete in this proposal or in this Address as to how they shall address to those problems. I have regrets that they have made no mention about opening of an IIM in Srinagar. They have made no mention about one time grant to Sher-e-Kashmir Agriculture University in Srinagar. They have made no mention about the suffering of the people who have suffered recently under 'Snownami'.

It was a disaster. Most of the areas of my constituency, like Gurez, Karnah, Karen, Muchil and other places are still cut off. I have to accept that unless we had the support of the Army there, people would have died in bigger numbers.

Our State Government is still collecting the facts as to how many people have died in the snow disaster. But still there is no comprehensive support to those people, and no mention has been made in this Address about their rehabilitation.

So, my humble request is that the first consideration should be given to the disaster hit area. It is because of the present disaster that people have suffered and they are still in problems. There is no mention about the healthcare problems the people are generally facing, and especially the areas which are militancy ridden areas, where people suffer from heart diseases, where people are with neurotic diseases and where people suffer from cancers. They are begging for support, but we do not get support from anywhere. From the Prime Minister's Office our applications are returned that 'you do not have so many formalities done.' The bureaucratisation of the Government will not help this Government to get, to achieve what they have put in their common minimum programme.

*SHRI SARBANANDA SONOWAL (DIBRUGARH): Mr Deputy Speaker Sir, I would like to say a few words on the Motion of Thanks on the President's Address. Mr Deputy Speaker Sir, India is a subcontinent. More than one hundred crores of people belonging to various communities and religions are living in the subcontinent. And the subcontinent has a glorious history. India's freedom struggle was led by the Father of the Nation Mahatma Gandhi, and in the freedom struggle people from all parts of our country took part and sacrificed their lives. Many lost their lives in this freedom movement. Gandhiji dreamt of a democratic India. He dreamt of a strong India. But we are yet to see such an India. Gandhiji's dream has not been fulfilled till now. As an example, I would like to state that although the Government of India under its Common Minimum Programme has spelt out certain welfare measures for rural development, for the development of backward communities, for the SCs and STs, for the minorities, and for women, yet these measures have not been successfully implemented till now. That is why our villages are still backward. The conditions of roads and other means of transport and communication system are in a very bad shape for which even in the 21st century villages have remained underdeveloped. As a representative of the north-east region I would like to say a few words about the region. The people of Assam also made valuable contribution in the country's freedom struggle. They joined in this freedom movement. But even after 57 years of independence the people of Assam have not enjoyed the fruit of independence the way they should have enjoyed. They have not enjoyed the fruit of freedom so far as the State's development is concerned. We have observed that the Central Government has completely betrayed Assam and the entire north-east region. The Central

*Translating of the speech originally delivered in Assamese.

Government has neglected the whole of north-east region for which we have not got good roads. The bridges and roads remain unconstructed and proper academic

and other institutions based on modern science and technology have not been set up in the State. While the Central Government has given all the modern facilities to other States, it has not given such facilities to our States for which we are still backward. Moreover, politically also we are not secured. Mr Deputy Speaker Sir, you are aware that a movement to deport the illegal migrants started in Assam in 1979. The Central Government was also aware of the fact that Assamese people felt insecure politically, culturally and economically. It was because of the influx of lakhs of foreigners, that the people of Assam felt insecure, and to deport these foreigners, they struggled for long six years. After 6 years of agitation an accord was signed in 1985. On 15th August 1985, the then Prime Minister of India, Mr Rajiv Gandhi announced that as per the provisions of Assam accord, the illegal migrants would be detected, and their names would be deleted from voters' list and they would be deported from our country so as to ensure the safety and security of Assemese people. But unfortunately that had never happened. Lakhs of foreign nationals are still residing illegally in the State. The border between the north-east region and Bangladesh is still open. The foreigners may come and occupy our land at anytime. That is why we still feel insecure. We demand security. In this connection, Mr Deputy Speaker Sir, I would like to mention that our Hon. Prime Minister Shri Manmohan Singh, during his recent visit to Assam assured the people of Assam and All Assam Students' Union that under the Chairmanship of the Prime Minister a meeting would be called to take steps to implement Assam accord. But no such steps have been taken so far. I would like to request the hon. Prime Minister that as per his assurance he had given to All Assam Students' Union, an arrangement should be made for a tripartite talks for the speedy

implementation of Assam accord. Another burning problem which Assam is facing at present is the problem of ULFA and NDFB. Since the people of Assam want a peaceful political solution to this problem, this should not be treated as a problem of mere insurgency. This problem should be solved by peaceful negotiations. Through you Sir, I would like to request the Central Government to hold talks with ULFA and NDFB so that a political and meaningful solution could be arrived at. Moreover, Mr Deputy Speaker Sir, you are aware of the tea industry in Assam. The British India and also the independent India came to the limelight of the industrial scenario through this tea industry.

MR DEPUTY SPEAKER: Thank you.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: But the conditions of the tea labourers are very very pathetic. They are yet to get proper housing facilities, they have not got pure drinking water, education, etc.

MR DEPUTY SPEAKER: Thank you. Please sit down.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: They have been deprived of bare necessities of life. The Assam Plantation Act of 1951 has not been implemented so far. The Government of India and also the State Government must ensure security to the tea labourers. I strongly demand that Central Government should incorporate these issues in its Common Minimum Programme.

MR DEPUTY SPEAKER: Thank you. Please sit down.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Mr Deputy Speaker Sir, just one more minute. Mr Deputy Speaker Sir, I would like to say that as per the assurance given in the Assam accord the Bogibeel bridge should be constructed and Assam Gas cracker project should be set up as soon as possible. Thank you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chandra Mani Tripathi, please give your suggestions only. Four hon. Members belonging to your Party are there to speak; and so, please give only the suggestions. If there are only two Members, then, we appreciate it. You may please give only the suggestions; I want to finish it soon.

Now, you may speak.

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राट्रपति जी के अभिभााण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राट्रपति जी का अभिभााण केन्द्रीय सरकार की भावी योजनाओं और कार्यक्रमों का दस्तावेज होता है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह केवल शब्द जाल का पुलिन्दा है, यह दिशाहीन अभिभााण है। इसमें कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। नाम बड़े, दर्शन छोटे, यह कहावत चरितार्थ करता है। पेज आठ में इस सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता बताते हुए कहा है कि मेरी सरकार एक समवेत समाज, हित चिन्तक राज व्यवस्था तथा साझी अर्थव्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इन्ही तीन बिन्दुओं पर केवल अपनी बात केन्द्रित करना चाहूंगा। यह सरकार समवेत समाज की बात करती है लेकिन इनका सारा ध्यान अल्पसंख्यकों की तुटिकरण की नीति पर है। पहले एक दूसरा वर्ग अल्पसंख्यकों का था। जब से श्रीमती सोनिया गांधी का प्रादुर्भाव राजनीति में हुआ है, ईसाइयत जोरों से आ गई है। आदि वासियों का व्यापक पैमाने पर धर्मान्तरण हो रहा है। यह सरकार इस बारे में खामोश है। जब तक …(व्यवधान)

SHRI BIJOY HANDIQUE : How can you connect it with Shri…

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : जब से सोनिया गांधी का प्रादुर्भाव हुआ है .....(व्यवधान) MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Tripathi, you should address to the Chair… *(Interruptions)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्षा हैं। आपको इतना बुरा क्यों लगता है? …(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, the way he is speaking is quite objectionable.… (*Interruptions*)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोनिया गांधी का अपमान नहीं कर रहा हूं। सोनिया जी यूपीए की अध्यक्षा हैं। जब से सोनिया गांधी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, आदिवासियों का व्यापक पैमाने पर धर्मान्तरण हो रहा है। …(व्यवधान)

SHRI CHANDRA MANI TRIPATHI : What is objectionable in it?… (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : What is he saying, Sir?… (*Interruptions*)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : सोनिया जी यूपीए की अध्यक्षा हैं ।…(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : What does he want to make of this country?

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : मुझे कहने का हक है। यदि इसमें कोई असंगति हो ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : आप इस देश को क्या बना देना चाहते हैं? ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : धर्मान्तरण हो रहा है। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bansal, you are a senior Member.

... (*Interruptions*)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : राट्रपति के अभिभाण में धर्मान्तरण को रोकने की कोई बात नहीं कही गई है। एक तरफ समवेत समाज की बात कही जा रही है लेकिन दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता का उल्लंघन करके कुछ खास वर्गों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। मैं इस चीज को मान सकता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए लेकिन किसी का तुटिकरण भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, यह घातक है । यह इस देश की शिक्षा को बर्बाद कर देगा । यह समवेत समाज के संबंध में यू, पी, ए, सरकार का कार्यक्रम है।

दूसरा बिंदु है हित चिंतक राज्य व्यवस्था । किसकी हित चिंतक व्यवस्था? यह देश की हित चिंतक व्यवस्था नहीं है । यह कांग्रेस पार्टी की हित चिंतक राज्य व्य वस्था है । प्रधानमंत्री की गरिमा को अवमूल्यित कर दिया गया है । प्रधानमंत्री के पद का अवमूल्यन कर दिया गया है । ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded.

*(Interruptions)**

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : गैर-कांग्रेसी सरकारों को बेहूदे ढंग से, बहुमत के बावजूद उलट पुलट करके बर्खास्त किया जा रहा है, क्या यह राजनीतिक हित चिंतक है? तीसरा बिंदु साझी अर्थव्यवस्था का है । कांग्रेस पार्टी कांग्रेस मिश्रित अर्थव्यवस्था से चली थी, फिर आवड़ी कांग्रेस में कांग्रेस ने ससोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसायटी, का नारा दिया। फिर सोशलिस्टिक समाज हो गया । आज यह साझी अर्थव्यवस्था क्या है? राट्रपति जी के अभिभाण में कीमतों को स्थिर किए जाने की बात की गई है । जिस दिन मान्यवर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता थी, उस दिन 12 रुपए किलो चीनी बिकती थी ।

21.00 hrs.

लेकिन आज वही चीनी 22 रुपये किलो के भाव बिक रही है। हर जिन्स के दाम बढ़े हैं। लोहा महंगा हो गया है, सीमेंट महंगा हो गया है और महामहिम राट्रपति जी के अभिभाण में लिखा है...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why are you giving a running commentary? You are the most responsible person and most hon. Member of this House.

* Not Recorded

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि महामहिम के अभिभाण में लिखा है कि

2004 में मुद्रास्फीति की दर 8 प्रतिशत थी जो अब 7.5 प्रतिशत हो गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि महंगाई का स्तर बढ़ा है। देश अस्थिरता के कगार पर खड़ा है और अराजकता की स्थिति में चला गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश में यू, पी, ए, सरकार सभी लोकतांत्रिक को नट करने पर अमादा हैं और सभी योजनाओं में समयबद्व कार्यक्रम नहीं है। मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं राट्रपति जी के अभिभाण में धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऑनरेबल मैम्बर्स से रिक्वैस्ट है कि श्री जे.एम. आरुन रशीद जी की तबीयत खराब है, वे पहले बोलना चाहेंगें। इसलिये उनका भाण पहले करने के लिये कह रहा हूं।

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Respected Deputy-Speaker, Sir, our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh has protected India's pride by not taking the foreign contributions at the time of Tsunami disaster. He has said that we do not want foreign contribution. He has told America that we do not want your help as we are self-sufficient. So, India's pride has been kept by our hon. Prime Minister under the able guidance of our leader, Madam Sonia Gandhi.

The UPA Government has given thousands of crores of rupees for the Tsunami victims. More than Rs.1400 crore has been given to Tamil Nadu alone. I would only request that the help should go directly to the needy people. If a person is missing, he should be declared as dead. If the head of the family is missing for 60 days, the family is under starvation. So, I would

request that the persons who are missing should be declared as dead and compensation should be given to them. According to the law, if they want to take compensation, it will take 5 to 7 years' time. Why should they have to wait 5 to 7 years for getting compensation? They should get the due compensation. Therefore, I would request the Government to see that compensation is given to the Tsunami victims.

I welcome the concern shown by the UPA Government for the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minorities.

21.03 hours (Shri Pawan Kumar Bansal *in the Chair*)

The NDA Government did not care the minorities. During its regime, the Scheduled Castes were deprived of their dues. But the UPA Government under the guidance of our CPP Leader, Shrimati Sonia Gandhi has given very good schemes to the nation. During UPA Government's regime, the inflation rate has come down from 8 per cent to 4 per cent. The NDA had forgotten the grievances of the minorities… (*Interruptions*). When I speak in Tamil, I can reply to you but when I speak in English, I cannot reply to you… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please carry on. Please do not be distracted by him. Otherwise, you will lose your own time.

Sir, this Government has allocated rupees one lakh crore to the agriculture sector. We have spent around Rs. 93,000 crore for the welfare of the agriculturists. The people associated with farming and other related aspects in the rural areas and in the far-flung tribal areas have been protected by the new Act. They have been given importance… (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: Sir, there is no translation.

MR. CHAIRMAN : You have to give notice if you have to speak in any language other than Hindi and English.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please continue your speech. We have to conclude the debate today itself.

SHRI J.M. AARON RASHID : Their rights have been guaranteed by this. For years together these people have been engaged in agriculture. Some forest officials are denying their rights. Now, the UPA Government have assured the tribal people, the villagers their rights. They are actually the poor people of this country. They have been given full support by this Government. I welcome it.

This Government has taken initiative to help the rural poor by launching schemes like the *Sarvasiksha Abhiyan* scheme, the Mid-day meal scheme, the Kasturba Gandhi *Balika* Nutrition scheme and the Direct to Home television educational satellite. This launching of the educational satellite will enlighten the rural poor and help in their education. The rural youth, women and people belonging to the backward classes will come under this hi-tech educational policy of the Government. This UPA Government is doing whatever they can for the poor people of this country. I welcome the decision of the Government for constituting the Minority Commission in matters of education to safeguard the interests of the minority institutions. In the name of minority, the linguistic minorities are taking advantage of these institutions with the help of those people who are representing the NDA. When NDA was in power, they included linguistic minority as well. For instance, if any Tamil speaking person goes to Karnataka, then they become a linguistic minority and the same old persons continue to enjoy the status of being a minority. In the institutions meant for minorities, the Christians, the Muslims, the *dalits* should be given 50 per cent reservation for admission in the minority institutions. Now, in the name of being a linguistic minority, the people who are having more money are enjoying the benefits of this reservation. So, the Government should bring in a strict legislation to curb this practice.

Sir, Congress Party has brought freedom to this country. Now, under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi the party is planning a *Dandi Yatra* to remember our Father of the Nation who led our struggle for Independence. By this *Yatra* the Party also wishes to remember those people who participated in the famous Salt *Satyagraha.* The people who represent the NDA never did any such thing. They only speak against the Congress but they did not do any good.

Sir, in my constituency the weavers are suffering. This Government has come up with a plan to encourage and modernise the handloom sector.

According to the UPA Government's time-bound programme, it is two years in respect of weavers. Under this programme, all the old handlooms will be replaced. It is really a good programme as it will boost up the economy of the poor weavers.

With these words, I thank the President for his Address to Parliament.

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया सदरे जम्हूरिया के खुदबे पर इज़हारे-खयाल करने के लिए।

मैं सबसे पहले अपने मौअकिफ़ का इजहार करना चाहूँगा कि हम सदर जम्हूरिया के खुदबे के मोशन की ताईद करते हैं। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि सदर जम्हूरिया के खुदबे में बहुत सी अच्छी बातें कही गईं। मिसाल के तौर पर हिन्दुस्तान की अकलियतों के लिए जिनकी आबादी 19 फीसदी है, उनके सिलसिले में लिंग्विस्टिक यानी लिसानी और मज़हबी अकलियतों के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। मैं हुकूमत से चाहूंगा कि इसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाए। क्योंकि इस कमीशन को कायम हुए दो-ढाई महीने हो चुके हैं और इस कमीशन की मियाद 31 मार्च को खत्म होने वाली है। अभी-अभी इनको ऑफिस मिला है। मैं चाहूंगा कि हुकूमत इस कमीशन को एक्सटैन्ड करे, इसकी मियाद में इजाफा करे और एक वक्त मुकर्रर करे कि इस वक्त के खत्म होने तक यह कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अकलियतों के सिलसिले में हुकूमत ने वायदा किया कि एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत का अहम फरीज़ा यह होना चाहिए कि इस व्हाइट पेपर के लिए वक्त का तखर्युर किया जाए और इस वक्त के तखर्युर करने के बाद इस व्हाइट पेपर को फौरन जारी कर दिया जाए।

तीसरी बात जो सदर जम्हूरिया के खुदबे में कही गई, 15 निकाती प्रोग्राम पर नये अंदाज़ से दोबारा अमलाआवरी की जाएगी। मैं समझता हूँ कि 16 साल के लंबे अर्से के बाद आज मरकज़ी हुकूमत 15 निकाती प्रोग्राम की बात कर रही है। अगर वाकयी में कांग्रेस पार्टी मरहूम वज़ीरे-आज़म राजीव गांधी को इज़हारे अकीदत पेश करना चाहती है तो उसको सख्ती से 15 निकाती प्रोग्राम पर अमल करना चाहिए। अब वक्त आ गया है इस अलायंस के लिए कि वह अपने वादों को अमली जामा पहनाए। सिर्फ यह नहीं कि मीठी-मीठी बातें करके अकलियतों को, खासकर मुसलमानों को खुश कर दिया जाएगा। एक बात इनको ज़हननशीन कर लेनी चाहिए कि मुसलमानों ने कई फसादात देखे, कई ज़ुल्मो-ज़्यादती देखे, अपने घरों को लुटता हुआ देखा, अपने आपको खत्म होते हुए देखा, मगर कोई भी रियासत या हुकूमत मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकी। हम तूफानों में रहकर अपनी कश्ती को चलाना सीख चुके हैं। अब आप बार-बार हमें यह नहीं कह सकते कि कोई शेर आ रहा है, बल्कि यह कौम खुद एक शेर बन चुकी है। इसीलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने वादों को अमली जामा पहनाएं। मुसलमानों के लिए जो मुसरते अकलियत है, खास तौर से आप मुसलमानों को देखें हिन्दुस्तान में तो सबसे ज्यादा बंडियों पर काम करने वाले मुसलमान हैं, रोडों पर सफाई का इंतज़ाम करने वाले मुसलमान हैं। इनके लिए ठोस इक़दामात कीजिए।

हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने पोटा को खत्म किया। आपने अकलियती तालीमी इदारों के लिए कमीशन कायम किया, मगर जहां तालीम की बात आती है, मैं बतलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने दस्तूर की दफा 30, जो हमारे हिन्दुस्तान के दस्तूर की आईन की अहम चीज़ है, फंडामैंटल राइट है, उसको भुलाकर रख दिया। आज अकलियती तालीमी इदारों में 50 फीसद सीटें गैर अकलियती उम्मीदवारों को दी जाती हैं। जब दस्तूर बनाया गया और उसमें दफा 30 को शामिल किया गया तो उसका मकसद यह था कि इस मुल्क की अकलियतें अपनी पसंद के तालीमी इदारे कायम करें और उनको चलाएं। अगर यही फैसला हक और सच्चाइयत पर मुबन्नी है तो मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहूंगा कि गवर्नमैंट के प्रोफैशनल कालेजों में भी आप अकलियतों के लिए 50 फीसद रिजर्वेशन कीजिए, वरना आप इस ऐवान में एक बिल लेकर आइए, ताकि अकलियतें जो अपनी मेहनत से, अपने पैसों के बल बूते पर तालीमी इदारें कायम कर रही हैं, वह इन तालीमी इदारों में अकलियतों को एडमिशन दे सकें। हम जानते हैं कि तालीमी खवानगी का क्या फीसद है अकलियतों में। खासकर मुस्लिम अकलियत का तालीम लिट्रेसी रेट काफी नीचे आ चुका है। मैं जानना चाहूंगा कि सदर जम्हूरिया के खुदबे में तेलंगाना के ताल्लुक से क्या पालिसी है? मैं हैदराबाद शहर की नुमाइंदगी करता हूँ। आज हम करोड़ों रुपये का इनवैस्टमैंट खो रहे हैं सिर्फ इस बात से कि मरकज़ी हुकूमत की एक वाजे पालिसी अवाम के सामने नहीं आ रही है। मैं हुकूमत को इंतबाह करना चाहता हूं, मुतनब्बा करना चाहता हूं कि तेलंगाना के ताल्लुक से आप इकवाजे पालिसी को बयान कीजिए। हैदराबाद और तेलंगाना में मुस्लिम अकलियत 45 फीसदी बसती है।

आपको हमसे मशविरा करना चाहिए । यह नहीं हो सकता है कि सात अराकीन-ए-पार्लियामेंट को ले कर उनकी राय को ले कर आप फैसला कर लें । इसको हम मंजूर करेंगे । इसे तेलंगाना में बसने वाले लोग नहीं मानेंगे । आपको अपनी पालिसी को वाजे करना पड़ेगा । खास तौर से मुसलमानों को विश्वास में लेना पड़ेगा । इहतिमाद में ले कर आप हमको बुलाइए । हम से बात करिए । यहां एक तरफा बात हो रही है । हम जो असल में राज्य होल्डर हैं, इस ताल्लुक से अपनी पालिसी वाजे करनी चाहिए ।

छठी बात नकस्लाइट के ताल्लुक से है । सदर जमुरिया के खुतबे में कभी यह भी कहा गया कि रियासतें हुकूमतों को इस बात की इजाजत दी गई है कि वह जिस तरीके से चाहे बात करें । मैं मरकजी हकूमत से मुतालबा करता हूं कि आप अपनी पालिसी बनाइए ताकि वाजे सतह के ऊपर नकस्लाइट के मसले को सही तौर से निपटाया जा सके । आप जम्मू-कश्मीर में हुरियत से बात कर सकते हैं, मार्कसिस्ट में दिगर तंजीमों से बात कर सकते हैं, इसलिए नकस्लाइट्स से बात कीजिए । हमारी रियासत में आज से दो दिन पहले दस नकस्लाइट्स का इंकाउंटर हुआ । अखबारी इत्तालात बताते हैं कि इन दस नकस्लाइट्स को किसी एक जगह पर गिरफ्तार किया गया । उनके खाने में नशीली दवाओं को मिलाया गया और जंगल में किसी मुकाम पर ले जा कर उनके सिर के ऊपर और औरतों की छाती के ऊपर गोलियां मार दी गईं । बतलाइए कि क्या यह मसले का हल है? इससे तशदुद्द में और इजाफा होगा और जितना गलत तरीके से होगा, मसला और बढ़ता जाएगा । मेरा हुकूमत से यह मुतालबा है कि आपके जरिए से इस मसले पर एक वाजे पालिसी का एलान हो । बेशक यह सही है कि जब से यह सरकार बनी है उस वक्त से हिंदुस्तान के सेक्युलर जहन रखने वाले लोगों में खास तौर से मुस्लिम अकलियत में राहत की सांस ली है लेकिन हम जानते हैं कि छह साल में क्या-क्या हुआ और क्या-क्या नहीं हुआ? किस तरह से नित नए तरीकों से मामले को दबाने की कोशिश की गई । तबाह और बरबाद करने की कोशिश की गई । लोग सिर्फ गुजरात की मिसाल देते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि हमारे हर सूबे जात में ऐसे लोगों को ला कर बिठाया गया है जिनकी मंशा और मकसद हिंदुस्तान के सेक्यूलरिज्म को तबाह करके और गारत करना है । आज यह हुकूमत आई है । इसका काम सिर्फ हुक्मरानी करना है । हुक्मरानी इंसाफ से करिए । मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का जो फंड है उसमें आपने कितना दिया है? एक साल में कितना फंड दिया है? यह मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन आपकी कांग्रेस हुकूमत ने बनाई है । कौमी अकलियती फाइनेंस कारपोरेशन को आपकी हुकूमत ने बनाया है । आपने क्या किया है? मैं जानना चाहूंगा कि हुकूमत क्या करेगी?

एक सीडी बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से निकली है । बाबरी मस्जिद की शहादत से दो दिन पहले साबका वजीरे आजम अपनी तकरीर में लोगों को उकसा रहे हैं कि मैं नहीं जानता की बाबरी मस्जिद का क्या हाल होगा? मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि सीडी को बुनियाद बनाते हुए इसको आप खुद रूबरू होइए । लिब्राहन कमीशन आपके पास है, सीबीआई आपके पास है । सीबीआई को कहकर साबका वजीरे आजम के खिलाफ मुकदमा आईद कीजिए कि इन लोगों की साजिश की वजह से ही बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया । यह तमाम चीजें आपके सामने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कल जब वजीरे आजम हिंद खड़े हो कर सदरे जमुरिया के खुतबे के ऊपर या इन अमुर पर वाजे तरीके से ब्यान करेंगे तब हिंदुस्तान की मुस्लिम अखलियत को भी न सिर्फ इहतिमाद में लिया जाएगा बल्कि वजीरे आजम अपनी जबान से कहेंगे, हाँ हम इन चीजों पर अमल करेंगे ।

जो वक्त आपने मुझको दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

SHRI W. WANGYUH KONYAK (NAGALAND): Mr. Chairman, thank you very much. I got the opportunity to speak after waiting for many hours. I want to make a remark before I start my speech. We have 33 political parties and leaders in the present House. We are not getting opportunity to speak. Only when some problems arise, you call us. Otherwise, it is from BJP to Congress and from Congress to BJP. You please give us time to speak. I am the lone Member from Nagaland.

MR. CHAIRMAN : Please start your speech now.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : If you cannot give me time even to speak, can I get money for development of Nagaland?

MR. CHAIRMAN: My request would be, please do not take your time on preliminaries. Please get down to your speech. You have got time now. Please start.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : Now, I rise to participate on the Motion of Thanks on the President"""""""

India.

The decision to accept the invitation of the Prime Minister to visit India has benefited the peace in many ways. Here are two such noteworthy points, which I want to point out: The Prime Minister of India is easily available for talks; the NSCN leadership had easy access to cross-section of Indian political leaders and parliamentarians, including the Leader of the House, who is sitting here tonight.

Therefore, it is the Nagas who are the masters; we have started many things. We do not want development, we do not want anything. We said, 'Nagas of Manipur, Nagas of Assam, Nagas of Arunachal Pradesh'. We are not talking about that. We do not want even an inch of land from any State but Naga's birth right.

As here, in the President's Address, on page 16 it is clearly mentioned, 'legitimate aspirations'. Mr. Chairman, please see this House. Out of 543 Members, how many Members are present here this evening. Is that the way to function?

MR. CHAIRMAN : Please carry on and try to conclude.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : Therefore, my point is that the slogans of the Nagas in 1950s and 1960s were: "Nothing short of absolute sovereignty, nothing short of complete independence, and nothing to do with the Indians." But today the Nagas are talking of closeness with India because of the importance of interdependence everywhere in the world and pragmatic basis of coming closer to the point that would be acceptable to both the parties. When the Nagas are prepared to come as close as possible with Delhi, is Delhi prepared to reciprocate?

It is high time for the Indian leadership to give the much needed, much awaited healing touch to the bitter wounds inflicted on every heart of the Nagas by keeping them arbitrarily divided and sub-divided. The Nagas feel there is nothing wrong with their aspirations to live together because brothers and sisters on earth naturally have every right to desire to live together and they know that they have every right to live together whether for the better or for the worse; for the richer or for the poorer.

It may be a great mistake on the part of the Central Government to send back the NSCN leadership without any sight of resolution of the conflict.

Sir, I repeat that kindly give time to the 9 (nine) single MPs belong to the smaller parties to speak first before giving chance to Congress-BJP. When you are in trouble, you invite us and when you are not in trouble you do not give us time. This is wrong. You call us back-benchers. We are not back-benchers. This needs to be rectified. I am sorry to say this. The Leader of the House is here. So, this needs to be rectified immediately.

MR. CHAIRMAN: I have given you more time than was allotted to you. Please conclude now.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : There are 80 Members from Uttar Pradesh and about 40 to 50 Members can speak from that State.

I am the lone MP from Nagaland. I do not get the time to speak. What does it mean? I think it is bitter enough to say it in this House. This is wrong. This needs to be rectified immediately.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to put in a few words at the near end of the discussion.

I have had the opportunity to give certain amendments to the President's Address to Members of both the Houses of Parliament assembled together. Though a few in numbers, I think they hold very special relevance since I have been listening to all the speeches today. Somehow, unfortunately most of the very revered and hon. Members of Parliament have not bothered to mention certain vital and important matters which should concern all of us who claim ourselves to be the law makers of this nation.

Sir, the UPA Government, whose mouthpiece the President, has given in his Address, has kept before it certain priority areas such as agriculture, education, employment, health care, infrastructure, urban renewal and water. But unfortunately, two very important facts of life, which have been completely ignored throughout this Address, sadden me. The first is preservation of forest wealth which somehow nobody in India seems to bother about. There is complete ignorance. I would not say that there is complete antipathy. Or, there is complete 'I do not care' attitude of the Government towards preservation of our forest wealth.

Sir, I would like to know how much time I have got.

MR. CHAIRMAN : You have actually five minutes' time.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I will try to complete within that time. Today, if you see the map of India, all along the East Coast, whether it is the land of the bandit Veerappan or in the Nepal border and beyond that where the MCC is operating, there used to be a rich forest belt. But today that belt is depleted. Economically it is one of the worst and the most backward stretches of this country. If you see that belt, if you see the map of India, in about 150 to 160 districts which lie all along that belt, and that is where the naxalites are active today. Naxalites are not anti-social. Naxalism is a political movement. It is a movement born where the poor man is living. This is where the *aam admi* is living. The Government is always beating the drums of the *aam admi.* Yet that is the most neglected area of this country.

I come from the land of Lord Jagannath and from the land of Kalinga of Ashoka's transformation, Orissa. A major patch of that belt is within our State. What we see in our State is unfortunate. If you come to realise or even if you would have seen that area just 15 or 20 years ago, it is amazing. I am not talking about half a century. I was not born during Independence. But we, are the generation of post-Independence. If you see the depletion in the forest wealth, the kind of damage that has occurred there, it is amazing.

The President's Address mentions about 'forest villages', where it is said that people have been practising agriculture on these lands for several generations but have not been given due recognition of their rights. It says that their problems are engaging the attention of the Government and that the Government would try to settle the issue of land rights of tribals. As I had mentioned, this is where the Naxalites have been active. This is a major concern for the Supreme Court. This is where all our forest wealth is but we have not tried to preserve our forests and nor are we trying for the economic uplift of people living in those areas. In the very basic sense of land ownership, we have not bothered to have the land given to the tiller. Landlords and moneylenders still rule the roost in these areas. There is no Government whether it is of NDA or of UPA that has done it. It is still the landlords and moneylenders who are active but this Address does not mention that in any way. So, it is a pity.

The extinction of wildlife is something that should concern all of us, human beings. As we all know, we have the blessings of the Lord. We have had the fruits of education. We all know and the whole world today is aware about the wildlife, how to preserve wildlife and also how by preserving wildlife we could help ourselves to be preserved but India is one country where we are completely callous towards wildlife that exists in this country. We have been merciless in the extinction of wildlife.

Having talked about forest wealth and wildlife extinction, before I conclude I would like to just mention two points. In this Address, there is no mention about last year's Budget under which special huge amounts of money were to be spent for creating water bodies. In the seven points of priority of the UPA, water comes at the very last. Unfortunately, the President did not think it necessary to mention what happened to that huge sum of money which was to be spent for creating water bodies in the rural belt of India. As far as I know, in my constituency and in a few other areas I have seen in the neighbouring States, nothing has actually trickled down. Forget preservation of water, no money is trickling down. Out of the money that has been spent by the Union Government, nothing has actually reached the people.

We have a very honest State Government in Orissa but unfortunately it has been constantly neglected by the Central Government. The Congress, which has ruled this country for several years after Independence, has made it a point that although Orissa had always been supporting the Congress the Congress has always purposefully and very consciously tried to keep Orissa behind every other State in the country. We have the largest amount of mineral wealth in this country. We have the capacity to hold on to industry. But unfortunately we do not get the benefits of any of these minerals. So, eventually, you would see, a time would come when our money, our wealth, and our minerals would enrich other States and other parts of this country but we would go the way that many South American and Central American countries have gone, into depravity and abject poverty, and we would be destroyed while this country would sit and laugh at Orissa. Fortunately, we have the blessings of Lord Jagannatha. We have an able and honest leader in Mr. Naveen Patnaik. In the case of the UPA Government, they have several leaders whose names have to be taken. For instance, the Prime Minister's name and the UPA Chairperson's name have to be taken. In our case, we have only one name to take. I would like to conclude by saying that like Orissa, India should also be protected from all the vagaries of opportunism and politics of convenience.

Lastly, it is of interest to know that when the Pope came to India a few years ago, he said that proselytisation of India is high on the list of papal activities. I am not a communal person but I would like to state here very categorically that India is a tolerant country. Today, if you sit on a high chair and if you look around you will find that all the high posts in this

country are occupied by people who are from the Minority Community or who are from the Backward Class. They get the respect that they deserve from the rest of the country.

I am sure that in spite of all the failures of this Government, in spite of a very lackadaisical, uninterested and haphazard Address by the hon. President, this country will shine, India will shine and nobody can stop India from shining.

MR. CHAIRMAN : Shri Haribhau Rathod. I will give the bell after four minutes and you have to complete your speech within five minutes.

… (*Interruptions*)

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति महोदय, मैं राट्रपति के अभिभाण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं। अभिभाण के पृठ नम्बर 8 और कालम नम्बर 8 में यह दिया गया है कि यह धर्मनिर्पेक्ष, पंथनिर्पेक्ष है। यह बात सदन में भी बार-बार आती है। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार धर्मनिर्पेक्ष ही होनी चाहिए। अगर वह धर्मनिर्पेक्ष नहीं है तो आप कौन्सटीट्यूशनली उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। हमारी सरकार धर्मनिर्पेक्षता पर विश्वास करती है, बार-बार यह बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां यही होता है। मैंने देखा है कि पांच साल में आदरणीय अटल जी की सरकार ने जो काम किए, उतने काम 50 साल में कांग्रेस ने नहीं किए। जब इलैक्शन में हमने लोगों के सामने यह बात रखी, विकास के नाम पर वोट मांगे तो कांग्रेस ने गोधरा के नाम पर वोट मांगे। उन्होंने गोधरा की बात लोगों में जाकर की। लोगों को बहकाया, फुसलाया और ये बार-बार अल्पसंख्यकों की बात करके और दरारें बढ़ाना चाहते हैं। मैंने पूर्व राट्रपति * का वक्तव्य पढ़ा। जब वे राट्रपति थे, उनको यह लगा कि कुछ गलत हो रहा है। …(व्यवधान) **सभापति महोदय** : यहां की परम्परा है कि जो हाउस के सदस्य नहीं होते, हम उनके नाम का जिक्र नहीं करते। आप नाम के बिना जो बात कहना चाहते हैं, वह बेशक कहें लेकिन इस तरह से किसी का नामा लें।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : मैं पूर्व राट्रपति जी का वक्तव्य पढ़ रहा था, जिसमें यह बात उठाई गई कि भारतीय जनता पार्टी और अटल जी जिम्मेदार थे। अगर उनको मालूम था तो उन्हें उस समय एक्शन लेना चाहिए था। इससे ऐसा लगता है कि वक्त पर उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास 17 शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, 17 शैडयूल्ड ट्राईब्स के लोग हैं और 62 ओबीसीज़ के लोग हैं। कुल मिलाकर 92 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के एम.पीज. देहात से आये हैं। पिछली सरकार में हमने देखा था, जब हम लोगों को बताते थे कि पिछले पांच साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इतना काम किया, हम विकास का नारा देते थे। हमारे महाराट्र में इलैक्शन हुआ, उस समय ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया था, वहां कपास की प्रौब्लम था, बिजली की प्रौब्लम थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि वहां शिवसेना और भारतीयानता पार्टी की सरकार आयेगी लेकिन कांग्रेस लोगों को गुमराह करने में बहुत मजबूत है। उन्होंने 50 साल तक यही किया है। धर्म के नाम पर यह अपना वोट बटोरते रहे हैं।

* Not Recorded

जब शैड्यूल कास्टस, शैड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन की बात आती है तो श्री अटल बिहारी की सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने का काम किया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमैंट आये जिससे रिजर्वेशन रुक गया था। मिसाल के तौर पर मैं साबरवाल प्रकरण का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कांस्टीट्यूशनल अमेंडमैंट किया और एस.सी. और एस.टी. को आरक्षण दिया। 100 करोड में से 15 करोड विजे एंटी यानी विमुक्त जाति, भकटिया जमात हैं। श्री गुलाम नबी साहब को मालूम है कि बंजारा समाज के छः करोड़ वासी पूरे देश में हैं। आठ करोड़ भकटिया जमात के हैं । इन 15 करोड़ समाज को न्याय देने का काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। एक राट्रीय आयोग जिसका नाम राट्रीय पिछड़ती बंजारा विजे एटी कमीशन, डीनोटीफाइड एंड सेमीनोमेडिक कमीशन उन्होंने बनाया था। ऐसा क्या हुआ कि जो छः महीने पहले कमीशन था, उसे कांग्रेस ने क्यों हटा दिया ? सरकार बदलने से क्या ऐसा होता है ? जिन 15 करोड़ लोगों को न्याय देने का काम अटल जी ने किया था, आज वह नहीं हो रहा है। घरघर समाज के लिए बकरियां, भेड़ पालने के लिए एक डेवलपमैंट कारपोरेशन बनाया गया था जिसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था लेकिन उसका भी नाम कांग्रेस वाले नहीं लेते। हम गरीबों की बात करते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : अब आप समाप्त करिये। आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये हैं।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बहुत दिन से महिला आरक्षण की बात चल रही है। मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के बारे में 50 परसेंट के लिए अपना लाइन ऑफ कंट्रोल दे दिया है कि 50 परसेंट के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। यदि महिला 50 परसेंट है तो आप 25 परसेंट महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। आम आदमी को जो न्याय मिलता है, वह महिला को भी मिलना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि महिलाओं के लिए 25 परसेंट आरक्षण का बिल आप लेकर आयेंगे तो मैं समझता हूं कि वह जरूर पास हो जायेगा और उसको कोई रोकेगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अटल जी के राज में और उसके बाद भी देश में एक बहुत बड़ा सपना देखा था कि हर हाथ को काम और हर जमीन को पानी मिलना चाहिए। इसीलिए सारी नदियों को

जोड़ने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन इस बात को कांग्रेस सरकार और वामपंथी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन हर हाथ को काम और जमीन को पानी मिल जायेगा, उस दिन इस देश में हरित क्रान्ति आ सकती है। यह मेरा सुझाव है।

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Bikram Keshari Deo will speak. He is the last speaker.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): After a long wait, I got my turn; I thank you very much, Mr. Chairman. I would like to quote Article 74(1) of the Constitution. It reads :

> "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice:
>
> Provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration."

Sir, I am sure the President must have applied himself when the speech was being prepared for addressing Members of both the Houses assembled together. I respect his intelligence because he is basically a thinker, and one of the leading scientists of our country. Our country was not even capable to launch its own satellite, and had to take it on hire from different countries to launch our satellites. I give credit to this great man, who is our President today for breaking the ice in launching the first Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) in the country. Today, we have been able to save thousands of crores by doing this.

I was going through the hon. President's address. It is nothing, but a reflection of the rural revolution development work, which the NDA Government started under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee. It is just a reflection of it. Therefore, through you, I would request the UPA Government to implement the path of progress with utter sincerity like in the case of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).

There was a Rajiv Gandhi Foundation for drinking water, and they were doing a very good job. There is no doubt about it, but I am very sorry to say that you named the entire 'Swajal Dhara' Yojana under his name. 'Swajal Dhara' means potable drinking water, and you should not have done this.

The personality cult persists so much in the Congress, and the UPA. It becomes, virtually, an autocratic type of system, and it is the NDA where the actual democratic system persisted. In the last six years, under the able leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee, we could take the country forward in foreign policy, in defence policy, in rural development policy, etc. In all the policies we were ahead of the Congress Government, which it could not do in the last 50 years. If you want to show the country something new, then get agriculture into the Concurrent List, create the disaster management institute, etc.

Sir, it is an irony of fate. When the NDA Government took power, the super cyclone hit Orissa, and today, when the UPA Government is in power Tsunami hit us, and thousands of lives were lost. So, it goes to show -- for both these sides -- that we can be taken unaware by any disaster. The creation of a disaster management institute has become highly essential with the present climatic changes, with the present ecological imbalance, etc. The things have to be thought anew.

Today, the relief codes of the States with the help of which the disaster mitigation takes place are outdated British law. It was formulated during the British time. It was meant for flood, drought, and famine. There have been modifications done in them, but there must be a central comprehensive law for relief to the drought-affected people. They must create a security shield for those affected by disasters. Today, who knew beforehand that Tsunami would hit us. It hit us and it hit us badly, and you were not prepared for it. The same thing happened during the super cyclone days, when Orissa coast was hit by the super cyclone. The Government in Orissa, at that time, was also the Congress. They were completely lost. They could not manage the super cyclone. The blankets and relief materials, which were coming from abroad, were being sold in the market. The hero of the 1998 Parliament or the 12th Lok Sabha -- I should not name him -- was the former Chief Minister of Orissa. He masterminded the toppling of the 13-month old Government of Shri Atal Bihari Vajpayee, and the NDA.

That was the kind of Government which was there in Orissa then. We have to come out with a concrete policy on disaster management. The programme regarding National Horticulture Mission was announced long time back, and you have reviewed it, which is a welcome step. However, do you have food preservation facilities for this purpose? Today, 80 per cent of the horticulture produce, like vegetables and other crops, are being destroyed because of lack of proper storage facilities resulting in shortages everywhere.

Before I conclude my speech, I would like to refer to WTO because the hon. Leader of the House, Shri Pranab Mukherjee, is sitting in front of me. He was the Commerce Minister in 1993, when he signed the WTO Agreement in the Uruguay Round of talks. I am a Member of Parliament for the third time and, during this tenure, I have been going through various reports on WTO. I am sorry to say that the developing countries are not being looked after at all, and the developed countries are not reducing subsidies on agriculture. When Shri Mukherjee, who was the Commerce Minister in 1993, signed the Agreement in the Uruguay Round of talks, the Agreement on Agriculture was left blank. Today, the agriculturists of this country are suffering because there is nothing on record relating to agriculture.

I have given a lot of amendments from serial numbers 623 to 648. If I start speaking on all those points, I will not be able to complete my speech in time. However, I want the same to be recorded because they are valid points. They are not there to score political points, they are all points for the development and for the betterment of this country, this great democracy of ours, which is the biggest democracy in the world today.

I am sorry to say that the democratic set up in Jharkhand has been destroyed. I would not like to repeat it because other hon. Members have already mentioned it. What has happened in Goa is a rape of democracy because horse-trading was going on. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him. Let him continue.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : In Jharkhand, as per the Constitution and as per the election laws, the largest party should have been invited to form the Government and asked to prove its majority. However, I am sorry to say that a party with the least number of MLAs had been invited to form the Government in Jharkhand. What a sorry state of affairs it is!

Sir, I have got another minute to speak. You said that you would give me four minutes.

MR. CHAIRMAN: You have already taken nine minutes.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, you have said that after the bell is rung, I would get another minute. Please give me one more minute.

Now, I come to anti-dumping measures because of which this country has been losing a lot.

MR. CHAIRMAN: Please just state your point. You have taken nine minutes. Within one minute, you will have to conclude. Please just state your point. I will let you do that. Please just state your point and do not take more time on this.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : The Crop Insurance Scheme was initiated by the NDA for the first time, but it was not a very comprehensive scheme. To make it more comprehensive and more effective, village as a unit should be taken for insurance purposes. Besides, paddy, wheat, and cereals, other horticulture crops like vegetables should also be covered under this Scheme.

Sir, as you know, the credit given by the banks to agriculturists has been increased by about 50 per cent. I will speak on these things in the Budget discussion, if I get a chance.

Lastly, I would like to say that electricity is a very vital thing for any country. I am sorry to say that there is no mention of producing more electricity, especial nuclear energy, which is the order of the day. To make us self-sufficient, we have to produce more nuclear energy. Today, of the total capacity of the electricity generated, we are generating only 2.4 per cent from nuclear energy sources.

With these words, I thank you and conclude my speech. I do not feel like opposing the Address of the hon. President of India because he not only belongs to a minority community, but is also a great Scientist, who had been installed in his seat of power, the Rashtrapathi Bhawan, by the NDA Government.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the list of speakers is exhausted. The Prime Minister would reply to the debate tomorrow.

22.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, March 10, 2005/Phalguna 19, 1926 (Saka).